राष्ट्रीय संस्करण

आइपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रिंस को मिली वन-डे टीम में जगह

>> 12

वर्ष 9 अंक 341

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, बुधवार, 20 मई, 2026

www.jagran.com

पृष्ठ 14

बांदा देश का सबसे गर्म शहर, 48.2 डिग्री पहुंचा पारा

जागरण टीम, नई दिल्ली

- 2019 में 48.1 और 2022 में 49 डिग्री सेल्सियस किया गया था रिकार्ड
- देश में दूसरे नंबर पर मप्र का नौगांव और तीसरे नंबर पर हरियाणा का रोहतक
- उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी, अगले पांच-छह दिन नहीं मिलेगी राहत

उत्तर भारत में भीषण गर्मी और हीटवेव (लू) का प्रकोप जारी है, जिसमें उत्तर प्रदेश का बांदा जिला सबसे अधिक प्रभावित है। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बांदा देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री दर्ज किया गया है। यह इतिहास में तीसरी बार है, जब बांदा में पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। इसके पूर्व वर्ष 2019 के मई माह में 48.1 डिग्री, 2022 में 49 डिग्री रिकार्ड किया गया था। देश में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का नौगांव व तीसरे नंबर पर हरियाणा का रोहतक रहा है।

मौसम विभाग के मुताबिक, पूरब से पश्चिम तक अगले पांच-छह दिनों तक तपिश से राहत के आसार नहीं हैं। इस बीच उप्र के 60 से अधिक जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल, पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से उत्तर भारत में शुष्क और गर्म हवा का प्रभाव काफी बढ़ गया है। इसके चलते देश के ज्यादातर राज्यों में लू की स्थिति लगातार गंभीर हो रही है।

सर्वाधिक गर्म अन्य चार शहर

नौगांव (मप्र)	47.00
रोहतक (हरियाणा)	46.90
अमरावती (महाराष्ट्र)	46.80
दिल्ली रिज	46.50

भीषण गर्मी के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में अपनी चुन्नी से बच्चे को ढककर तपिश से बचाने का प्रयास करती एक महिला। प्रेट्र >>

दावा- दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत के

एक्यूआइ.इन की लाइव ग्लोबल टेंपरेचर रैंकिंग के मुताबिक, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत के हैं। यह पहली बार है, जब इस सूची में सभी शहर भारत के हैं। एक्यूआइ.इन के मुताबिक, सबसे गर्म शहरों में बांदा, नौगांव, रोहतक, आगरा, झांसी, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और वाराणसी शामिल हैं।

नार्डिक देशों के साथ संबंधों को ग्रीन टेक्नोलाजी और इनोवेशन रणनीतिक साझेदारी का दर्जा

ओस्लो में मंगलवार को तीसरे भारत-नार्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान (बाएं से) आइसलैंड की अपनी समकक्ष क्रिस्ट्रून फ्रोस्टाडटिर, स्वीडन के उल्फ क्रिस्टरसन, नार्वे के योनास गहर स्टूर, डेनमार्क की मेटे फ्रेडरिकसन और फिनलैंड के पेत्तेरी ओर्पो के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एएनआइ

ओस्लो में भारत-नार्डिक शिखर सम्मेलन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे, स्वीडन और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नरेन्द्र मोदी की बैठक
- मोदी ने कहा, नार्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई

भारत और पांच उत्तरी यूरोपीय देशों फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे, स्वीडन व डेनमार्क के संगठन नार्डिक ने आपसी संबंध को ग्रीन टेक्नोलाजी व इनोवेशन रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है। इसकी वजह से माना जा रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा जैसे अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इन देशों की कंपनियां ज्यादा खुल कर भारत में निवेश करेंगी। उक्त फैसला ओस्लो में मोदी और पांचों देशों के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में हुई तीसरे भारत-नार्डिक सम्मेलन में हुआ। पीएम मोदी ने इसे नार्डिक देशों संग भारत के संबंधों के नए स्वर्णिम युग की शुरुआत बताया। मोदी ने इन सभी देशों के प्रधानमंत्रियों से अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। नार्डिक क्षेत्र के देशों को आकर्षित करने की यह भारत की सबसे अहम पहल है। इस तरह की पहल दुनिया का कोई और देश नहीं कर रहा।

मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमने भारत और नार्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलाजी और इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलाजी पार्टनरशिप से, हम आइसलैंड की जियो-थर्मल व मछली पालन, नार्वे की सामुद्रिक आर्थिकी और आर्कटिक तथा सभी नार्डिक देशों की समुद्र विज्ञान व सतत विकास के विशेषज्ञों को भारत के स्केल (विशाल बाजार व प्रतिभा) के साथ जोड़कर, पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। पीएम ने आगे कहा कि वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में, भारत और नार्डिक देश साथ मिलकर एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को बल देते रहेंगे। चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि बहुदेशीय संस्थानों का तत्काल सुधार आवश्यक है। आतंकवाद पर हमारा स्पष्ट और एकजुट रुख है- कोई समझौता नहीं, कोई दोहरे मापदंड नहीं।

नेताओं ने अगला भारत-नार्डिक शिखर सम्मेलन हेलसिंकी में आयोजित करने का निर्णय लिया। विदेश मंत्रालय ने शिखर सम्मेलन के आठ परिणामों की एक सूची साझा की, जिसमें जलवायु कार्रवाई में भारत-नार्डिक पहल, चिन्हित एसटीईएम क्षेत्रों में अनुसंधान पहल, ब्लू अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाना, प्रतिभा की गतिशीलता को बढ़ावा देना और नार्डिक देशों के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग का निर्माण करना शामिल है।

नार्डिक देशों ने भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का समर्थन दोहराया पेज>>11

जागरण विशेष

घर में बसा दिया 'कश्मीर', खिलखिलाई केसर की फसल

मैनपुरी: धान और मूंगफली की फसल के लिए प्रसिद्ध मैनपुरी में परंपरागत खेती करने वालों के समक्ष सास-बहू ने पेश किया अनुकरणीय उदाहरण। ● पेज-7

संपादकीय

अमेरिका-चीन संबंधों के नए समीकरण: सामरिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनते हुए आर्थिक मामलों में सूझबूझ से कदम उठाए जाएं तो चीन और अमेरिका के बीच बदलते रिश्तों का भारत बड़ा लाभार्थी बन सकता है। **श्रीराम चौलिया** का आलेख।

इंदौर हाई कोर्ट के फैसले का संदेश: अयोध्या और उसके बाद भोजशाला पर आए न्यायालय के फैसले ने आने वाले मामलों को भी आधार दे दिया है। **अवधेश कुमार** का दृष्टिकोण। ● पेज-8

विमर्श

महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का नतीजा: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया बीजिंग यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। **राहुल राण्डेय** का विश्लेषण।

कैलोरी भरपूर, पोषण कमजोर: भारत में भोजन में अनाज और वसा की मात्रा बढ़ रही है, परंतु पोषण विविधता की भारी कमी है। **सुहानी गुप्ता** और **अपूर्व खंडेलवाल** का आलेख। ● पेज-9

रेबीज संक्रमित और खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोगों को बिना किसी खतरे के स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों से हटाने संबंधी आदेश वापस लेने से शीर्ष अदालत का इन्कार
- पूर्व आदेश में बदलाव और एबीसी रूल की तय एसओपी को चुनौती देने वाली सभी अर्जियां खारिज
- कहा- आदेश पालन में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि गरिमा से जीवन जीने के अधिकार में यह अधिकार भी शामिल है कि कोई व्यक्ति कुत्तों के काटने व उनके हमलों के खतरों के बिना स्वतंत्र रूप से घूम सके और सार्वजनिक जगहों पर जा सके। लोगों की सेहत और सुरक्षा की रक्षा करने के सरकार के संवैधानिक दायित्व का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार सिर्फ निष्क्रिय दर्शक बनकर नहीं रह सकती।

आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने और उनके बंध्याकरण के आदेश को वापस लेने की मांग वाली सारी अर्जियां खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने आवारा कुत्तों से जनता की सुरक्षा करने के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया और रेबीज से पीड़ित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त, खतरनाक व हिंसक कुत्तों को मारने की अनुमति दे दी। हालांकि इसमें नियम-कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने आवारा कुत्तों की समस्या पर स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही सुनवाई के मामले में ये आदेश दिए। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पूर्व में दिए गए आदेशों में बदलाव और पशु जन्म नियंत्रण नियम (एबीसी रूल) में तय एसओपी को चुनौती देने वाली सभी अर्जियां पीठ ने खारिज कर दीं।

साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और दूसरी वैधानिक संस्थाओं को आवारा कुत्तों से निपटने के लिए ढांचागत संसाधन और व्यवस्था बढ़ाने और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए की निर्देश जारी किए हैं।

कोर्ट के आदेश

- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पशु जन्म नियंत्रण ढांचे के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तत्काल कदम उठाएंगे।
- हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह से काम करने वाला पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित हो।
- संबंधित विभाग और अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।
- राज्यों के सरकारी चिकित्सा केंद्रों में एंटी रैबीज, वैक्सीन व इम्यूनोग्लोबुलिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।
- एनएचएआइ राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे पर आवारा पशुओं से निपटने के लिए तंत्र तैयार करके लागू करे।
- इस तंत्र में आवारा पशुओं के लिए परिवहन वाहनों की तैनाती व आश्रय सुविधाओं का निर्माण शामिल होगा।
- सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त व सात नवंबर, 2025 के आदेशों और वर्तमान आदेश का कड़ाई से पालन हो।
- हाई कोर्ट इस आदेश के अनुपालन की निगरानी करेंगे। 17 नवंबर को सुनवाई में अनुपालन रिपोर्ट पर विचार होगा।

कोर्ट ने कहा, जमीनी सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकते पेज>>3

जीवों की भलाई के मुकाबले इंसानी जान अधिक कीमती पेज>>3

आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार : उप्र सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा प्रस्ताव, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है मामला
- साथ ही राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा- मगर यह भविष्य के लिए नजीर नहीं होगा

उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नियुक्ति की योग्यता रखने वाले लेकिन चयन सूची से बाहर रह गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार करने के लिए राजी है, जो हाई कोर्ट की खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। हालांकि, यह नियुक्ति उम्मीदवारों की प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करने और उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा और इसे भविष्य में किसी अन्य चयन में नजीर नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव को रिकार्ड पर लिया और प्रक्रिया तैयार करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। मामले की आठ सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।

यह मामला 2018 से लंबित है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के फैसले को चुनौती दी है।

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साथ हुआ है अन्याय पेज>>7

रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली

नरेन्द्र मोदी   जार्जिया मेलोनी

भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है विशेष आलेख। ● पेज-11

पेट्रोल-डीजल के दाम 90 पैसे प्रति लीटर बढ़े, सप्ताह में दूसरी बार कीमतों में वृद्धि पेज>>5

उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापी लेने की तिथि 23 मई पेज>>7

दैनिक जागरण सप्तरंग

सेहत भरे जीवन का

गर्मी में थकान क्या है समाधान

सही न्यूट्रिशन से रुकेगा टीवी का संक्रमण!

● पेज-13

आइपीएल 19 धूम धड़ाका

आज का मैच

कोलकाता नाइटराइडर्स बनाम **मुंबई इंडियंस**

शाम 7.30 वजे स्थान: कोलकाता

प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स/जियो हाटस्टार

'चिकन नेक' कारिडोर के लिए केंद्र को 120 एकड़ जमीन देगी शुभेंदु सरकार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- बंगाल की नई भाजपा सरकार ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर जमीन हस्तांतरण का लिया फैसला
- देश की सुरक्षा, पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी और सैन्य तैयारियों को मिल सकती है नई मजबूती

बंगाल की नई भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व संवेदनशील माने जाने वाले उत्तर बंगाल में 'चिकन नेक' कारिडोर (सिलीगुड़ी कारिडोर) क्षेत्र में लगभग 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सिलीगुड़ी कारिडोर, जिसे आमतौर पर 'चिकन नेक' कहा जाता है, भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला बेहद संकरा गलियारा है। यह इलाका रणनीतिक रूप से इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके आसपास बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमाएं स्थित हैं जबकि चीन सीमा की दूरी भी अपेक्षाकृत कम है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस कारिडोर के कुछ हिस्सों की चौड़ाई महज 20 से 22 किलोमीटर है, जिससे किसी भी सैन्य या भू-राजनीतिक संकट की स्थिति में यह क्षेत्र संवेदनशील बन जाता है। यही कारण है कि भारतीय सुरक्षा रणनीति और रक्षा योजनाओं में 'चिकन नेक' कारिडोर की अहम भूमिका रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद इससे पहले राज्य में पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी थी। राज्य में हाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है।

पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए जीवनरेखा है यह कारिडोर पेज>>4

नई सुविधा

त्वरित व निर्बाध सेवाएं देने और शिकायतें घटाने की कवायद, इसके लिए एक विशिष्ट मोबाइल नंबर जारी करेगा ईपीएफओ

अब वाट्सएप पर भी ईपीएफ बैलेंस, दावे व लेन-देन की मिलेगी जानकारी

संजय मिश्र ● जागरण

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक माह में वाट्सएप पर भी ईपीएफ खातों से जुड़ी जानकारी देना शुरू कर देगा। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इससे ईपीएफ सदस्यों को पीएफ बैलेंस देखने, पिछले पांच लेन-देन, पीएफ दावे की स्थिति आदि सुविधाएं निर्बाध व त्वरित गति से मिल सकेंगी। यह संचार स्थानीय भाषा में भी होगा जिससे सदस्यों को ईपीएफओ से जुड़ने में आसानी होगी। वहीं, ईपीएफ सेवाओं से जुड़ी शिकायतें कम करने के लिए शुरू की गई समाधान योजना से मुकदमों का बोझ घटकर पिछले 10 वर्षों में सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है।

वाट्सएप सेवा के लिए ईपीएफओ एक विशिष्ट पंजीकृत मोबाइल नंबर जारी करेगा। इस पर सदस्य अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 'हेलो' का संदेश भेजकर जवाब हासिल कर सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ के वाट्सएप पर ईपीएफ खाते से जुड़ी सेवाएं लाने की तैयारी की पुष्टि की और कहा कि अधिकांश मोबाइल यूजर संचार के लिए वाट्सएप का उपयोग करते हैं। ईपीएफओ का यह कदम सेवाओं को लेकर सदस्यों की बढ़ती शिकायतों के संदर्भ में अहम है। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2025 के पहले 11 महीनों में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सरकारी विभागों से संबंधित सबसे अधिक शिकायतें दर्ज कीं, जिनमें अधिकांश ईपीएफओ से जुड़े पीएफ निकासी, पेंशन और वेतन के मामले थे।

पंजीकृत मोबाइल नंबर से भेजना होगा संदेश

ईपीएफओ पहले यह सत्यापित करेगा कि संदेश सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नंबर से आया है, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ईपीएफओ, एआइ-संचालित चैटबाट या ईपीएफओ डाटाबेस से जानकारी लेकर सदस्यों को मांगी गई संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। ईपीएफ खाते से जुड़ी शिकायतों के लिए सदस्यों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाने की दृष्टि से भी वाट्सएप सेवा को अहम माना जा रहा है।

कम हुई मुकदमेबाजी

ईपीएफ के लंबित मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ की "निधि आपके निकट" योजना के तहत मामलों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। परिणामस्वरूप उपभोक्ता न्यायालय में 31 मार्च, 2026 तक लंबित मामले 2,646 पर आ गए जो अप्रैल, 2024 तक 4936 थे। समग्र मुकदमेबाजी में भी कमी आई है। अप्रैल, 2025 में ऐसे मुकदमों की संख्या 31,036 थी, जो अप्रैल, 2026 में घटकर 27,639 पर आ गई है।

यूपीआइ के जरिये जल्द निकाल सकेंगे ईपीएफ का पैसा

मांडविया ने बताया कि ईपीएफओ के सदस्य जल्द ही यूपीआइ के जरिये ईपीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इस सुविधा का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। निकाली गई रकम सीधे सदस्य के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सदस्य बैंक खातों में ट्रांसफर करने योग्य उपलब्ध ईपीएफ बैलेंस भी देख सकेंगे। उन्हें अपने बैंक खातों में पैसे का सुरक्षित ट्रांसफर सुनिश्चित करने के लिए अपने लिंक्ड यूपीआइ पिन का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।

खुद को 'पुष्पा' बताने वाले जहांगीर खान ने फलता में चुनावी मैदान छोड़ा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

बंगाल की सियासत में 'झुकेगा नहीं' का दंभ भरने वाले तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता और फलता सीट से उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव मैदान छोड़ दिया। 21 मई को पुनर्मतदान से ठीक पहले प्रचार के आखिरी दिन जहांगीर का यह पलायन बंगाल की राजनीति में एक नए युग की आहट है।

उन्होंने चुनावी मैदान से हटने की वजह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा फलता के विकास के लिए घोषित विशेष पैकेज को बताया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को माननीय भी कहकर संबोधित किया। नामांकन वापसी की तारीख बीत जाने के कारण फिलहाल ईवीएम पर उनका नाम दर्ज रहेगा। गौरतलब है कि फलता सीट डायमंड हार्बर लोस क्षेत्र के अंतर्गत आती है जहां से पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। जहांगीर को उनका करीबी माना जाता है।

जहांगीर खान। आइएएनएस

बंगाल की इस विधानसभा सीट पर गुरुवार को होना है पुनर्मतदान

तृणमूल ने इसे जहांगीर का व्यक्तिगत फैसला बताया। हालांकि, तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने तंज कसते हुए पूछा कि जिसके चलने पर 'बास' का बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था, वह 'पुष्पा' आखिर झुक क्यों गया? क्या 'बास' डर गया? यह तो अभिषेक बनर्जी बताएं कि पुष्पा झुका क्यों?

शुभेंदु का 'शून्य चैलेंज' पेज>>5

20 विशेष शिविर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू किए हैं। यह शिविर जनता के बीच लगाए जा रहे हैं, जहां पर महिलाएं जाकर आसानी से अपने पिंक कार्ड बनवा सकती हैं। पहले से 36 डीटीसी पास सेक्शन और 17 डीएम, एसडीएम कार्यालय में यह सुविधा चल रही है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 20 मई, 2026

आज का मौसम

बुधवार को आसमान साफ रहेगा। तेज धूप में ज्यादातर जगह लू चलेगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
20 मई	45.0	27.0
21 मई	44.0	27.0
नोएडा		
20 मई	44.0	29.0
21 मई	44.0	29.0
गुरुग्राम		
20 मई	42.0	29.0
21 मई	43.0	29.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

छात्र कार्यकर्ताओं के प्रताड़ना में सीबीआइ जांच से इन्कार

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना और अवैध हिरासत के मामले में फिलहाल सीबीआइ जांच कराने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट में बताया गया कि जांच के लिए दक्षिणी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त को नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर जांच शुरू हो चुकी है, इसलिए पहले उसे पूरा होने दिया जाए। (जासं)

जजों पर अभद्र टिप्पणी प्रसारित करने के आरोप में केस दर्ज

गाजियाबाद : वाट्सएप ग्रुप व इंटरनेट मीडिया पर न्यायाधीशों को लेकर अभद्र टिप्पणी प्रसारित करने के आरोप में साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अवमानना मामले में पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच की। पता चला कि इंदिरापुरम स्थित शिप्रा सनसिटी के पिंटू तोमर उर्फ आदेश तोमर ने वाट्सएप ग्रुप व फेसबुक से न्यायपालिका को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। (जासं)

यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को छह माह की सजा

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइट फार ज्यूडिशियल रिफर्म्स नामक यूट्यूब चैनल चलाने वाले गुलशन पाहुजा को अदालत और न्यायिक अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में दो आपराधिक अवमानना मामलों में छह माह की साधारण कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक मामले में दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। (जासं)

कुतुब मीनार परिसर में भी पूजा की अनुमति मिलने की उम्मीद

वी के शुक्ला • जागरण

नई दिल्ली : धार स्थित भोजशाला में पूजा करने की अनुमति मिलने के बाद हिंदू संगठनों को उम्मीद है कि दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में भी पूजा करने की अनुमति मिल जाएगी। इस संबंध में जल्द हिंदू संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के बैनर तले भोजशाला मामले में हिंदुओं की ओर से मुकदमा लड़ने वाले वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन से मिलकर सलाह लेगा। वैसे, विष्णु शंकर जैन ने वर्ष 2020 में कुतुब मीनार परिसर में भी पूजा करने की अनुमति के लिए साकेत कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो 2023 में खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने दोबारा याचिका डाल दी थी, जो अभी लंबित है। हिंदू संगठनों की ओर से इस कानूनी लड़ाई को तेज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

बताया जाता है कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ राजा अनंगपाल द्वारा बनाए गए विष्णु मंदिर में स्थापित था। इसे विष्णु स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ के पास ही वह विवादित ढांचा भी मौजूद है, जिसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। इसे कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद नाम दिया गया है। इस ढांचे में आज भी हिंदू देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां मौजूद हैं। लौह स्तंभ पर लिखी गई भाषा को 1903 में पढ़ा गया था। इसके अनुसार यह स्तंभ चौथी शताब्दी में राजा चंद्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। स्तंभ के ऊंपर बने एक छेद से यह माना जा रहा है कि कभी इस स्तंभ के ऊपर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति लगी थी। इसे वर्तमान स्थान पर राजा अनंदपाल द्वारा लाया गया था। वह इसे कहां से लाए थे, इसके बारे में जानकारी मौजूद नहीं है। मगर यह स्पष्ट है कि यह वर्तमान स्थान पर राजा अनंगपाल द्वारा बनवाए गए भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित था। स्तंभ की लिखावट पढ़ने के बाद एक जनवरी 1903 में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, चार भाषाओं में उच्चारण कर अलग-अलग शिलालेख लगाए गए हैं।

मस्जिद में देवी-देवताओं की मूर्तियां देख आहत होती हैं हिंदुओं की भावनाएं : कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के गेट पर वह शिलालेख मौजूद है, जिस पर लिखा हुआ है कि इसे 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। मस्जिद में कई स्थानों पर मूर्तियां दीवारों में लगी हुई हैं। कहीं भगवान विष्णु की मूर्ति है तो कहीं माता पार्वती गणेश जी को गोद में लिए हुए हैं। गणेश जी की मूर्ति अनादर करने की नीयत से दीवार के निचले भाग में लगी है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) विभाग ने कांच के बाक्स से ढंक जरूर दिया है, लेकिन मूर्ति और कांच के बाक्स को लंबे समय से साफ नहीं किया गया है।

कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद का ढांचा देश की दूसरी भोजशाला है : डा. धर्मवीर : एएसआइ के पूर्व निदेशक डा. धर्मवीर शर्मा की मानें तो कुतुब मीनार परिसर में स्थित विवादित ढांचे को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर जामा मस्जिद के नाम से बनाया था। अब से करीब ढाई सौ साल पहले इसे कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद नाम दिया गया था। उनके अनुसार यह ढांचा देश की दूसरी भोजशाला है। इसमें भी भोजशाला की तरह ही मंदिर होने के कई प्रमाण मौजूद हैं।

▶ कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में लगी हैं कई देवी-देवताओं की मूर्तियां

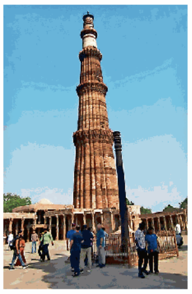

मस्जिद परिसर में स्थित विष्णु स्तंभ और पीछे की ओर कुतुबमीनार। जागरण

> विवादित ढांचे के मलबे और दीवारों में आज भी हिंदू देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां और सनातन संस्कृति के प्रतीक चिह्न स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। जब धार की भोजशाला में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिल सकती है, तो दिल्ली के इस ऐतिहासिक परिसर में सदियों से उपेक्षित पड़ी देवी-देवताओं की मूर्तियों की पूजा-अर्चना का अधिकार भी मिलना ही चाहिए।
>
> **- जयभगवान गोयल, अध्यक्ष, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट**

> कुतुब मीनार परिसर में पूजा का अधिकार मांगने के लिए साकेत कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने पूजा स्थल (विशेष प्रविधान) अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद फिर से याचिका डाली गई, जिस पर नोटिस जारी हुए। यह याचिका अभी लंबित है। उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा।
>
> **- विष्णु शंकर जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता**

▶ परिसर में पूजा की अनुमति के लिए दाखिल याचिका खारिज चुका है साकेत कोर्ट, दूसरी याचिका लंबित

मस्जिद परिसर में रखी माता पार्वती की गणेश जी को गोद में लिए की खंडित मूर्ति। जागरण

निर्माण श्रमिकों को सत्तू, ओआरएस व गमछा युक्त किट बांटेगी दिल्ली सरकार

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों को सत्तू, ओआरएस, शरबत, घमौरी पाउडर, गमछा और अन्य सामग्री युक्त किट वितरित करेगी। सरकार ने दिल्ली भवन एवं अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत लगभग एक लाख श्रमिकों को समर किट की खरीद, पैकेजिंग व वितरण के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक किट में नौ वस्तुएं होंगी, जिनमें 250 ग्राम इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज, एक किलो प्रीमियम गुणवत्ता वाला सत्तू, 30 ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन (ओआरएस) पाउच, सूती गमछा, धूप से बचाव वाली टोपी, घमौरी पाउडर, एक लीटर पानी की बोतल और शरबत शामिल है। इन्हें एक टिकाऊ बैग में रखा जाएगा। हर किट वितरण की अनुमानित लागत 1890 रुपये है। बोर्ड का उद्देश्य लगभग 1,00,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ग्रीष्मकालीन किट की समय पर आपूर्ति व वितरण सुनिश्चित करना है ताकि उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा व कार्य स्थितियों में सुधार हो। परिस्थितियों के अनुसार श्रमिकों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

23,000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा

गडकरी ने किया एलान ▶ नोएडा-फरीदाबाद हाई-स्पीड कारिडोर पर खर्च होंगे 7,500 करोड़ रुपये

एम्स से महिपालपुर-गुरुग्राम तक बनेगा एलिवेटेड करिडोर, ट्रैफिक दबाव होगा कम

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दिल्ली से जुड़ी 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की आगामी परियोजनाओं की घोषणा की। इनमें यूईआर-दो से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के लिए 3500 करोड़ रुपये की छह-लेन परियोजना, नोएडा-फरीदाबाद हाई-स्पीड कारिडोर के लिए 7,500 करोड़ रुपये की परियोजना, दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, शिवमूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक 7,000 करोड़ रुपये की टनल परियोजना और एम्स से महिपालपुर-गुरुग्राम तक 5,000 करोड़ रुपये का एलिवेटेड करिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से दिल्ली में ट्रैफिक दबाव कम होगा और इसकी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अधिक मजबूत होगी।

कालिंदी कुंज इंटरचेंज एवं फ्लाईओवर, आश्रम-बदरपुर सिक्स-लेन करिडोर, हरियाणा-दिल्ली बार्डर से पंजाबी बाग तक सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी और महरौली से दिल्ली-हरियाणा बार्डर तक सिक्स-लेन करिडोर जैसी परियोजनाओं से दिल्ली के भीतर यातायात और अधिक तेज, सुरक्षित और अवरोध-मुक्त होगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये परियोजनाएं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जीवनरेखा बनेंगी। उन्होंने ओखला व गाजीपुर लैंडफिल साइट से निकलने वाले लाखों टन इनर्ट (निष्क्रिय मिट्टी) का उपयोग हाइवे में करने के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी का आभार जताया।

उन्होंने कहा 'डबल इंजन सरकार' के साझा प्रयासों से दिल्ली आज ट्रैफिक जाम और प्रदूषण जैसी पुरानी समस्याओं से बाहर निकलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे राजधानी के लोगों को राहत मिलेगी।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नीचे ओखला हेड के पास से गुजर रही मेट्रो लाइन को देखते केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जागरण

सड़क नेटवर्क से बदल रहा भूगोल, अब फ्यूचर-रेडी है दिल्ली : रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दिल्ली में आधुनिक, विश्वस्तरीय और फ्यूचर-रेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य किया है। इससे राजधानी को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं से राहत मिल रही है।

यदि केंद्र सरकार के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड करिडोर, टनल और सिग्नल-फ्री सड़क नेटवर्क का निर्माण नहीं हुआ होता तो आज दिल्ली में ट्रैफिक जाम की स्थिति की कल्पना करना भी कठिन होता। पिछले 12 वर्षों में केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के विकास के लिए 1,31,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। वहीं केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जानकारी दी कि अब पूर्ण हो चुकी, निर्माणाधीन और आगामी योजनाओं को मिलाकर दिल्ली व एनसीआर में कुल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का दायरा लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

कालिंदी कुंज-मथुरा रोड पर ट्रैफिक होगा कम, फरीदाबाद का यातायात बनेगा सुगम

मुहम्मद रईस • जागरण

नई दिल्ली : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) के डीएनडी महारानी बाग से जैतपुर पुश्ता रोड तक का नौ किलोमीटर का हिस्सा शुरू होने के बाद दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी और समय भी बचेगा। डीएमई का जैतपुर पुश्ता रोड से आगे फरीदाबाद सेक्टर-65 तक का 24 किलोमीटर का हिस्सा और सेक्टर-65 से आगे सोहना तक 26 किलोमीटर का हिस्सा पहले से चालू है।

नौ किमी हिस्से के चालू होते ही दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से फरीदाबाद, पलवल आने-जाने वाले हजारों वाहन चालकों को तेज और सुगम रास्ता मिल जाएगा, जो मथुरा रोड और कालिंदी कुंज रोड का विकल्प भी बनेगा। वहीं कालिंदी कुंज चौराहे पर भारी यातायात दबाव भी ट्रैफिक को जाम कर देता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नौ किमी के नए तैयार हिस्से के साथ ही पहले से तैयार फरीदाबाद सेक्टर-65 तक के हिस्से का निरीक्षण किया। दिल्ली के मीठापुर चौक पर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पहले ही बना दिए गए हैं, जिससे दक्षिण दिल्ली के लोगों को लाभ मिलेगा। डीएनडी से मीठापुर तक आने वाले भी इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे और उन्हें जाम से मुक्ति मिलेगी। दक्षिणी दिल्ली के लोगों को सोहना जाने में पहले ढाई घंटे लगते थे। अब लोग 28 मिनट में पहुंच रहे हैं और 30 मिनट में बड़ौदा-मुंबई हाइवे पर पहुंच जा रहे हैं।

> **कालिंदी कुंज के पास बना सबसे लंबा नेटवर्क आर्क ब्रिज**
>
> **जासं, नई दिल्ली :** डीएनडी महारानी बाग से जैतपुर पुश्ता रोड तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नौ किमी के हिस्से में से 7.50 किमी एलिवेटेड है। इसी एलिवेटेड हिस्से पर कालिंदीकुंज के पास आगरा कैनाल पर देश का सबसे लंबा स्टील 'नेटवर्क आर्क ब्रिज' बनाया गया है। एनएचएआइ के मुताबिक इसमें 2,396 टन स्टील का उपयोग किया गया है। इसकी लंबाई 140 मीटर है। नेटवर्क आर्क ब्रिज मेट्रो क्रासिंग या नहरों के ऊपर वहां बनाए जाते है। इस ब्रिज को आधुनिक 'टाइड-आर्क' तकनीक का इस्तेमाल कर डिजाइन किया गया है।

उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा की साजिश रचने के आरोपित उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेई ने 15 दिन की अंतरिम जमानत देने से इन्कार करते हुए कहा कि याचिका में बताए गए आधार पर्याप्त नहीं हैं।

याचिका में उमर खालिद ने अपने चाचा के चेहल्लुम (मौत के बाद का चालीसवां दिन) में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए राहत मांगी थी। अदालत को बताया गया कि उनकी मां की अगले महीने सर्जरी होनी है और परिवार में उनकी उपस्थिति आवश्यक है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह आधार ठोस नहीं हैं और आरोपित अदालत की उदारता का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। अदालत ने कहा कि चेहल्लुम में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। यदि संबंध इतना करीबी होता, तो आरोपित पहले ही अंतिम संस्कार के समय राहत मांग सकता था। मां की सर्जरी के मुद्दे पर अदालत ने माना कि परिवार में अन्य सदस्य मौजूद हैं, जो देखभाल कर सकते हैं।

दीपिका के शरीर के ऊपर और अंदर 13 गंभीर चोटें मिलीं, लिवर व किडनी फटी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

सूरजपुर कोतवाली अंतर्गत जलपुरा निवासी दीपिका नागर की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर हुई मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट नहीं हो सका है। रिपोर्ट में ऊपरी और अंदरूनी अंगों में छोटी बड़ी 13 गंभीर चोटें होने की पुष्टि हुई है। यह चोटें घटना से पहले दीपिका संग निर्ममता से पिटाई होने की ओर इशारा कर रही हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दीपिका नागर के शरीर पर कई जगह चोट, सूजन और गहरे घाव मिले हैं। सबसे बड़ी चोट चेहरे के दाहिने हिस्से पर में है। यहां पर करीब 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई में अंदरूनी चोट है। बाएं हाथ की कोहनी पर भी चोट के निशान आए हैं। दाहिनी जांघ पर लगभग 38 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा दबाव और नीला निशान मिला। बाएं घुटने पर हड्डी तक गहरा घाव मिला। कमर और पेट के निचले हिस्से में भी चोटों के निशान हैं। दाहिने कूल्हे के ऊपर गोल आकार की अंदरूनी चोट के साथ दोनों हाथों पर चोटें हैं और बाएं कान से खून निकला है। मस्तिष्क के बीच और बाईं ओर खून का थक्का मिला। तिल्ली (स्प्लीन) फटी मिली। कई हिस्सों में अंदरूनी रक्तस्राव मिला। हृदय के चैंबर खाली और बाईं किडनी पीली होने का जिक्र है। फिलहाल, मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने से जहरीले पदार्थ की आशंका के चलते बिसरा सुरक्षित कर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है।

▶ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर, हाथ-पैर व पेट समेत शरीर के अधिकतर अंगों पर चोटों के निशान

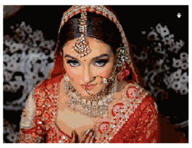

मृतक दीपिका नागर की फाइल फोटो। सौ. स्वजन

यूपीएससी की तैयारी कर रही महिला ने मायके में फांसी लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : क्रासिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र के रघुनाथपुरी में मंगलवार सुबह करीब छह बजे एक विवाहिता का शव मायके में फंदे पर लटका मिला। 24 वर्षीय पूजा की पांच फरवरी को ही शादी हुई थी। स्वजन का कहना है कि पूजा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तीन प्रयास में सफल न होने पर वह डिप्रेशन में थी। पूजा तीन माह की गर्भवती भी थी।

मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि रघुनाथपुरी में एक महिला ने मायके में फांसी लगा ली है। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि 24 वर्षीय पूजा ने आत्महत्या की है। पूजा के पिता रमन कुमार यादव ने बताया कि उन्होंने पांच फरवरी को ही अपनी बेटी की शादी बिहार के सुपौल में की थी। कुछ समय से पूजा उनके यहां ही रह रही थी। प्रतियोगी परीक्षा में तीन साल से सफल न होने से वह तनाव में थी। उसको काफी समझाया भी था, लेकिन उसका तनाव कम नहीं हुआ। उन्होंने ससुराल में परेशान किए जाने से मना किया है।

आबकारी नीति मामले में हाई कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य आरोपितों को भेजा नया नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपितों को ट्रायल कोर्ट से मिली राहत को चुनौती देने वाली सीबीआइ की याचिका पर नया नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके चलते न्यायमूर्ति मनोज जैन ने सुनवाई 25 मई तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने सीबीआइ को निर्देश दिया कि वह आरोपितों को आबकारी नीति मामले की सुनवाई नई पीठ को सौंपे जाने की जानकारी दें।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जैन ने पूछा कि क्या आरोपित अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से कोई पेश हुआ है? इस पर सीबीआइ की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नौ मार्च को जारी नोटिस सभी पक्षों को तामील हो चुके हैं और सभी आरोपितों को कार्यवाही की पूरी जानकारी है। अदालत ने टिप्पणी की कि फिर भी अभियोजन पक्षकारों को सूचित करे कि मामला इस अदालत के समक्ष है और यदि वे पेश होना चाहें तो हो सकते हैं।

आप की मान्यता रद करने की मांग: दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआइएल) दाखिल कर चुनाव आयोग को निर्देश देकर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद करने और केजरीवाल, सिसोदिया व दुर्गेश को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।

▶ आरोपितों की तरफ से नहीं हुआ कोई पेश, 25 मई तक के लिए टली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल

> **अवमानना मामले में भेजा नोटिस**
>
> दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले की सुनवाई से जुड़ी इंटरनेट मीडिया पोस्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई आप नेताओं से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आपराधिक अवमानना मामले में आरोपितों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने मंगलवार को अवमानना कार्यवाही पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी। यह मामला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा 14 मई को शुरू आपराधिक अवमानना कार्यवाही से जुड़ा है। आरोप लगाया था कि सुनवाई के दौरान इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करने व न्यायपालिका की छवि धूमिल करने का अभियान चलाया गया।

भीषण गर्मी के साथ बिगड़ी हवा, लागू हुईं ग्रेप एक की पाबंदियां

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच एनसीआर की वायु गुणवत्ता भी 'खराब' हो गई है। इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर में ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) एक की पाबंदियों को लागू कर दिया है।

सीएक्यूएम द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 19 मई को दिल्ली का एक्यूआइ 208 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग और आइआइटीएम ने आने वाले दिनों में भी शहर का एक्यूआइ इसी श्रेणी में रहने का अनुमान लगाया है। इसे देखते हुए शहर में ग्रेप एक की पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में 31 बिंदुओं की कार्ययोजना के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं। आयोग ने निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों में धूल नियंत्रण के नियमों का पालन अनिवार्य किया है और बिना पंजीकरण वाले बड़े निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी।

रिज में तापमान पहुंचा 46 डिग्री के पार, छह दिन लू का आरेंज अलर्ट: भीषण गर्मी की चपेट में चल रही राजधानी में मई में ही लोगों का हाल बेहाल हो गया है। मंगलवार को अनेक इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया।

मौसम विभाग ने अगले छह दिनों तक लू चलने का आरेंज अलर्ट जारी किया है। आलम यह है कि तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों के बीच दोपहर में सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम ही दिखाई दे रही है। 2024 के बाद इस साल मई में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। 2024 में 26 से 30 मई तक छह दिन अधिकतम तापमान 45 डिग्री से अधिक था।

प्रधानमंत्री आवास के पास झुग्गी बस्तियों पर फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित तीन झुग्गी बस्तियों के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए फिलहाल उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, अगली सुनवाई तक जिन लोगों ने अभी तक अपने घर खाली नहीं किए हैं, उन्हें जबरन नहीं हटाया जाए।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने भाई राम कैंप, डीआइडी कैंप व मस्जिद कैंप के कुछ निवासियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर अंतरिम राहत दी। ये तीनों झुग्गी बस्तियां लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित हैं, जहां प्रधानमंत्री का आवास है। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) व अपीलकर्ताओं के वकीलों से पुनर्वास व्यवस्था पर निर्देश लेने को कहा।

न्यू अशोक नगर थाने के मालखाने में लगी भीषण आग, 131 वाहन धू-धू कर जले

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। मंगलवार दोपहर करीब एक बजे न्यू अशोक नगर थाने के आवासीय परिसर में मालखाने में खड़े वाहनों में भीषण आग लग गई। पूरा मालखाना आग की चपेट में आ गया।

पुलिसकर्मियों ने अग्निशामक यंत्र और परिसर में लगे ओवरहेड टैंक के पानी का इस्तेमाल कर आग बुझाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पांच गाड़ियों में दमकल कर्मी भी पहुंच गए। एक घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया लिया। आग में 131 वाहन जले हैं। इनमें अधिकांश पुलिस की तरफ से जब्त किए गए वाहन हैं। दमकल के मुताबिक, जले वाहनों में 58 कारें, 40 बाइक, चार आटो, तीन टेंपो, पांच ई-रिक्शा, एक तेल टैंकर और 20 पैडल रिक्शा शामिल हैं। न्यू अशोक नगर थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मालखाने के पास ही आवासीय परिसर में रहने वाले कर्मचारी भी अपने वाहन खड़े करते हैं। मालखाने से धुआं उठता देखकर पुलिसकर्मी वहां से अपने वाहन हटाने लगे थे। इसके बाद भी उनकी चार कारें आग की चपेट में आई हैं। आग लगने ही पुलिसकर्मियों ने उसे बुझाना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से यह पास ही में स्थित पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाई। वहीं, कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि थाने के पास ही दमकल विभाग का कार्यालय है। इसके बाद भी दमकल एक घंटे देरी से पहुंची। वहीं, इस मामले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि विधायक झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने दमकलकर्मियों की बहादुरी का अपमान किया है। सूचना मिलने के चार मिनट में दमकल की टीम पहुंच गई थी।

▶ दमकल व पुलिस कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बुझाई आग

न्यू अशोक नगर थाने के आवासीय परिसर में वाहनों में लगी आग को बुझाने में लगे दमकलकर्मी। सौ-सुधी पाठक

सुप्रीम कोर्ट में पेश नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन के दो आरोपित जेल में ही रहेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : नोएडा में पिछले महीने औद्योगिक श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपितों को 15 मई के आदेश के अनुसार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून काम करेगा और दोनों आरोपित न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने दोनों आरोपितों आदित्य आनंद और रूपेश राय से बातचीत की। दोनों आरोपितों ने पीठ को पुलिस हिरासत में उनके साथ कथित प्रताड़ना और गैरकानूनी बर्ताव के बारे में बताया। जस्टिस भुइयां ने टिप्पणी की कि आरोपितों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। यह याचिका लंबित होने के कारण दोनों आरोपितों को कानून के अनुसार राहत मांगने में कोई बाधा नहीं आएगी।

238 करोड़ रुपये की परियोजना जम्मू-श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग के लिए मंजूर की गई है। इसके तहत कटरा रेल मार्ग पर संवेदनशील स्थानों पर ढलानों का सुदृढ़ीकरण, सुरंगों में पानी का रिसाव रोकने और पुलों की सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल हैं।

विकसित बस्तर का रोडमैप पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा, अब भय से जीने की जरूरत नहीं

माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोग भेष बदलकर आएंगे, पर बहकावे में नहीं आना है

केंद्र और राज्य में जनता की चुनी हुई सरकारें हैं, ये लोकतांत्रिक तरीके से पूरे बस्तर का करेंगी विकास

नीलू रंजन • जागरण

जगदलपुर: पांच दशक से चली आ रही माओवादी हिंसा से मुक्ति के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विकसित बस्तर का रोडमैप पेश किया। माओवादियों के खात्मे के बाद पहली बार प्रेस कान्फ्रेंस करते हुए शाह ने 2031 तक विकसित बस्तर बनाने का वादा किया। उन्होंने यहां के सभी नागरिकों को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से विश्वास दिलाते हुए कहा कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं है, यहां नया सूर्योदय हो चुका है। यहां के आदिवासी युवा और महिलाएं विश्वास के साथ आगे बढ़ें। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार उनके साथ है। अब बस्तर विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है। अब यहां की जनता को सजग रहना चाहिए, क्योंकि बंदूक लेकर बस्तर को बर्बाद करने वाले माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोग भेष बदलकर आएंगे, लेकिन आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। केंद्र और राज्य में जनता द्वारा चुनी हुईं सरकारें हैं। ये लोकतांत्रिक तरीके से पूरे बस्तर का विकास करेंगी। इसके तहत सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को शत-प्रतिशत लोगों तक पहुंचाना और वनोपजों की पैकेजिंग, मार्केटिंग के साथ ही कौशल विकास और दुग्ध उत्पादन द्वारा आम लोगों की आय बढ़ाना भी शामिल है।

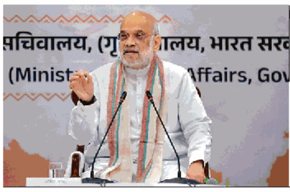

जगदलपुर में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सौ. गृह मंत्रालय

- हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस देने का किया एलान

शाह के विकसित बस्तर के रोडमैप में सुरक्षा कैंपों की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि बस्तर के इन कैंपों को सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन इसका माडल तैयार कर रहा है। इन सेवा केंद्रों के सहारे केंद्र और राज्य की 371 योजनाओं का लाभ लोगों तक शत प्रतिशत पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। जिनमें जन वितरण प्रणाली की दुकानें, कामन सर्विस सेंटर, आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बैंकिंग सेवाएं तक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सेवा केंद्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये किसानों की प्राथमिक समिति (पैक्स) के रूप में भी काम करेंगे। बस्तर में हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस देने का एलान करते हुए कहा कि सेवा केंद्र दूध एकत्र कर डेरी तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। उनके अनुसार, नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ छत्तीसगढ़ सरकार का करार हो चुका है। शाह ने कहा कि माओवादियों के कारण पिछले पांच दशक तक बस्तर विकास से अछूता रह गया। इसे देश के अन्य भागों के समकक्ष लाने में पांच साल का समय लगेगा। 13 दिसंबर 2023 में यहां भाजपा की सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद शुरू की। हमारे सुरक्षाबलों के पराक्रम, साहस और बलिदान के कारण 31 मार्च, 2026 की जो तिथि तय हुई थी, उससे पहले ही देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है।

सरकार ने बनाई है पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास की कार्ययोजना : अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में माओवाद मुक्त हुए बस्तर सहित पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास की एक कार्ययोजना भारत सरकार ने बनाई है। हमने 20557 करोड़ रुपये की लागत से 12211 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर दिया है। 1804 बैंक शाखाएं खुली हैं, 1321 एटीएम खुल चुके हैं और 890 पोस्ट आफिस खोलने का काम भी पूरा हो चुका है।

दिल्ली में 12 व 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन

- इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, एक साल के भीतर पुतिन का यह दूसरा भारत दौरा होगा
- इससे पहले दिसंबर 2025 में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे पुतिन

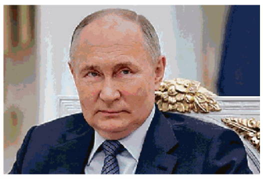

व्लादिमीर पुतिन। फाइल

मास्को, प्रेट्र : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्रेमलिन (रूसी राष्ट्रपति कार्यालय) के अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने इस बात की पुष्टि की है। साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसके तहत इस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली द्वारा की जाएगी। एक साल के भीतर पुतिन का यह दूसरा भारत दौरा होगा। इससे पहले वह दिसंबर 2025 में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे।

चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की योजना : इस शिखर सम्मेलन के इतर राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है। गौरतलब है कि इसी महीने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी नई दिल्ली में ब्रिक्स सदस्य देशों के दो दिवसीय विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी।

वैश्विक मंच पर ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव : मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के इस संगठन (ब्रिक्स) का लगातार विस्तार हो रहा है। साल 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) इसमें शामिल हुए, जबकि 2025 में इंडोनेशिया इसका हिस्सा बना। वर्तमान में 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का यह समूह वैश्विक मंच पर बेहद शक्तिशाली हो चुका है। यह दुनिया की कुल आबादी के लगभग 49.5 प्रतिशत, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के करीब 26 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

पुतिन की चीन यात्रा : ट्रंप-शी बैठक के बाद रूस-चीन संबंधों को मजबूत करने की पहल

बीजिंग, एपी: पुतिन मंगलवार से दो दिवसीय चीन यात्रा पर हैं, जहां वे चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के ठीक एक हफ्ते बाद हो रही है। क्रेमलिन के अनुसार, दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह दौरा 2001 की 'चीन-रूस मित्रता संधि' की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच चीन, रूस का एक अहम व्यापारिक भागीदार रहा है। चीन इस संघर्ष में खुद को तटस्थ रखता आया है। बीजिंग की कोशिश अमेरिका के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने के साथ-साथ रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को भी अक्षुण्ण रखने की है।

एअर इंडिया के ड्रीमलाइनर के फ्यूल स्विच माड्यूल की होगी विस्तृत जांच

- डीजीसीए ने अमेरिका में बोइंग प्लांट में इसकी जांच कराने का लिया निर्णय
- फरवरी में एक पायलट ने की थी इस स्विच में गड़बड़ी की शिकायत

नई दिल्ली, प्रेट्र: एअर इंडिया के एक ड्रीमलाइनर विमान के फ्यूल स्विच माड्यूल की विस्तृत जांच कराई जाएगी। गत फरवरी में एक पायलट ने इस स्विच में गड़बड़ी की शिकायत की थी। एयरलाइन ने कहा कि यह जांच अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिहाज से की जा रही है।

गत दो फरवरी को एअर इंडिया के एक पायलट ने बोइंग 787-8 विमान के फ्यूल स्विच माड्यूल में गड़बड़ी की शिकायत की थी। उन्होंने यह शिकायत एआइ132 उड़ान का संचालन करने के बाद की थी। इस विमान ने एक फरवरी को लंदन में इंजन स्टार्ट के दौरान फ्यूल स्विच माड्यूल में समस्या का सामना किया था। इसके बाद एअर इंडिया ने ऐहतियात के तौर पर अपने सभी बोइंग 787 विमानों के फ्यूल स्विच माड्यूल की जांच कराई थी और उस दौरान कोई समस्या नहीं पाई गई थी।

सूत्रों के अनुसार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निर्णय लिया है कि उस विशेष फ्यूल स्विच माड्यूल की जांच अमेरिका में बोइंग के प्लांट में कराई जाएगी। एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और डीजीसीए पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि फ्यूल स्विच माड्यूल पूरी तरह काम कर रहे हैं। आगे की जांच प्रक्रिया को बढ़ाने का निर्णय यह सुनिश्चित करना है कि अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। हालांकि डीजीसीए और बोइंग की ओर से इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं आई है।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 12 जून को एअर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद फ्यूल स्विच माड्यूल के काम पर ध्यान केंद्रित हुआ था। अहमदाबाद में इस हादसे में 260 लोगों की जान गई थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि उड़ान भरने के तुरंत बाद ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी।

अच्छी मुलाकात...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (दाएं) मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पूर्वोत्तर राज्यों से आए कारीगरों और बुनकरों के एक समूह से बातचीत करती हुईं। प्रेट्र

जीवों की भलाई के मुकाबले इंसानी जान अधिक कीमती : सुप्रीम कोर्ट

प्रथम पृष्ठ से आगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्यों की जिम्मेदारी को प्रशासनिक असुविधा, वित्तीय बाधाओं या लाजिस्टिक चुनौतियों के आधार पर कम या टाला नहीं जा सकता। ऐसे मामले जो शासन की प्राथमिकताओं में आते हैं, उन्हें कार्यकारी निष्क्रियता के लिए संवैधानिक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के आंकड़े भी दिए और इन पर चिंता जताते हुए कहा कि जब इंसानों की सुरक्षा को, संवेदनशील जीवों के हितों और भलाई के मुकाबले तौला जाता है, तो संवैधानिक संतुलन को अनिवार्य और बिना किसी शक के इंसानी जान की रक्षा व सुरक्षा में झुकना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद-21 में मिला जीवन का अधिकार संवैधानिक सुरक्षा के सबसे ऊंचे पायदान पर है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि पशु जीवन के प्रति करुणा, चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसकी व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती कि वह नागरिकों को अपने स्वयं के जीवन, सुरक्षा के प्रति बार-बार उत्पन्न होने वाले खतरों को सहने के लिए विवश करे।

जमीनी सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकते : पीठ ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की याचिकाओं के जवाब में कहा कि कोर्ट जमीनी सच्चाई से आंखें नहीं फेर सकता, जहां बच्चे, बुजुर्ग और विदेशी यात्री कुत्तों के काटने की घटनाओं का शिकार हुए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा कि जिन इलाकों में आवारा कुत्तों की आबादी खतरनाक हद तक बढ़ गई है या जहां कुत्तों के काटने या हिंसक हमलों की घटनाएं आम हो गई हैं, वहां संबंधित अधिकारी योग्य पशु विशेषज्ञों के मूल्यांकन के बाद, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और पशु जन्म नियंत्रण नियम (एबीसी रूल) और अन्य संबंधित कानूनी प्रोटोकाल का पालन करते हुए रेबीज से पीड़ित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त, स्पष्ट रूप से खतरनाक एवं हिंसक कुत्तों को मारने का आदेश दे सकते हैं।

मंदिरों के सोने के मुद्रीकरण की कोई योजना नहीं : सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने मंदिरों के पास रखे सोने के मुद्रीकरण की किसी भी योजना से इन्कार किया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को इन अफवाहों और अटकलों को पूरी तरह से गलत बताया है। स्पष्ट किया कि ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि देशभर के मंदिर न्यासों या किसी भी धार्मिक संस्थान के पास रखे सोने के लिए मुद्रीकरण योजना शुरू करने की कोई योजना नहीं है। ये अफवाहें पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और निराधार हैं।

मंत्रालय ने उन दावों को भी खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि मंदिर के गुंबदों, दरवाजों या अन्य संरचनाओं पर लगी सोने की परतें 'भारत के रणनीतिक स्वर्ण भंडार' का हिस्सा मानी जाएंगी। इन दावों को भी गलत और निराधार बताया गया। सरकार ने नागरिकों से ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करने और उन्हें प्रसारित न करने का आग्रह किया है।

हावड़ा-दिल्ली मार्ग पर किउल-झाझा तीसरी रेल लाइन परियोजना मंजूर

- वैष्णव बोले, इससे हावड़ा-दिल्ली रेल कारिडार की क्षमता बढ़ेगी
- रेलवे ने 2,193 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली, एएनआइ: भारतीय रेलवे ने सबसे व्यस्त हावड़ा-दिल्ली रेल मार्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए किउल-झाझा तीसरी लाइन के निर्माण और जम्मू-श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर सुरक्षा मजबूत करने समेत 2,193 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

रेल मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हावड़ा-दिल्ली रेल मार्ग पर किउल-झाझा तीसरी लाइन के लिए मंजूरी दी गई है। 54 किमी लंबी इस परियोजना की लागत 962 करोड़ रुपये होगी। जम्मू-श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग के लिए 238 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत कटरा रेल मार्ग पर संवेदनशील स्थानों पर ढलानों को मजबूत करना, सुरंगों में पानी रिसाव की समस्या का समाधान और पुलों की सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल हैं। जबकि चेन्नई के उपनगरी रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अरक्कोनम-चेंगलपट्टू लाइन के दोहरीकरण परियोजना को भी मंजूरी मिली है। 68 किमी लंबी इस परियोजना की लागत 993 करोड़ रुपये होगी।

अश्विनी वैष्णव। फाइल

प्रेट्र के अनुसार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किउल-झाझा तीसरी लाइन परियोजना से हावड़ा-दिल्ली कारिडोर पर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रेल सेवाओं की समय पाबंदी और परिचालन में सुधार करने में मदद मिलेगी।

तेलंगाना में सीधी भर्ती के लिए ऊपरी उम्र सीमा में 10 वर्ष की वृद्धि

हैदराबाद, आइएएनएस: तेलंगाना सरकार ने सीधी भर्ती के लिए ऊपरी उम्र सीमा में 10 वर्ष की वृद्धि की है। इसके साथ ही, ऊपरी उम्र सीमा 34 वर्ष से बढ़कर 44 वर्ष हो गई है। यह छूट केवल एक साल के लिए है।

राज्य सरकार इससे पहले फरवरी, 2024 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की वृद्धि की थी। हालांकि, फरवरी 2026 में आदेश के निरस्त होने के साथ ही, सीधी भर्ती के लिए ऊपरी उम्र सीमा 34 वर्ष कर दी गई। नए आदेश में कहा गया है कि बेरोजगार युवाओं से कई अभ्यावेदन मिले हैं, जिनमें सीधी भर्ती के लिए ऊपरी उम्र सीमा में छूट देने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है, ताकि अधिक युवा भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकें। मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि सीधी भर्तियों के लिए ऊपरी उम्र सीमा को 10 वर्ष बढ़ाकर यानी 34 वर्ष से 44 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

आपरेशन सिंदूर में दिखी भारत की 'स्मार्ट पावर'

- सेना प्रमुख बोले- अब सुरक्षा बोझ नहीं, समृद्धि की पहली शर्त बन चुकी है
- 22 मिनट की कार्रवाई और 88 घंटे बाद संयमित निर्णय को बताया रणनीतिक बुद्धिमत्ता का उदाहरण
- सेमीकंडक्टर से होर्मुज तक बदलती वैश्विक राजनीति का भी किया जिक्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ढांचे को ध्वस्त नहीं किया, बल्कि वर्षों पुरानी रणनीतिक धारणाओं को भी तोड़ा। इसके बाद भारत ने सोच-समझकर और उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्रवाई रोकी, जो 'स्मार्ट पावर' का सबसे सशक्त उदाहरण है। मानेकशा सेंटर में आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि 6-7 मई, 2025 की रात भारत ने 22 मिनट की सटीक सैन्य कार्रवाई के जरिये दुनिया को स्मार्ट पावर की नई परिभाषा दिखाई। इस अभियान में सैन्य सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक दृढ़ता का समन्वित प्रदर्शन देखने को मिला।

सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय बलों ने आतंकी ढांचे पर गहरी चोट की और लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद 88 घंटे के भीतर बेहद सोच-समझकर लिया गया निर्णय इस बात का प्रमाण था कि भारत जानता है कि कब कौन-सा साधन, कितनी तीव्रता के साथ इस्तेमाल करना है और सैन्य उपलब्धि को रणनीतिक सफलता में कैसे बदलना है।

नई दिल्ली में मंगलवार को मानेकशा सेंटर में आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। प्रेट्र

जनरल द्विवेदी ने कहा कि दुनिया इस समय अव्यवस्था, अविश्वास और बदलते गठबंधनों के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि कभी माना जाता था कि व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाएं और वैश्विक संपर्क देशों को इतना परस्पर निर्भर बना देंगे कि संघर्ष की संभावना कम हो जाएगी, लेकिन अब वही ताकतें दबाव और नियंत्रण के औजार बनती जा रही हैं। सेमीकंडक्टर की सीमित उपलब्धता अब रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही है, जबकि होर्मुज जलडमरूमध्य सक्रिय संघर्ष का क्षेत्र बन चुका है। वैश्विक रक्षा खर्च 2.7 ट्रिलियन डालर से अधिक पहुंच गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के बजट से भी ज्यादा है।

सेना प्रमुख ने कहा कि अब सुरक्षा और समृद्धि के बीच की रेखा लगभग समाप्त हो चुकी है। सुरक्षा अब समृद्धि पर बोझ नहीं, बल्कि विकास यात्रा की पहली शर्त बन चुकी है। 'स्मार्ट' शब्द को एक रणनीतिक ढांचे के रूप में समझाते हुए कहा कि इसमें स्टेटक्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, नवाचार, लचीलापन और तकनीकी श्रेष्ठता जैसे तत्व शामिल हैं।

आने वाले दशक में वही देश वैश्विक संघर्षों की दिशा तय करेगा, जिसके पास तकनीक पर बढ़त होगी। भारत को केवल नई तकनीकों को अपनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें स्वदेशी बनाकर नेतृत्वकारी भूमिका भी निभानी होगी।

रेलवे की व्यवस्था

23 साल बाद बदली पहचान, यार्ड मास्टर कहलाएंगे स्टेशन मास्टर

वर्ष 2003 में ही कर दिया गया पदों का विलय, अब राजपत्रित अधिकारी बनने के खुले द्वार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

रेलवे की व्यवस्था में आखिरकार वो बदलाव लागू हो गया, जिसका इंतजार दो दशक से ज्यादा समय से था। भारतीय रेलवे ने यार्ड मास्टर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर जैसे पुराने पदनाम खत्म कर उन्हें 'स्टेशन मास्टर' कैडर में शामिल कर दिया है। इन पदों का विलय वर्ष 2003 में ही कर दिया गया था, लेकिन फील्ड ड्यूटी और डिजिटल सिस्टम एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) में पुराने नाम अब तक बने हुए थे। इसका असर कर्मचारियों की सुविधाओं व प्रमोशन पर पड़ रहा था। वर्दी भत्ता, पदोन्नति नियम और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अलग-अलग पहचान परेशानी का कारण बनी हुई थी। अब रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद सभी कर्मचारियों की पहचान एक समान होगी और वे स्टेशन मास्टर कैडर में शामिल होकर राजपत्रित अधिकारी बनने का अवसर पा सकेंगे। अब एक ही अधिकारी को जरूरत के अनुसार स्टेशन संचालन, यार्ड प्रबंधन या निरीक्षण ड्यूटी सौंपी जा सकेगी।

प्रतीकात्मक

स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशनों पर परिचालन संभालते हैं। यार्ड मास्टर बड़े जंक्शनों, टर्मिनल स्टेशनों और मालगाड़ी के मार्शलिंग यार्डों में तैनात होते हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर एक सेक्शन के अंदर सुपरवाइजरी पद है। इसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रमोशन पाकर भी सेफ्टी या इंस्पेक्शन शाखा में ही रह जाता था, जबकि यार्ड मास्टर प्रमोशन पाकर चीफ यार्ड मास्टर ही बन पाता है, लेकिन अब पदोन्नति मिलने पर स्टेशन मास्टर से स्टेशन अधीक्षक और फिर सहायक परिचालक प्रबंधक (ग्रुप बी राजपत्रित), मंडल परिचालन प्रबंधक (ग्रुप ए सीनियर स्केल) और वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (ग्रुप ए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव) के पद पर पहुंचा जा सकेगा। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (पे कमीशन व एचआरएमएस) जया कुमार ने इसके लिए 15 मई को आदेश जारी कर दिया है। कैडर विसंगतियां दूर होने से करीब 40 हजार स्टेशन मास्टर का एक एकीकृत कार्यबल होगा। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि एचआरएमएस में अपग्रडेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

रेलवे में 6565 पदों पर होगी टेक्नीशियनों की भर्ती, आवेदन 30 जून से

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने देशभर में टेक्नीशियनों के कुल 6565 पदों पर बंपर भर्ती निकालने का फैसला किया है। इसके तहत टेक्नीशियन ग्रेड-वन (सिग्नल) और टेक्नीशियन ग्रेड-तीन के पदों को भरा जाएगा। आवेदन 30 जून से 29 जुलाई तक आनलाइन किया जा सकेगा। चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती सीधे स्टेशनों, यार्डों में होगी, जहां वे सिग्नल की मरम्मत, बोगियों की जांच और ब्रेक-गियर को दुरुस्त कर ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करेंगे। रेलवे के बड़े कारखानों में तैनात होने वाले कर्मी रेल इंजनों और डिब्बों की समय-समय पर होने वाली बड़ी मरम्मत का काम संभालेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड-तीन के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष तथा ग्रेड-एक (सिग्नल) के लिए 33 वर्ष तय की गई है। शैक्षिक योग्यता के तहत ग्रेड-एक सिग्नल के लिए बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीएससी डिग्री धारक पात्र होंगे। वहीं, ग्रेड-तीन के लिए संबंधित ट्रेड में आइटीआइ के साथ 10वीं पास होना या पीसीएम विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

कह कर रहेंगे | माधव जोशी

107 सीटें जीती है विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु के 2026 के विस चुनाव में। यह पहली बार था कि टीवीके ने विस चुनाव में हिस्सा लिया था।

'कालीघाट' में बगावत की चिंगारी, ममता के आवास पर बैठक में नहीं पहुंचे 15 विधायक

अंदरूनी कलह ▶ ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तीन विधायकों का सीधा हमला

लिखित शिकायत की बंदिश तोड़ फूंका बगावत का बिगुल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

<< मंगलवार को कोलकाता के कालीघाट स्थित टीएमसी प्रमुख और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर बैठक में भाग लेते पार्टी के विधायक। टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने ने बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार समीक्षा बैठक बुलाई है। एएनआइ

बंगाल की सत्ता से हटते ही तृणमूल कांग्रेस के भीतर का अंदरूनी कलह अब खुलकर सतह पर आने लगा है। तृणमूल सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास 'कालीघाट' में हुई विधायक दल की बैठक महज एक औपचारिक समीक्षा बैठक नहीं रही, बल्कि इसने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ पनप रहे गहरे असंतोष को उजागर कर दिया है। बैठक की सबसे बड़ी सुगबुगाहट 15 विधायकों की रहस्यमयी अनुपस्थिति और तीन कद्दावर नेताओं व विधायकों द्वारा सीधे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर उठाए गए सवाल रहे।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, ममता ने पहले ही सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी शिकायत को केवल लिखित रूप में दिया जाए। इसके बावजूद बेलेघाटा के विधायक कुणाल घोष, उलुबेरिया पूर्व के ऋतब्रत बनर्जी और एंटाली के विधायक संदीपन साहा ने एक ही गाड़ी में बैठकर कालीघाट पहुंचकर बगावत की नई स्क्रिप्ट लिख दी।

इन विधायकों ने फलता से तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनाव से दो दिन पहले मैदान छोड़ने को हथियार बनाया। जहांगीर को अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है, इसलिए विधायकों ने सीधे सवाल दागा कि पार्टी विरोधी आचरण के बाद भी उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ऋतब्रत और संदीपन ने जहांगीर को 'केंद्र शासित प्रदेश का नेता' बताते हुए तंज कसा कि इतनी सहूलियतें मिलने के बाद भी वे रणछोड़ क्यों बन गए?

इस विद्रोह की धार तब और तेज हो गई जब कुणाल घोष ने दोटूक कहा कि पार्टी के भीतर 'खुली हवा' यानी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। बंद कमरों में ड्राइंग रूम पालिटिक्स करने के बजाय अब नेताओं को सड़कों पर उतरना होगा। बैठक में अभिषेक की चुनावी घोषणाओं और उनकी हालिया रहस्यमयी चुप्पी पर भी सवाल उठे। वहीं दूसरी ओर, 15 विधायकों का बैठक से नदारद रहना पार्टी के लिए सबसे बड़ा रेड सिग्नल है। सात विधायकों ने बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन मालदा के हरिश्चंद्रपुर के विधायक का इस अहम वक्त पर दिल्ली में होना और कांग्रेस आलाकमान से संपर्क की खबरें तृणमूल की चिंता बढ़ाने के लिए काफी हैं। साथ ही, शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता का दर्जा दिलाने के प्रस्ताव वाले पत्र पर महज 65 विधायकों के हस्ताक्षर होना साफ दिखाता है कि दीदी के कुनबे में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर बंगाल खिलाड़ियों को मिलेगा आठ करोड़

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

▶ बंगाल में खेल मंत्री निशिथ प्रमाणिक का बड़ा एलान, डीएसपी तक नौकरी और हर जिले में खेल महोत्सव

निशिथ प्रमाणिक।

बंगाल की खेल संस्कृति को वैश्विक पटल पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के खेल मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में बंगाल के खिलाड़ियों के लिए इनामों की ऐसी झड़ी लगा दी, जिसने देश के खेल जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खेल मंत्री ने घोषणा की कि अब अगर बंगाल का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) जीतता है, तो उसे पिछली सरकार की तरह महज 25 लाख रुपये नहीं, बल्कि सीधे आठ करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा, ओलंपिक रजत पदक विजेता को छह करोड़ (पहले 15 लाख) और कांस्य पदक विजेता को चार करोड़ रुपये (पहले 10 लाख) देने का प्रस्ताव रखा गया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में खेल मंत्रालय का पूरी तरह कायाकल्प करने की योजना है। इस महा-योजना के तहत सिर्फ ओलंपिक ही नहीं, बल्कि एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेताओं को पांच करोड़, कामनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण विजेताओं को डेढ़ करोड़ और विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेताओं को दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे। साथ ही, नेशनल गेम्स के विजेताओं की इनामी राशि में भी भारी बढ़ोतरी की गई है।

वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करते हुए खेल मंत्री ने एलान किया कि अंतरराष्ट्रीय, ओलंपिक या राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीधे 'डीएसपी' स्तर तक की सरकारी नौकरी दी जाएगी।

बंगाल के सुदूर ग्रामीण अंचलों से छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में 'खेल महोत्सव' का आयोजन किया जाएगा। बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए रवींद्र सरोवर स्टेडियम में ओलंपिक स्तर का ट्रैक बनेगा। खेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि बंगाल अब राष्ट्रीय खेल नीति को पूरी तरह लागू करेगा, ताकि यहां का हर होनहार खिलाड़ी वैश्विक मंच पर तिरंगा लहरा सके।

मेसी दौरे के मुख्य आयोजक ने पूर्व डीजीपी के विरुद्ध भी दर्ज कराई प्राथमिकी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के पिछले साल दिसंबर में भारत दौरे के मुख्य आयोजक रहे शतद्रु दत्ता ने पूर्व खेल मंत्री अरूप बिश्वास के बाद अब राज्य पुलिस के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में शतद्रु ने कहा- 'युवाभारती क्रीड़ांगन में मेसी के कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए मैंने पूर्व डीजीपी से संपर्क किया था। मैं उनकी भूमिका से संतुष्ट नहीं हूं। उनकी गलतियों के कारण ही कार्यक्रम का ऐसा हश्र हुआ। इससे पहले शतद्रु ने पूर्व खेल मंत्री अरूप बिश्वास के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना अनुमति मैदान में प्रवेश कर मेसी को घेर लिया था। उनकी पत्नी जुई को मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने वहां जाकर मेसी के साथ तस्वीर खिंचवाई।

शतद्रु के समर्थन में कई लोग सामने आए हैं। उन्हीं में से एक संजय ने दावा किया कि स्टेडियम में प्रवेश के लिए उनसे अतिरिक्त रुपये वसूले गए थे। संजय ने बताया कि पहले उनसे अधिक रकम मांगी गई थी। बाद में इसे थोड़ा घटाकर 10 हजार रुपये किए गए थे, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुए। जब वह जाने लगे तो उन्हें बुलाकर कहा गया कि पांच हजार रुपये से कम में प्रवेश नहीं मिलेगा। अंततः उन्होंने पांच हजार रुपये देकर टिकट खरीदा।

नेहरू ने 1961 में असम को टुकड़ों में बांटने की साजिश रची थी: निशिकांत

नई दिल्ली, एएनआइ : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 1961 में पूर्वोत्तर राज्य असम को टुकड़ों में बांटने, बांग्लादेशी मुस्लिमों को बसाने और स्थानीय असमिया लोगों के बीच दूरी पैदा करने की साजिश रची थी।

'एक्स' पर निशिकांत ने 19 मई, 1961 को 'कांग्रेस का काला अध्याय' बताते हुए कहा कि 1960 के दशक में भाषा के नाम पर असम में भारी हिंसा भड़की थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने असमिया भाषा को शिक्षा और नौकरियों में अनिवार्य बनाने का कानून पास किया था। इसके खिलाफ विरोध कर रहे बंगाली भाषी समुदाय पर 19 मई, 1961 को बराक घाटी (सिलचर) में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गोलीबारी की, जिसमें 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और हजारों घायल हुए। वहां के प्रबुद्ध लोग लगातार नेहरू जी से मिलते रहे, लेकिन सिलचर गोलीबारी की घटना होने तक नेहरू जी अपने रुख पर अडिग रहे।

अन्नाद्रमुक में गहराया संकट, दोनों गुट अपने रुख पर अड़े

▶ पलानीस्वामी ने खारिज की आम परिषद की बैठक बुलाने की मांग

ईके पलानीस्वामी। फाइल

चेन्नई, प्रेट्र: अन्नाद्रमुक में संकट गहराता जा रहा है। पार्टी महासचिव ईके पलानीस्वामी व बागी गुट दोनों अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं। पलानीस्वामी ने बागी गुट की आम परिषद की बैठक बुलाने की मांग खारिज कर दी है, जबकि उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाला यह गुट भी झुकने को तैयार नहीं है। इस गुट ने टीवीके सरकार को समर्थन दिया है। पार्टी की आम परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है।

पलानीस्वामी ने मंगलवार को पार्टी के पदाधिकारियों और जिला सचिवों के साथ एक अहम बैठक की। यह बैठक ऐसे समय की गई, जब पार्टी में फूट पड़ गई है। उन्होंने बागी गुट की आम परिषद की बैठक बुलाने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। जबकि बागी गुट ने भी पलानीस्वामी की उस अपील पर सकारात्मक जवाब नहीं दिया, जिसमें उन्होंने साथ मिलकर काम करने की बात कही है। पूर्व मंत्री बीवी रामना ने पत्रकारों से कहा कि पलानीस्वामी की अध्यक्षता में यह बैठक करीब दो घंटे चली, जिसमें करीब 80 जिला सचिवों ने हिस्सा लिया। सभी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पलानीस्वामी के साथ मजबूती से खड़े हैं और पार्टी आने वाले दिनों में विजेता के रूप में उभरने के लिए एक रणनीति तैयार करेगी। जबकि एक अन्य वरिष्ठ नेता वीवी राजन चेलेप्पा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हम अपने महासचिव के हाथों को मजबूत करने के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग देने के लिए दृढ़ रहेंगे।

2027 की तैयारी में आए राहुल गांधी के तरकश से निकले पुराने तीर

जागरण संवाददाता, रायबरेली

4 महीने बाद संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष

▶ फिर केंद्र सरकार पर दो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप दोहराया

रायबरेली में ग्राम विकास संवाद कार्यक्रम में सांसद किशोरी लाल शर्मा के साथ राहुल गांधी। एएनआइ

नेता प्रतिपक्ष व स्थानीय सांसद राहुल गांधी मंगलवार को चार महीने बाद जब अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, तो सियासी गलियारों में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सुगबुगाहट तेज थी।

कांग्रेस ने भी उनके आगमन के पहले ही दिन तीन बड़ी जनसभाओं का आयोजन कर माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन मंचों से राहुल के संबोधन में कुछ भी नया नहीं रहा। वह अपने पुराने अंदाज में ही दिखे और उनके तरकश से वही पुराने तीर निकले, जो वह लंबे समय से अन्य मंचों से चलाते आ रहे हैं।

तीनों जनसभाओं में उनका पूरा जोर केंद्र पर हमला बोलने पर रहा, लेकिन भाषण की पूरी स्क्रिप्ट पुराने ढर्रे पर ही टिकी दिखी। उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर दो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप दोहराया।

राहुल ने वैश्विक परिदृश्य और डीजल-पेट्रोल की स्थिति का हवाला देकर देश पर इसका गहरा असर पड़ने का दावा तो किया, लेकिन रायबरेली की जनता के सामने कोई नया विजन रखने के बजाय भाषण को गांधी परिवार के अटूट रिश्ते और भावुकता के इर्द-गिर्द ही समेटे रखा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने राहुल के आगमन पर तंज कसते हुए कहा कि वह यहां भ्रमण के बाद यूरोप में पिकनिक मनाने चले जाएंगे।

राहुल अर्थव्यवस्था पर गलत जानकारी फैलाकर भ्रम पैदा कर रहे: भाजपा

नई दिल्ली, प्रेट्र: भाजपा ने मंगलवार को राहुल गांधी पर देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर गलत सूचना फैलाकर भ्रम और अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया और कांग्रेस नेता से पूछा कि क्या वह किसी भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमें स्पष्ट और सटीक जवाब चाहिए। इस रणनीति के पीछे किसका हाथ है?

इससे पहले रायबरेली में राहुल ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ते एक भीषण आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, जिसका सामना "हमने पहले कभी नहीं किया"। लोगों से विदेश यात्रा न करने की अपील के तुरंत बाद मोदी के पांच देशों के दौरे पर रवाना होने की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अडानी-अंबानी द्वारा निर्मित आर्थिक ढांचा इस तूफान में ढह जाएगा, लेकिन उद्योगपति अपने महलों में आराम से रहेंगे जबकि आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी अब आर्थिक क्षेत्र में अराजकता पैदा करने के लिए भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं।

राष्ट्रीय फलक

रांची के जेल अधीक्षक पर महिला कैदी के यौन शोषण का आरोप, भाजपा ने की जांच की मांग

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

▶ विधिक सेवा प्राधिकार की टीम ने जेल जाकर पीड़िता और आरोपितों के लिए बयान

झारखंड की सबसे सुरक्षित जेलों में गिने जाने वाली बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा इन दिनों गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है। भाजपा नेताओं ने जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर पर जेल में बंद एक महिला कैदी का यौन शोषण करने और जबरन गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। मरांडी ने जेल आइजी पर भी मामले को दबाने और सुबूत मिटाने के आरोप लगाए हैं। चेतावनी दी है कि भाजपा मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष भी उठाएगी।

जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि वह हर जांच के लिए तैयार हैं। वहीं, जेल के चिकित्सक डा. विनीत राज ने भी कहा कि महिला गर्भवती नहीं है, बल्कि उसे गर्भाशय में ट्यूमर है। इसी कारण उसे जांच को रांची सदर अस्पताल ले जाया गया था।

मामले पर राज्य की राजनीति भी गर्म हो गई है। भाजपा नेता जहां जांच और कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने जांच तक धैर्य बनाए रखने को कहा है। मंगलवार को यह मामला राज्यपाल संतोष गंगवार तक भी पहुंचा।

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात कर इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। राज्यपाल ने कहा कि महिला सुरक्षा एवं मानवाधिकार से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं हो सकती। कहा कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

इससे पहले सोमवार को मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के न्यायिक सदस्यों की एक टीम ने जेल जाकर महिला बंदी के यौन शोषण के आरोपों की जांच की। झालसा की सचिव रंजना अस्थाना ने कहा कि टीम को प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत हुए हैं। जांच टीम ने पीड़िता से घटना के संबंध में पूछताछ की।

'भारत-नेपाल सीमा पर बेहतर निगरानी को ले हो नई तकनीक का इस्तेमाल'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन पर उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा पर बेहतर निगरानी के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। सीमा पर होने वाले अनैतिक और गैर वैधानिक कार्यों पर पूरी सख्ती बरतें। मुख्यमंत्री की बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि 26-27 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी। आज की उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा से जुड़े फैसलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए जीवनरेखा है यह कारिडोर

प्रथम पृष्ठ से आगे

यह कारिडोर पूर्वोत्तर के आठों राज्यों के लिए देश की जीवनरेखा माना जाता है। सड़क, रेल, सैन्य आपूर्ति, व्यापारिक गतिविधियों और रसद संचालन के लिए यही मुख्य संपर्क मार्ग है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भूमि उपलब्धता को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाता है। हालांकि केंद्र या राज्य सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस जमीन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि यहां रक्षा ढांचा, लाजिस्टिक्स हब, सुरक्षा प्रतिष्ठान, कनेक्टिविटी विस्तार या अन्य रणनीतिक परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के बाद राज्य सरकार केंद्र के साथ रणनीतिक समन्वय को तेज कर रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, 'चिकन नेक' क्षेत्र में जमीन हस्तांतरण से भारत की सामरिक क्षमता और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इलाके में सैन्य ढांचा और लाजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित होने से सीमावर्ती इलाकों में सेना की त्वरित तैनाती और आपूर्ति व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सकेगी। चीन और बांग्लादेश से जुड़े भू-राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इस कारिडोर की सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस दिशा में बढ़ता सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

अंबुमणि रामदास ने सेंथिल बालाजी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मांगी अनुमति

चेन्नई, प्रेट्र: पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से मांग की कि द्रमुक नेता और पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में कानूनी कार्रवाई की अनुमति दी जाए।

अंबुमणि रामदास ने कहा कि ईडी ने राज्य सरकार से उस मामले में जांच आगे बढ़ाने की मंजूरी मांगी है, जिसमें आरोप है कि राज्य परिवहन निगमों में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से करोड़ों रुपये की अवैध वसूली की गई।

रामदास ने कहा कि चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने सेंथिल बालाजी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

आरोप है कि परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने हजारों लोगों को ड्राइवर, कंडक्टर, इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारियों की नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी की।

योगी की टिप्पणी पर रिजीजू ने कहा, किसी को तनाव पैदा नहीं करना चाहिए

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने सड़कों पर नमाज पढ़ने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई टिप्पणी पर मंगलवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति या नेता को तनाव पैदा नहीं करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए सभी को कानून का पालन करना होगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा बुलाए गए राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के एक सम्मेलन के बाद रिजीजू ने संवाददाताओं से कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'मेरा कहना है कि कोई भी हो, चाहे राजनेता हों या सामाजिक कार्यकर्ता, हमें तनाव पैदा नहीं करना है। हर भारतीय को एक-दूसरे के साथ सद्भाव से रहना होगा।' मंत्री ने कहा कि हम सभी को

किरेन रिजीजू। फाइल

एक साथ रहना है। लेकिन सभी को कानून का पालन करना होगा।

बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर चेतावनी देते हुए सोमवार को कहा था कि धार्मिक स्थलों पर अलग-अलग पालियों में धर्म से संबंधित गतिविधियां की जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार सड़क जाम करके नमाज की अनुमति नहीं देगी।

ईडी का दावा-सस्ती दर पर जमीन खरीदने के लिए विश्वजीत पोद्दार दिखाता था डर

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

▶ ईडी ने अदालत में किया दावा, कारोबारी और पूर्व डीएसपी के लिए काम करने का आरोप

विश्वजीत पोद्दार। एएनआइ

ईडी ने मंगलवार को अदालत में दावा किया कि कोलकाता कसबा के कारोबारी व अपराधी विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू जमीन सिंडिकेट के प्रमुख चेहरों में से एक था और लोगों को डराकर कम कीमत पर उनकी जमीन और संपत्ति खरीदता था। सोमवार रात करीब नौ घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सोना पप्पू को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया गया। ईडी के वकील ने अदालत में कहा कि सोना पप्पू अकेले काम नहीं करता था, बल्कि यह तीन लोगों का संगठित गिरोह था। जांच एजेंसी के अनुसार, कोलकाता के कारोबारी जय और कोलकाता पुलिस के पूर्व डीसी शांतनु सिन्हा विश्वास के लिए सोना काम करता था और जमीन सिंडिकेट के अहम काम संभालता था।

ईडी ने अदालत में आरोप लगाया कि सोना पप्पू के खिलाफ वसूली, धमकी, जमीन कब्जा और अवैध हथियार रखने जैसे कई मामले हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, उसके घर पर छापेमारी के दौरान एक रिवाल्वर बरामद हुई थी, जिसे जय की कंपनी के नाम पर खरीदा गया था। यह भी दावा किया कि रिवाल्वर खरीदे जाने के बाद कांकुलिया इलाके में अशांति की घटना हुई थी। हालांकि सोना पप्पू के वकील ने अदालत में कहा कि हथियार खरीदने के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।

जांच एजेंसी ने अदालत में कई जमीन सौदों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर संपत्तियां खरीदी गईं। ईडी के अनुसार, 2024 में 7.7 करोड़ रुपये मूल्य की एक जमीन सिर्फ एक करोड़ रुपये में खरीदी गई। इसी तरह 2022 में जिस जमीन की बाजार कीमत 5 करोड़ 42 लाख रुपये थी, उसे एक करोड़ 39 लाख रुपये में खरीदा गया। सोना पप्पू के वकील ने सवाल उठाया कि यदि जमीन जबरन कम कीमत पर खरीदी गई होती तो उसके मालिक शिकायत क्यों नहीं करते।

बीएचयू में 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' पर पूछे गए सवाल, कुलसचिव से मांगी गई सफाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी

▶ एमए इतिहास के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का प्रश्न इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद उठा विवाद

बीएचयू एक बार फिर वैचारिक बहस के केंद्र में है। इस बार विवाद सामाजिक विज्ञान संकाय के इतिहास विभाग द्वारा आयोजित एमए इतिहास चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को लेकर खड़ा हुआ है। प्रश्न पत्र में पूछा गया था-'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता शब्द से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए कि किस प्रकार ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में बाधा डाली?'

पीएमओ ने मामले का संज्ञान लेते हुए बीएचयू के कुलसचिव से जवाब मांगा कि यह सवाल क्यों पूछा गया। कुलसचिव ने बताया कि क्योंकि यह विषय सिलेबस में था, इसलिए सवाल पूछा गया था।

परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्नपत्र का स्क्रीनशाट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया, जिसके बाद इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। ब्राह्मण समाज और कई छात्र संगठनों ने आपत्ति जताते हुए इसे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने और समाज को विभाजित करने की कोशिश बताया।

हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डा. श्रीप्रकाश शुक्ल ने कहा कि परीक्षा में इस तरह के संवेदनशील और जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग छात्रों के बीच एक वर्ग विशेष के प्रति नकारात्मक धारणा बना सकता है। उनके अनुसार आधुनिक वैचारिक और पश्चिमी अवधारणाओं को प्राचीन भारतीय इतिहास पर सीधे लागू करना उचित नहीं है। उन्होंने इसे परीक्षा प्रणाली में वैचारिक एजेंडे की घुसपैठ बताया।

25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है राज्य सूचना आयुक्त ने कौशांबी के डीएम। यह कार्रवाई आरटीआइ के तहत मांगी गई सूचना न देने पर की गई है। जुर्माने अदा नहीं होने तक उनके वेतन भुगतान पर रोक है।

पेट्रोल-डीजल के दाम 90 पैसे प्रति लीटर बढ़े, सप्ताह में दूसरी बार कीमतों में वृद्धि

महंगा ईंधन ▶ दिल्ली में अब पेट्रोल 98 .64 रुपये और डीजल 91 .58 रुपये प्रति लीटर

शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दाम तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए थे

महंगा हुआ पेट्रोलियम ईंधन। प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की और बढ़ोतरी की गई। एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 97.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत अब 90.67 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले, शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दाम तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए थे।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पश्चिम एशिया संकट के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण बढ़ते नुकसान को कम करने के लिए यह कदम उठाए हैं। तेल की वैश्विक आवाजाही के लिए अहम मार्ग होर्मुज स्ट्रेट के बाधित होने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। सरकार का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद ईंधन खुदरा विक्रेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था।

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सोमवार को कहा था कि 15 मई को हुई बढ़ोतरी से नुकसान में लगभग एक चौथाई की कमी आई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां अब भी प्रतिदिन लगभग 750 करोड़ रुपये का नुकसान झेल रही हैं। क्रिसिल के अनुसार, तेल कंपनियों को 15 मई को हुई मूल्य वृद्धि के बाद भी पेट्रोल पर लगभग 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। विभिन्न राज्यों में वैट में अंतर के कारण भी ईंधन की कीमतों में अंतर होता है।

पेट्रोल-डीजल कीमतों में चार दिन में दूसरी बढ़ोतरी आम जनता पर बोझ : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मल्लिकार्जुनखरगे

खरगे बोले- आम से लूट और अमेरिका से अदाणी को छूट, यह है मोदी का समझौतावादी माडल

कांग्रेस ने चार दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में दूसरी बार की गई बढ़ोतरी को लेकर तीखा हमला करते हुए ईंधन कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार से एक स्पष्ट कार्य योजना लाने की मांग की है। साथ ही देश की ऊर्जा संप्रभुता को सुरक्षित रखने की जरूरत भी बताई।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। ऐसे में सभी को साथ लेकर संकट का समाधान खोजना चाहिए। खरगे ने कहा कि आम जनता से लूट और अदाणी को अमेरिका से छूट- ये है मोदी का समझौतावादी माडल। विश्वगुरु का झूठा दंभ भरने वाले मोदी ने अमेरिका से हाथ-पैर जोड़कर रूसी तेल खरीदने के लिए एक महीने के विस्तार की अनुमति ली है। हर बार ऐसा करके वो 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं।

खरगे ने कहा कि अब सवाल यह है कि जब सरकार के हिसाब से हमें ये अनुमति मिल गई तो फिर आम जनता पर पेट्रोल-डीजल के दामों का बोझ क्यों? संकट से निपटने के लिए खुद क्या कर रहें हैं इसका पीएम से जवाब मांगते हुए कहा कि वह तभी जनता के असली प्रधान सेवक कहलाएंगे, वरना महज प्रचारक बनकर ही रह जाएंगे।

भाजपा के झंडे और हूटर लगे ई-रिक्शा से बैठक में पहुंचे विधायक

मथुरा : कलक्ट्रेट में सोमवार को विधायक पूरन प्रकाश अपनी कार छोड़कर ई-रिक्शा से पहुंचे। सांसद हेमा मालिनी को भी उन्होंने कुछ दूरी तक ई-रिक्शा में बैठाया। जागरण

जागरण संवाददाता, मथुरा

▶ **इलेक्ट्रिक कार से पहुंची थीं सांसद हेमा मालिनी, लौटते में बैठीं ई-रिक्शा में**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन कम खर्च करने की अपील के असर में भाजपा विधायक का अंदाज चर्चाओं में आ गया। सोमवार को कलक्ट्रेट में आयोजित एक बैठक में भाजपा का झंडा और हूटर लगे ई-रिक्शा से बलदेव विधायक पूरन प्रकाश पहुंचे। ई-रिक्शा में विधायक की फोटो लगे पोस्टर भी चस्पा थे। बैठक के लिए इलेक्ट्रिक कार से पहुंची सांसद हेमा मालिनी लौटते में ई-रिक्शा में कुछ दूरी तक के लिए बैठीं।

ई-रिक्शा के आगे वाले शीशे पर विधायक लिखा था। बैठक के बाद जब सांसद चलने लगीं तो विधायक ने उन्हें ई-रिक्शा में बैठने का आग्रह किया। सांसद के बैठने पर हूटर बजाते हुए ई-रिक्शा चल पड़ा। 50 मीटर चलने के बाद हेमा मालिनी रिक्शा से उतरकर अपनी कार से चली गईं।

हूटर लगाना यातायात नियमों का उल्लंघन : मोटर वाहन अधिनियम के तहत निजी वाहनों पर हूटर लगाना नियमों का उल्लंघन है। एआरटीओ प्रवर्तन सत्येंद्र सिंह का कहना है कि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों में ही हूटर लगाए जा सकते हैं। इसमें जुर्माने का प्रविधान है। विधायक का कहना है कि हम अपनी गाड़ी में भी हूटर लगाते हैं। इसलिए ई-रिक्शा पर लगाया।

लंबे समय से कार्यरत अस्थायी कर्मियों को आउटसोर्सिंग पर रखना गलत : हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के उस आदेश को रद कर दिया है, जिसमें लंबे समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले कर दिया गया था। कहा कि लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को आउटसोर्सिंग पर रखना अनुचित है। यह मामला आयकर विभाग से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि याचियों की अस्थायी कर्मचारी के रूप में सेवाएं समाप्त करना, जबकि उनसे आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से वही कार्य लिया जा रहा है और समान प्रकृति के कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है, यह मनमाना एवं भेदभावपूर्ण है। ऐसा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

याची लतेल प्रसाद यादव, राजबीर दास सहित अन्य ने बताया कि आयकर विभाग में उनकी नियुक्ति अलग-अलग तिथियों पर हुई थी। उन्होंने 10 से 15 वर्षों तक संतोषजनक सेवाएं दीं। सेवा अवधि के दौरान विभागीय अधिकारियों ने उनके नियमितीकरण की सिफारिश की थी, लेकिन आयकर विभाग ने 2011 में नीति में बदलाव कर कई सेवाओं को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया। कोर्ट कहा कि याचियों के नियमितीकरण के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारी नियमितीकरण के लाभ के अधिकारी हैं।

रेलवे ने बांद्रा स्टेशन के पास लगभग 18 प्रतिशत अवैध झोपड़ियों को हटाया

<< मुंबई में मंगलवार को बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान तैनात पुलिसबल और कर्मचारी। प्रेट्र

मुंबई, प्रेट्र : पश्चिमी रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के लिए मंगलवार को अभियान शुरू किया। बांबे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद शुरू किए गए इस अभियान के दौरान बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास बनी 500 अवैध झोपड़ियों में से लगभग 18 प्रतिशत झोपड़ियों को हटा दिया गया।

पांच दिवसीय अभियान का उद्देश्य 5,300 वर्ग मीटर रेलवे भूमि को खाली कराना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अभियान 23 मई तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे ने मुंबई के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से बांद्रा टर्मिनस पर एलिवेटेड रोड, बहुमंजिला इमारतों, प्लेटफार्मों और रखरखाव सुविधाओं से युक्त एक एकीकृत परिसर की योजना बनाई है। अधिकारी ने कहा, गरीब नगर में रेलवे की जमीन पर बनी 500 झोपड़ियों में से, अतिक्रमण विरोधी अभियान के पहले दिन हमने लगभग 15 से 18% झोपड़ियों को खाली करा लिया है। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को नागरिक प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है।

चंद्रकांत रथ हत्याकांड में पांचवां आरोपित विनय राय वाराणसी में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी

▶ **सीबीआइ कोलकाता ले गई, शूटरों को संसाधन उपलब्ध कराने का आरोप**

▶ **विनय से पूछताछ में मुनमुन नाम के एक और शूटर का नाम आया सामने**

चंद्रनाथ रथ हत्याकांडमें वाराणसी से गिरफ्तार आरोपित विनय राय। स्रोत- इंटरनेट मीडिया

शुभेंदु अधिकारी (अब बंगाल के मुख्यमंत्री) के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआइ टीम ने पांचवें आरोपित गाजीपुर निवासी विनय राय को मंगलवार शाम चार बजे वाराणसी पुलिस लाइन के पास से गिरफ्तार किया। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कोयला कारोबारी विनय राय पर हत्या में शामिल शूटरों को धनबाद में संसाधन उपलब्ध कराने का आरोप है। सीबीआइ टीम उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले गई। उसे 21 मई को कोलकाता की अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में बलिया के राज सिंह, राजकुमार सिंह तथा बक्सर के मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीबीआइ और बंगाल एसटीएफ की टीम अब विनय के गुर्गे गाजीपुर निवासी संजय राय की तलाश में दबिश दे रही है।

चंद्रनाथ रथ की छह मई की रात उत्तर 24 परगना में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआइ ने सोमवार को बलिया के राजकुमार सिंह को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया था। राजकुमार को शूटर बताया जा रहा है। विनय राय के खिलाफ पहले से हत्या, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक विनय से पूछताछ में मुनमुन नाम के एक अन्य शूटर का नाम भी सामने आया है।

राजकुमार सिंह के फोन से मिला विनय राय का सुराग: विनय राय का बलिया अक्सर आना-जाना होता था। सूत्रों के मुताबिक उसका राजकुमार सिंह से भी संबंध था। राजकुमार से मिली सूचना के आधार पर सीबीआइ ने उसे वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार सिंह के मोबाइल फोन से मिले सुराग व पूछताछ में विनय राय की इस हत्याकांड में संलिप्तता का पता चला। सीबीआइ मुख्य शूटर के रूप में राजकुमार सिंह को प्रस्तुत कर रही है।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने हथियारों की व्यवस्था और भागने का रूट मिलकर तय किया था। दोनों का पूर्वांचल में गाजीपुर-बलिया के साथ बिहार के बक्सर में मजबूत नेटवर्क है।

परमाणु दुर्घटना पर क्षतिपूर्ति का निर्धारण बेहद संवेदनशील

3 **हजार करोड़ के मुआवजे पर सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी**

▶ **कहा, क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी से सरकार को भी जुड़ना पड़ सकता है**

नई दिल्ली, प्रेट्र : परमाणु संयंत्र में होने वाली किसी दुर्घटना पर अधिकतम तीन हजार करोड़ रुपये का मुआवजा देने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संवेदनशील विधायी नीति से जुड़ा मसला बताया है। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अधिकतम तीन हजार करोड़ रुपये देने के 2025 में बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने याचिका के अध्ययन में पाया कि उसमें सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट आफ न्यूक्लियर एनर्जी फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया (शांति) एक्ट, 2025 के कई प्रविधानों को चुनौती दी गई है। इस कानून को आर्थिक नीति से जुड़ा मसला बताया गया है।

कोर्ट ने कहा, किसी भी दुर्घटना की स्थिति में किसी व्यक्ति को होने वाली नुकसान की क्षतिपूर्ति का हमें आकलन करना है। याचिकाकर्ता की ओर पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, कुल आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के मामले से जुड़े तीन बिंदुओं को लेकर हमें स्पष्टीकरण चाहिए।

अधिवक्ता ने कहा, अगर देश में परमाणु दुर्घटना होती है और नुकसान तीन हजार करोड़ रुपये से सैकड़ों गुना ज्यादा का होता है तो उस स्थिति में क्या होगा? सरकार नीति बनाकर खतरे के अनुसार मुआवजे और क्षतिपूर्ति के तरीकों को निर्धारित कर सकती है। लेकिन नागरिकों के अधिकारों की बलि नहीं चढ़ा सकती है। अमेरिका में परमाणु दुर्घटना की स्थिति में 1.54 लाख करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का प्रविधान है जो भारत की निर्धारित धनराशि से 50 गुना से भी ज्यादा है। इसी के बाद पीठ ने कहा कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है। कोर्ट ने कहा, बड़ी दुर्घटना की स्थिति में सरकार को क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है।

जहां जाता परिवार वहां लग जाती है रहस्यमयी आग, 20 दिन में आगजनी की 50 घटनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर

▶ **मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले का मामला, तीन बार बदल चुका है परिवार अपना ठिकाना**

▶ **घर का सामान जल जाता है, बच्चों के कपड़ों में भी लग चुकी है आग, पूरा गांव सहमा**

अशोकनगर : आग लगने से सामान जलकर नष्ट हो गया। -नईदुनिया

मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले के एक गांव में पिछले 15-20 दिनों से एक परिवार के साथ हो रही रहस्यमयी आगजनी की घटनाओं से हर कोई हैरत में है। परिवार के मुखिया राजेश राजपूत का दावा है कि वे लोग जहां भी जा रहे हैं, वहां आग लगने की घटनाएं होने लगती हैं। इस परिवार के तीन अलग-अलग घरों में पिछले 20 दिनों में 50 से अधिक बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं।

राजेश राजपूत के मूल घर से शुरू हुई इन घटनाओं को क्रम तब भी जारी रहा, जब वह परिवार के साथ वह दूसरे घर में रहने पहुंच गए। वहां भी उनके सामान में आग लगने लगी तो परिवार धर्मशाला में रहने लगा, लेकिन ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का क्रम यहां भी नहीं थमा है। पीड़ित परिवार के अनुसार, घर में रखे कपड़े, अनाज, बर्तन, बच्चों के खिलौने और किताबों में अचानक आग लग जाती है। कई बार ऐसी जगहों पर भी आग भड़क उठी, जहां बिजली या शार्ट-सर्किट की कोई आशंका नहीं होती। आग लगने से पहले अजीब बदबू और धुआं महसूस होता है।

खेलते समय बच्चों के कपड़ों में लगी आग : पिछले दिनों इस परिवार का तीन साल का मासूम बालक और किशोरियां जब खेल रही थी तो उनके कपड़ो में भी आग लग गई। इस घटना के बाद परिवार ने घर छोड़ दिया, लेकिन परेशानी फिर भी खत्म नहीं हुई। पहले दूसरे मकान और बाद में गांव के बाहर धर्मशाला में शिफ्ट किए जाने पर भी आग लगने की घटनाओं का सिलसिला जारी रहा।

विशेषज्ञों की टीम करेगी जांच: इस परिवार से मुलाकात में पूरी जानकारी जुटाने और प्रारंभिक जांच के बाद मुंगावली के एसडीएम इसरार खान और थाना प्रभारी अरविंद कछुवाहा ने माना कि मामला असामान्य और रहस्य का विषय है। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बुलाकर मामले की जांच करा रहे हैं।

50 लाख की रिश्वतखोरी के मामले में सेना का कर्नल गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र: सीबीआइ ने सेना के एक कर्नल को 50 लाख रुपये के रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार किया है। यह अधिकारी कोलकाता में सेना के पूर्वी कमान में आर्मी आर्डनेंस कार्प्स के तहत तैनात थे। अधिकारी पर कानपुर स्थित एक कंपनी को निविदाओं के आवंटन में हेरफेर करने, घटिया नमूनों को मंजूरी देने और लंबित एवं बढ़ाए गए बिलों के निपटान में सहायता प्रदान करके लाभ पहुंचाने का आरोप है।

सीबीआइ ने एफआइआर में कहा कि कर्नल ने रिश्वत की बकाया राशि के संबंध में उद्योगपति से संपर्क किया था, जिस पर व्यवसायी ने पैसा न होने की बात कही थी। अधिकारी ने बाद में उद्योगपति के ड्राइवर को फोन किया और उसे अपने एक परिचित को भुगतान पहुंचाने के लिए कहा। आरोप है कि 50 लाख रुपये की बकाया रिश्वत हवाला चैनलों के माध्यम से भेजी जानी थी। सीबीआइ ने बताया कि कथित रिश्वतखोरी मामले में कर्नल और निजी ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन, आज हरिद्वार में होगी अंत्येष्टि

जागरण संवाददाता, देहरादून

भुवनचंद्रखंडूड़ी।

चला गया सरहद और सियासत का सच्चा सिपाही, प्रदेश में तीन दिन का राजकीय शोक

उत्तराखंड की राजनीति के सबसे सख्त, ईमानदार और अनुशासित चेहरों में शामिल रहे पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (सेनि) का निधन हो गया है। 92 वर्षीय खंडूड़ी ने मंगलवार को अंतिम सांस ली। उनकी अंत्येष्टि आज हरिद्वार में होगी। सेना में बड़ी जिम्मेदारी से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक का उनका सफर मिसाल माना जाता है। उनके निधन पर राज्य सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। राज्य सरकार ने बुधवार को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं और सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टि. जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदि ने उनके निधन पर शोक जताया है।

खंडूड़ी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। उनके पार्थिव शरीर को दोपहर करीब सवा एक बजे सेना की एंबुलेंस से सैन्य अस्पताल गढ़ी कैंट ले जाया गया। वहां से सैन्य सम्मान के साथ तिरंगे में उनके वसंत विहार स्थित आवास लाया गया। वहां उनकी बेटी ऋतु भूषण खंडूड़ी, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों, समेत भाजपा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। खंडूड़ी के पार्थिव शरीर को बुधवार सुबह 10 बजे बसंत विहार स्थित उनके निजी आवास से भाजपा प्रदेश कार्यालय लाया जाएगा, जहां 10:30 बजे अंतिम दर्शन के बाद 11 बजे हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया जाएगा।

राजनीति में आने से पहले सेना में दी सेवा : एक अक्टूबर 1934 को देहरादून में जन्मे भुवन चंद्र खंडूड़ी ने राजनीति में आने से पहले भारतीय सेना में लंबी सेवा दी। वह इंजीनियरिंग कोर में अधिकारी रहे। वर्ष 1954 में वह भारतीय सेना में सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती होकर वर्ष 1991 में मेजर जनरल के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध, 1965 और 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध में भी हिस्सा लिया। 1983 में उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला। खंडूड़ी पहली बार 1991 में गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वह पांच बार गढ़वाल के सांसद चुने गए। वह 2007-09 और 2011-12 में दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।

हरियाणा का हाल

लिंगानुपात सुधारने में विफल रहने पर चार अधिकारी निलंबित

आठ अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर मांगा जवाब, लिंगानुपात में सुधार के लिए क्रियान्वित अभियान की प्रभावी निगरानी नहीं करने का आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

प्रतीकात्मक

एक हजार लड़कों के सापेक्ष किस जिले में कितनी लड़कियां

जिला	लड़कियां
चरखी दादरी	769
अंबाला	843
महेंद्रगढ़	847
गुरुग्राम	863
जींद	872

लिंग अनुपात 950 तक ले जाने का लक्ष्य

हरियाणा सरकार का लक्ष्य राज्य में लिंग अनुपात एक हजार लड़कों के सापेक्ष 950 लड़कियों तक ले जाने का है। पिछले साल 923 तक लिंग अनुपात पहुंच चुका था, लेकिन पिछले कुछ माह से लिंग अनुपात में गिरावट आ रही है।

हर सप्ताह लिंग अनुपात की स्थिति की समीक्षा

स्वास्थ्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा इस माह दो बैठकों का आयोजन कर चुकी हैं। वह हर सप्ताह राज्य में लिंग अनुपात की स्थिति की समीक्षा कर रही हैं। बार-बार की चेतावनी के बावजूद अधिकारियों ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया है। जिन जिलों में इन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, वहां लिंग अनुपात की स्थिति संतोषजनक नहीं है। करीब एक दर्जन अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार की चेतावनी दी गई है।

हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के लिए संचालित अभियान की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य सरकार ने चार वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने आठ स्वास्थ्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लिंग अनुपात में कमी का संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में इन आठ अधिकारियों पर भी निलंबन की गाज गिर सकती है।

गौरतलब है कि वर्ष 2026 के पहले चार महीनों में राज्य का लिंग अनुपात घटकर 895 रह गया है, जो पिछले साल इसी अवधि के 925 के मुकाबले काफी कम है। इस गिरावट ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में सबसे खराब स्थिति चरखी दादरी की रही, जहां प्रति एक हजार लड़कों पर केवल 769 लड़कियां दर्ज की गईं।

स्वास्थ्य विभाग के जिन चार अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें सोनीपत के पुरखास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में तैनात सीनियर मेडिकल आफिसर (एसएमओ) डा. टीना आनंद, यमुनानगर के रादौर सीएचसी में कार्यरत एसएमओ डा. विजय परमार, रोहतक के छीरी सीएचसी में तैनात एसएमओ डा. सतपाल और नारनौल के सेहलंग सीएचसी में नियुक्त मेडिकल आफिसर (एमओ) डा. प्रभा शामिल हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने कहा कि जिन अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में लिंग अनुपात गिरा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

शुभेंदु का 'शून्य चैलेंज'

प्रथम पृष्ठ से आगे

पूर्व नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से गत 29 अप्रैल को अंतिम चरण के मतदान के दौरान फलता में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और धांधली की शिकायत की थी। आयोग ने पुनर्मतदान का फैसला किया था। इस बीच चार मई को आए चुनावी नतीजों में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। मंगलवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फलता में रोड शो करते हुए हुंकार भरी थी कि 'भाइपो (भतीजे) के पुष्पा' ने लंबे समय तक जनता को वोट नहीं देने दिया, अब जनता इन्हें 'शून्य' पर समेटकर इसका जवाब देगी। शुभेंदु की इस राजनीतिक घेराबंदी और कड़ी कानूनी कार्रवाई के खौफ के आगे जहांगीर टिक नहीं सके और घर पर प्रेस कान्फ्रेंस कर मैदान छोड़ दिया।

अजयपाल शर्मा से टकराव और 'पुष्पा' की सनक : विधानसभा चुनाव के दौरान डायमंड हार्बर के पुलिस पर्यवेक्षक बनाए गए यूपी के आइपीएस अजयपाल शर्मा (जिन्हें 'सिंघम' कहा जाता है) को खुलेआम चुनौती देकर जहांगीर ने खुद को बंगाल की राजनीति का 'पुष्पा' घोषित किया था। दावा किया था कि वह किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, लेकिन सत्ता बदलते ही जहांगीर की वह ठसक हवा हो गई। सोमवार को गिरफ्तारी से बचने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट से सुरक्षा कवच लेने के अगले ही दिन जहांगीर ने सीधे सरेंडर कर दिया।

भाजपा नेता देवजीत सरकार ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि फलता का 'मुकुटहीन राजा' डरकर भाग खड़ा हुआ है और अब चुनाव में म्यूजिक सिस्टम बजाने और भाजपा कार्यकर्ताओं को देख लेने की धमकी देने वाले अभिषेक जनता के सामने आने से कतरा रहे हैं।

19.21 करोड़ रुपये की मेथामफेटामाइन टैबलेट की खेप के साथ मिजोरम के सैतुअल जिले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मेथामफेटामाइन मादक पदार्थ होता है। यह भारत में प्रतिबंधित है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 20 मई, 2026

नाई का काम कर रहे यूपी के नाबालिग हिंदू किशोर का कश्मीर में मतांतरण

- उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है किशोर, कुपवाड़ा में केस दर्ज पर पुलिस ने नहीं की पुष्टि

राज्य ब्यूरो, जागरण • श्रीनगर

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के एक सैलून में नाई का काम कर रहे एक नाबालिग हिंदू किशोर का कथित तौर पर जबरन मतांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। हिंदू किशोर यूपी के बिजनौर का रहने वाला है। मतांतरण के बाद मस्जिद से बाहर निकलते उसका वीडियो बनाकर किसी ने इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित कर दिया। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। हयहामा क्षेत्र में करीब चार-पांच दिन पहले एक किशोर ने कथित तौर पर स्थानीय मस्जिद में इस्लाम कुबूल किया। वह हयहामा के एक सैलून में नाई का काम करता है। प्रसारित वीडियो में नजर आ रहा है कि मतांतरण के बाद वह गले में माला डाले हुए मस्जिद से बाहर निकला। उसके साथ कुछ और स्थानीय लोग भी थे। वे उसे एक छोटे जुलूस की शक्ल में बाहर लाए और एक कार में बैठाया। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश में नाबालिग के स्वजनों ने भी देखा और जबरन मतांतरण की शिकायत की। इस आधार पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कुपवाड़ा स्थित एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले का ब्योरा साझा करने से इन्कार करते हुए कहा कि कथित तौर पर जबरन मतातंरण की शिकायत मिलने के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। लोगों से कहा गया है कि वह इस मामले में किसी भी अपुष्ट सूचना या अफवाह पर ध्यान न दें।

सनातन चेतना का महाविजय उत्सव, प्रतिमा स्थापना तक होगा सत्याग्रह

भोजशाला में उत्सव

- जय मां वाग्देवी, जय श्रीराम और वैदिक मंत्रोच्चार से गुंजायमान रहा परिसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार:

धार स्थित मां वाग्देवी मंदिर यानी भोजशाला परिसर में मंगलवार को सनातन चेतना का महाविजय उत्सव मनाया गया। इस दौरान जय मां वाग्देवी, जय श्रीराम और वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। मां वाग्देवी की आराधना, पूजन-अर्चन, हवन पूर्ण धार्मिक विधि-विधान से संपन्न हुआ।

श्रद्धालुओं ने इसे सनातन अस्मिता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। भोज उत्सव समिति ने घोषणा की कि जब तक मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा स्थापित नहीं हो जाती, तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा। भोजशाला में हर मंगलवार होने वाले सत्याग्रह की शुरुआत धार्मिक अधिकार आंदोलन के रूप में हुई। 2024-25 में इसे संगठित अभियान का स्वरूप दिया गया था। हाई कोर्ट के निर्णय और एएसआइ के 365 दिन निर्बाध पूजा के आदेश के बाद पहली बार मंगलवार पड़ा है।

कोहिनूर से अधिक महत्वपूर्ण है मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा

अब मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से वापस लाने के लिए हिंदू फ्रंट फार जस्टिस संस्था ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। संस्था के सदस्य और याची ने यह भी मांग की है कि सर्वे में भोजशाला परिसर में मिलीं 94 मूर्तियों को भी दर्शन के लिए रखा जाए। वहीं, अन्य याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी ने कहा कि मां वाग्देवी की प्रतिमा आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है, इसलिए यह भक्तों के लिए कोहिनूर से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

धार स्थित भोजशाला में मंगलवार को आयोजित सत्याग्रह के दौरान बड़ी संख्या में जुटे मां वाग्देवी के भक्तों ने आरती की। नईदुनिया

जब प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया सख्त तो फिर नीट-यूजी का पेपर कैसे हुआ लीक

पेपर लीक के बीच सवाल, विशेषज्ञों का दावा- तय मानकों में चूक हो सकती है इसका बड़ा कारण

सीबीआइ जांच के बीच एनटीए भी लीक के कारणों सहित परीक्षा से जुड़े प्रत्येक चरण की कर रही पड़ताल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नीट-यूजी के पेपर लीक मामले की जांच भले ही सीबीआइ कर रही है लेकिन इसके साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) भी पेपर लीक के पीछे के कारणों की पड़ताल करने में जुटी है। इसे लेकर परीक्षा से जुड़े प्रत्येक कदम को बारीकी से जांचा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे अगली परीक्षा में होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी।

एनटीए से जुड़े विशेषज्ञों की मानें तो परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया इतनी सख्त है कि किसी के लिए भी पेपर लीक करना आसान नहीं है। यह तभी संभव है जब इसके किसी भी स्टेप पर शिथिलता बरती जाए या फिर उसका पालन न किया जाए। 2024 में नीट-यूजी के पेपर लीक होने के बाद गठित डा. राधाकृष्णन कमेटी ने इसे और भी सख्त बनाने की सिफारिश की थी। नीट-यूजी का पेपर लीक होने के बाद इसके अमल को लेकर खड़े हो रहे

प्रतीकात्मक

सवालों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने समिति की अधिकांश सिफारिशों को लागू किए जाने का दावा किया था।

कोई एक व्यक्ति नहीं तैयार करता है पूरा प्रश्न पत्र, यह है प्रक्रिया :प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए शीर्ष संस्थानों के 10 से 15 साल के अनुभवी शिक्षकों को चुना जाता है। एनटीए इस दौरान इनके साथ गुप्त समझौता भी करता है। पूरी प्रक्रिया में सौ से अधिक शिक्षक शामिल होते हैं। इन सभी को एनटीए मुख्यालय में बारी-बारी से बुलाकर प्रश्न तैयार कराए जाते हैं। इस दौरान उन्हें मोबाइल, कैमरा व पेन कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं होती है।

वहीं उन्हें कागज और पेंसिल दिया जाता है। प्रत्येक शिक्षक से उनकी विषय विशेषज्ञता के आधार पर पांच से दस सवाल तैयार कराए जाते हैं। वह प्रश्नों को तैयार कर एक बाक्स में डाल देते हैं। इनकी बाद में एक विश्वसनीय टीम इसकी छटाई करती है और एक प्रश्न पत्र बैंक तैयार करती है।

इस बैंक से प्रश्न पत्रों के चार से छह सेट तैयार कराए जाते हैं। इनमें से किन्हीं दो सेट को विशेष सुरक्षा कोड के साथ प्रिंटिंग प्रेस के लिए भेजा जाता है। इन प्रश्न पत्रों की छपाई के दौरान कर्मचारियों और अधिकारी को मोबाइल, कैमरा आदि सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होती है। पूरी छपाई की वीडियोग्राफी कराई जाती है। खराब व मिस प्रिंट पेजों को तुरंत वहीं पर नष्ट भी कर दिया जाता है। बाद में प्रश्न पत्र के दोनों सेटों को परीक्षा केंद्रों वाले शहरों में छात्रों की संख्या के आधार पर अलग-अलग स्टील बाक्स में सील पैक कर भेजा जाता है। इस बाक्स को शहर के अलग-अलग बैंक के स्ट्रांग रूम में जमा करा दिया जाता है। इस दौरान किस बैंक में रखे प्रश्न के सेट के जरिए परीक्षा करानी है, इसका फैसला एनटीए परीक्षा वाले दिन सुबह करता है।

प्रधान ने दोबारा होने वाली परीक्षा तैयारियों को जांचा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से जुड़ी नीट-यूजी की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा की तैयारियों को जांचा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकाल के साथ त्रुटिरहित परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले तीन मई को हुई नीट-यूजी की परीक्षा को पेपर लीक होने के चलते रद कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री ने यह निर्देश नीट-यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा की तैयारियों के लिए बुलाई गई एक उच्चस्तरीय के दौरान दिए हैं। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधान ने कहा कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को तुरंत दूर किया जाए। पूरी परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रोटोकाल के तहत सुरक्षित, सुचारू व त्रुटिरहित तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की मजबूत निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के डीएम व एसपी के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए जाएं। प्रधान ने परीक्षा केंद्रों की सतर्कता व सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता न करने के भी निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को छात्रों के लिए परिवहन, पेयजल व अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला, डाक्टर की हत्या में नौ को उम्रकैद

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई के प्रसिद्ध न्यूरोलाजिस्ट सुब्बैया की 2013 में दिनदहाड़े हुई हत्या के दोषियों को बरी करने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को रद करते हुए सभी नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ट्रायल कोर्ट ने कई दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने दोषियों को बरी कर दिया।

मामला सुप्रीम कोर्ट में आने पर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा मृत्युदंड की मांग न करने के फैसले पर गौर करते हुए सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। 96 पृष्ठों के फैसले को लिखते हुए जस्टिस शर्मा ने रवींद्रनाथ टैगोर का उद्धरण दिया। टैगोर ने कहा था, लालच की कोई समय सीमा नहीं होती। इसे न तो सुंदर प्रकृति पर दया आती है और न ही मनुष्यों पर। यह क्षणभर भी संकोच किए बिना जीवन को कुचलने के लिए निर्दयतापूर्वक तैयार रहता है।

आरोपितों ने 14 सितंबर 2013 को जमीन के विवाद के चलते डाक्टर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। 2021 में ट्रायल कोर्ट ने सात दोषियों को मौत की सजा और दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन जून 2024 में मद्रास हाई कोर्ट ने साक्ष्य में खामी और गवाहों के बयानों में देरी को देखते हुए सभी आरोपितों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और निचली अदालत के दोषी ठहराने के फैसले को बहाल कर दिया।

छात्रा को अगवा करके दुष्कर्म, चाकू और जलती सिगरेट से दिए जख्म

16 दिन बाद पुलिस ने किया बरामद, मप्र की रहने वाली पीड़िता ने गांव के ही युवकों पर लगाया आरोप

- महोबा में 30 अप्रैल को लाइब्रेरी से कमरे में लौटते समय कार सवारों ने किया था अपहरण, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, महोबा

यूपी के महोबा में लाइब्रेरी से कमरे में लौटते समय 30 अप्रैल को अगवा की गई नीट की तैयारी कर रही छात्रा को 16 दिन बाद पुलिस ने यहां बरामद किया। इसके दो दिन बाद छात्रा ने सनसनीखेज राजफाश किया। छात्रा का आरोप है कि अगवा करने के बाद उसे नशीला इंजेक्शन देकर दुष्कर्म किया जाता रहा। हाथ को चाकू से काटा और चिल्लाने पर सिगरेट से दागा गया।

आरोपितों ने उसके भाई की फोटो दिखाकर शादी का दबाव बनाया। कहा, शादी कर लो वरना भाई को मार देंगे। फर्जी आधार कार्ड बनवाया और जबरन शादी करा दी। फोटो-वीडियो भी बनाए। तीन मई को उसकी नीट की परीक्षा छूट गई। छात्रा मूलरूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिलेकी रहने वाली है व सीमावर्ती जिले महोबा में डेढ़ साल से किराये पर रहकर नीट की तैयारी कर रही है।

छात्रा का आरोप है कि जब उसका अपहरण किया गया तब कार के अंदर कई लोग बैठे थे। 13 मई को आरोपित उसे प्रयागराज ले गए। उसके गांव के मोहित के स्वजन भी वहां पहुंचे और उस पर दबाव बनाया। इस साजिश में 15-20 लोग शामिल हैं।

पीड़िता ने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि पीड़िता के न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए हैं। मां की सूचना पर सात मई को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। दो दिन पहले तीन आरोपितों मोहित श्रीवास, अंकित श्रीवास व संतराम श्रीवास को गिरफ्तार किया जा चुका है। चार पुलिस टीमें गठित कर शेष लगभग एक दर्जन आरोपितों की तलाश की जारी है। सभी आरोपों की जांच के बाद और तथ्य सामने आएंगे।

उधर, मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी 10 मई को केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई व निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया था। पीड़िता की मां ने बताया कि महोबा में एक दर्जन से अधिक अच्छे कोचिंग संस्थान हैं, इसलिए बेटी को नीट की तैयारी करने भेजा था।

आरोपितों ने नवंबर 2024 में भी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका मुकदमा महिला थाना छतरपुर में दर्ज है। तभी आरोपितों ने अपहरण कर दुष्कर्म की धमकी दी थी।

प्रतीकात्मक

अमृतसर में बीकेआइ के दो आतंकी हैंड ग्रेनेड समेत गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर: काउंटर इंटेलिजेंस (सीआइ) अमृतसर की टीम ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआइ) के दो आतंकियों को दो हैंड ग्रेनेड समेत गिरफ्तार किया है। टीम ने सूचना के आधार पर अजनाला के बाजीगर मोहल्ला के रहने वाले अजय और उसके साथी के खिलाफ कार्रवाई की। दोनों आतंकी विदेशी नेटवर्क के संपर्क में थे और पंजाब में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे थे। दोनों से पूछताछ में पता चला है कि इन विस्फोटकों का इस्तेमाल सरकारी संस्थानों और महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जाना था। इस संबंध में थाना स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है।

वहीं, जालंधर में बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय के पास पांच मई को हुए ब्लास्ट मामले में जीरकपुर से दो और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। मामले में चार अन्य लोगों की भी तलाश है। हालांकि, पुलिस ने किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

कानपुर में मां का कटा हाथ लेकर पुलिस आयुक्त दफ्तर पहुंचा आइटीबीपी जवान

- कृष्णा हास्पिटल के डाक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप, न्याय की गुहार
- मामला चर्चा में आने के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग, मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर

'यह वही हाथ है, जिसने पाल पोसकर...खाना खिलाकर मुझे बड़ा किया। मुझे इस लायक बनाया कि देश की सेवा कर सकूं। उन डाक्टरों को सजा दिलाना चाहता हूं, जिनके कारण मेरी मां की जान पर संकट आ गया।' रुंधे गले से निकलते ये शब्द इंडो-तिब्बत बार्डर पुलिस (आइटीबीपी) के जवान विकास कुमार थे। मंगलवार को वह आइस पैक बाक्स से अपनी मां का कटा हाथ निकाल कर पुलिस आयुक्त कार्यालय में न्याय की गुहार लगा रहे थे। आइस पैक बाक्स में कटा हाथ लेकर तीन दिन से भटक रहे जवान की पीड़ा सुनने के बाद पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएमओ ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर रिपोर्ट मांगी है।

फतेहपुर निवासी विकास कुमार आइटीबीपी की 32वीं बटालियन महाराजपुर में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि मां निर्मला देवी को सांस लेने में तकलीफ होने पर 13 मई को कृष्णा हास्पिटल में भर्ती कराया था। वहां इंजेक्शन लगाने के बाद मां का हाथ काला पड़ गया। हालत ज्यादा बिगड़ने पर 14 मई की शाम वह मां को लेकर पारस अस्पताल पहुंचे। वहां के डाक्टरों ने आशंका जताई कि गलत इंजेक्शन लगने से यह समस्या हुई है। इसके बाद उन्होंने 40 हजार रुपये का इंजेक्शन लगाया, मगर आराम नहीं मिला। डाक्टरों ने जांच के बाद बताया कि संक्रमण पूरे हाथ में फैलने के कारण अब इसे काटना पड़ेगा। 17 मई को आपरेशन कर मां का दाहिना हाथ काट दिया गया। आरोप है कि इसके बाद रेल बाजार थाना और सीएमओ के यहां चक्कर काटे, मगर सुनवाई नहीं हुई। पुलिस आयुक्त ने बताया कि सीएमओ की रिपोर्ट व जवान की तहरीर के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डा. हरिदत्त नेमी ने बताया कि जांच टीम ने कृष्णा अस्पताल जाकर इलाज से जुड़े पत्र जुटा लिए हैं। डाक्टर व अन्य स्टाफ के बयान लेकर रिपोर्ट भेजेंगे। वहीं, कृष्णा हास्पिटल के निदेशक ऐश्वर्य गर्ग ने बताया कि उनके यहां इलाज के बाद जवान अपनी मां को लेकर पारस हास्पिटल गया था। वहां पर हाथ काटा गया होगा। इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई है। जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा।

डिब्बे में अपनी मां का कटा हाथ लेकर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचा आइटीबीपी का जवान विकास। वीडियो ग्रैब

ईको कार को एंबुलेंस बना कर रहे थे गोतस्करी, मुठभेड के बाद एक गिरफ्तार

- अलवर से दिल्ली-मुंबई-एक्सप्रेसवे के रास्ते लाए थे चार गोवंशी
- लोहे के कांटे डाल टायर पंचर कर वाहन रोका, फायरिंग कर दो तस्कर फरार

जागरण संवाददाता, नूंह

जिले में ईको कार को एंबुलेंस बनाकर गोतस्करी करने का मामला सामने आया है। पुलिस व तस्करों के बीच मंगलवार सुबह मुठभेड़ में एक तस्कर दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया जबकि दो आरोपित फरार हो गए। घायल आरोपित पलवल जिले का उटावड गांव निवासी हम्मस खान है। फरार तस्करों की भी पहचान की गई है। दरअसल पुलिस की तरफ से पिछले कुछ दिनों में सख्त कार्रवाई के चलते तस्करों ने गोतस्करी का तरीका बदल दिया है। वे अब छोटे वाहनों को एंबुलेंस का रूप देकर तस्करी को अंजाम दे रहे हैं।

हरियाणा में नूंह सीआइए पुलिस टीम को मंगलवार को सूचना मिली थी कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते राजस्थान नंबर की ईको कार को एंबुलेंस वाहन बनाकर उसमें अलवर से चार गोवंशी को तस्करी करके लाया जा रहा है। पुलिस ने सूचना पर रास्ते में नाका लगा दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही राजस्थान नंबर की एंबुलेंस आती दिखाई दी, पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह नहीं रुकी। यह देख पुलिस जवानों ने वाहन के सामने लोहे के कांटे डाल दिए, जिससे टायर पंचर हो गया। इसके बाद दो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और वाहन से उतरकर भाग निकले। पुलिस की कार्रवाई में तीसरे तस्कर हम्मस के दोनों पैरों में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया।

इसी एंबुलेंस वाहन, इसी वाहन में हो रही थी गोवंशी की तस्करी। जागरण

'जिन जगहों को सील करने की जरूरत, उन्हें तुरंत करे सीबीआइ'

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता : आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआइ को फटकार लगाई, कहा कि सेमिनार हाल के अलावा जिन जगहों को सील करने की जरूरत है, उन्हें भी तुरंत सील किया जाए। मालूम हो कि मामले की सुनवाई से कलकत्ता हाई कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंच खुद को अलग कर चुकी हैं। बाद में मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल के निर्देश पर मामला नई डिवीजन बेंच को सौंपा गया। सीबीआइ की ओर से बताया गया कि सेमिनार हाल अब भी सील है। पीड़िता के परिवार ने दावा किया कि अस्पताल की सातवीं मंजिल पर स्थित तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष का कार्यालय अब भी खुला हुआ है। परिवार की ओर से आशंका जताई गई कि मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सुबूत वहां हो सकते हैं। कोर्ट ने सीबीआइ से सवाल किया कि क्या जांच एजेंसी को अन्य स्थानों को भी सील करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

धीमी प्रक्रिया

राज्य में बेसहारा मवेशियों के लिए 1,460 गोधाम किए जाने हैं स्थापित, सरकार ने प्रत्येक विकासखंड में 10-10 गोधाम खोलने की योजना है बनाई

छत्तीसगढ़ में जमीन के इंतजार में गोधाम योजना

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधाम योजना के तहत प्रदेशभर में 1,460 गोधाम स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन जमीन आवंटन की धीमी प्रक्रिया के कारण योजना अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है। बेसहारा मवेशियों की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रत्येक विकासखंड में 10-10 गोधाम खोलने की योजना बनाई है।

रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों में पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 14 मार्च को बिलासपुर से 29 गोधामों का औपचारिक शुभारंभ भी किया था, लेकिन रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों में अब तक पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है।

सड़कों पर घूमते मवेशी यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने भी कुछ दिनों पहले सख्त टिप्पणी की थी।

छत्तसीगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि यदि व्यवस्था सही है, तो पशुओं को सड़कों पर क्यों रहना पड़ रहा है?

गोधाम के लिए चाहिए इतनी जमीन : गोधामों में चारा विकास को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम एक एकड़ की जमीन जरूरी है। प्रति एकड़ 47 हजार रुपये प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकतम पांच एकड़ भूमि तक 2.35 लाख रुपये वार्षिक सहायता का प्रविधान किया गया है। प्रत्येक गोधाम में लगभग 200 गोवंश को रखने की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

मानदेय और भरण-पोषण की राशि तय : राज्य सरकार द्वारा बेसहारा मवेशियों के संरक्षण और संचालन के लिए मानदेय और भरण-पोषण की राशि तय की जा चुकी है। गोधाम में काम करने वालों के लिए 10,916 रुपये प्रति माह और पशुसेवकों (परिचारकों) के लिए 13,126 रुपये प्रतिमाह का मानदेय तय किया गया है।

वहीं, मवेशियों के चारे और रखरखाव के लिए राशि प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से तय गई है।

यह राशि पहले वर्ष 10 रुपये प्रतिदिन, दूसरे वर्ष 20 रुपये, तीसरे वर्ष 30 और चौथे वर्ष 35 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन तय की गई है। एक एकड़ में चारा विकास कार्यक्रम पर 47,000 रुपये और पांच एकड़ के लिए 2,85,000 रुपये का प्रविधान है।

प्रतीकात्मक

कोविड के दौरान जन समस्याओं संबंधी स्वत: संज्ञान मामले बंद

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड महामारी के दौरान शुरू किए गए चार अलग-अलग स्वतः संज्ञान मामलों को बंद कर दिया। जन समस्याओं से संबंधित ये मामले मरीजों के उपचार और अस्पतालों में शवों के प्रबंधन से जुड़े थे। कोर्ट ने कहा कि उस वक्त परिस्थितियां अलग थीं और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुद्दों का संज्ञान लिया था और नागरिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। पीठ चार स्वतः संज्ञान याचिकाओं पर विचार कर रही थी। ये मामले मिड-डे मील के बंद होने, महामारी के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के कामकाम के लिए दिशा-निर्देश, कोविड-19 मरीजों के उचित इलाज, अस्पतालों में शवों के प्रबंधन और महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति व सेवाओं के वितरण से जुड़े थे।

पेपर लीक और छात्रा पर दबाव बनाने का आरोपित शिक्षक निलंबित

कार्रवाई

- लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य परिषद बैठक में अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. परमजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक पर छात्रा के लिए पेपर आउट करने, अशोभनीय बातचीत और उस पर मिलने का दबाव बनाने सहित कई गंभीर आरोप लगे थे।

मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर जे.पी. सैनी की अध्यक्षता में संपन्न कार्यपरिषद की आपातकालीन बैठक में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुशासन समिति की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कार्यपरिषद ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को बेहद गंभीर मानते हुए आरोपित शिक्षक के निलंबन की संस्तुति पर मुहर लगा दी। अनुशासन समिति की रिपोर्ट में चार आरोप प्रथम दृष्ट्या सही पाए हैं। उच्चस्तरीय अनुशासन समिति ने वायरल आडियो की प्रमाणिकता, लिखित व मौखिक शिकायतों तथा आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) द्वारा जुटाए गए तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

डा. परमजीत सिंह।

प्रसारित आडियो में विश्विद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के एसो. प्रोफेसर पर लगे थे गंभीर आरोप

3 लोगों की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में मंगलवार को एक घर पर बिजली का तार गिरने से। भारी बारिश के कारण अथूर के अग्रहारा स्ट्रीट स्थित करुप्पैया के घर की ऊपरी मंजिल पर बिजली का तार टूटकर गिर गया था।

न्यूज गैलरी

पुणे में मामूली विवाद के बाद सांप्रदायिक तनाव

पुणे : पुणे में मामूली विवाद के चलते दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस टीमों पर भीड़ ने पत्थर फेंके। एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार देर रात कोंढवा इलाके में हुई इस झड़प में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना कोंढवा की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुछ किशोरों के बीच मामूली कहासुनी से शुरू हुई। विवाद तब बढ़ गया जब दो समुदायों के वयस्क भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए। (प्रेट्र)

पुडुचेरी में थट्टनचावडी सीट से रंगासामी ने दिया इस्तीफा

पुडुचेरी : पुडुचेरी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ए. अंबालगन ने मुख्यमंत्री एन. रंगासामी का थट्टनचावडी विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा मंगलवार को स्वीकार कर लिया। रंगासामी ने विधानसभा चुनावों में थट्टनचावडी और मंगलम सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर जीत हासिल की। मुख्यमंत्री ने अब थट्टनचावडी सीट छोड़ दी है। रंगासामी ने 13 मई को पांचवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। (प्रेट्र)

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरणों के प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन सभी न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल आठ सितंबर तक बढ़ा दिया, जिनका कार्यकाल आठ सितंबर से पहले समाप्त होने वाला था ताकि न्यायाधिकरणों का निर्बाध कामकाज सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची तथा जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने लंबित मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। (प्रेट्र)

संवैधानिक मामलों की सुनवाई को गठित होंगी कई पीठ

नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में लंबित संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए जल्द ही सात न्यायाधीशों की कई पीठ गठित करेंगे। उन्होंने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, मैं जल्द ही सात न्यायाधीशों की पीठों का गठन करने जा रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि मुझे इस मामले की सुनवाई का समय न मिले। (प्रेट्र)

सहपाठी से दुष्कर्म का आरोपित बीटेक छात्र गिरफ्तार

हैदराबाद : तेलंगाना में सहपाठी से दुष्कर्म के आरोपित बीटेक छात्र को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता और आरोपित दोनों एक ही कालेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। घटना हैदराबाद में 14 मई को हुई। आरोपित चाय पीने के बहाने पीड़िता को बाहर ले गया। उसने पीड़िता को घुमाया और लौटते समय रास्ते में शराब खरीदी। फिर उसने उसे 'जबरन शराब पिलाई' और खुद भी पी। इसके बाद, उससे दुष्कर्म किया। (प्रेट्र)

नागरिकों के चुराए गए व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

आइटी मंत्रालय को इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर गंभीरता से विचार के दिए निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा और विदेशी सर्वरों पर कथित रूप से संग्रहीत भारतीयों के चोरी हुए व्यक्तिगत डाटा को वापस पाने या नष्ट करने के मामले में एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर गंभीरता से विचार करे। साइबर सुरक्षा सलाहकार नीतीश कुमार द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई थी कि विदेश में संग्रहीत भारतीयों के डाटा को सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ ने याचिका को एक 'पूरक प्रतिवेदन' के रूप में मंत्रालय के पास भेजते हुए उचित कदम उठाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

विदेशी सर्वरों पर भारतीयों का डाटा और डिजिटल अरेस्ट का खतरा : सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कम से कम पांच देशों में मौजूद संस्थाओं द्वारा भारतीयों का डाटा चुराया गया है, जिसका इस्तेमाल अब नागरिकों के खिलाफ एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। फिंगरप्रिंट और व्यक्तिगत पहचान जैसी बेहद संवेदनशील जानकारियों का दुरुपयोग कर 'डिजिटल अरेस्ट' और जबरन वसूली जैसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। कोर्ट ने इस चिंता की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जब तक संबंधित देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि न हो, आरोपितों को भारत लाना मुश्किल है। इस पर याचिकाकर्ता का कहना था, "यदि हम डाटा वापस नहीं ला सकते, तो कम से कम हम इसे पुनर्गठित और सुरक्षित तो कर ही सकते हैं।"

कोर्ट ने माना कि यह मामला पूरी तरह कानूनी न होकर "अत्यधिक तकनीकी" है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप के बजाय प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है। इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार के पास जाने की सलाह दी। याचिका में केंद्र सरकार को डाटा रिकवर या नष्ट करने के निर्देश देने के साथ-साथ 'डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023' को तुरंत पूरी तरह लागू करने की मांग की गई है। साथ ही, डाटा चोरी की जांच की निगरानी के लिए एक एसआइटी के गठन का भी अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए मंत्रालय को भविष्य में डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस पर विचार करने की छूट दी है।

नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलने की याचिका नहीं सुनेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से साफ इन्कार कर दिया है। याचिका में केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार के उस प्रस्ताव पर समयबद्ध फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें एयरपोर्ट का नाम बदलकर 'लोकनेता डी. बी. पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट' रखने का सुझाव दिया गया था। पीठ कहा कि कोर्ट का काम यह तय करना नहीं है कि किसी हवाई अड्डे का नाम क्या हो। ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नीति निर्धारण में दखल देने जैसा होगा। कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट के नवंबर 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें इस याचिका को पहले ही खारिज कर दिया गया था।

अयोध्या के मेडिकल कालेज में 744 रुपये में खरीदा गया 44 रुपये का इंजेक्शन

वित्तीय अनियमितता

प्रमोद दुबे • जागरण

- शासनादेश ताक पर रख राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज ने खरीदीं 20 गुणा महंगी दवाएं

80 प्रतिशत यूपी मेडिकल कारपोरेशन से तो 20 प्रतिशत लोकल खरीद का है नियम

राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज दर्शननगर

अयोध्या : अयोध्या में दर्शननगर स्थिति राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज में 40 लाख रुपये का वाटरलेस शैंपू व बाडीवाश खरीदने का प्रकरण सामने आने के बाद कुछ और अनियमिताएं सामने आई हैं। अब दवाओं की खरीद में शासनादेश के उल्लंघन का मामला खुला है। पूर्व प्राचार्य डा. सत्यजीत वर्मा के कार्यकाल में यूपी मेडिकल कारपोरेशन के बजाय स्थानीय खरीद (लोकल परचेज-एलपी) को अधिक महत्व दिया गया। यही वजह रही कि केजीएमयू की अनुबंध दर से 10 से 20 गुणा तक अधिक महंगी दवाएं खरीदी गईं। स्थानीय खरीद के नाम पर दरों में जो बड़ा खेल हुआ, उसका अंदाजा बुखार में प्रयोग होने वाले पैरासीटामोल इंजेक्शन की कीमत से लगाया जा सकता है। पैरासीटामोल इंजेक्शन (100 एमएल) की केजीएमयू की अनुबंध दर जहां मात्र 44 रुपये है, वहीं इसे स्थानीय स्तर पर 744 रुपये की दर पर खरीदा गया। इसी तरह अन्य दवाइयां भी खरीदी गईं।

यह पूरा प्रकरण तब उजागर हुआ, जब दवा आपूर्ति करने वाली कंपनी ने बकाया भुगतान की मांग की। जब ये पत्रावलियां वर्तमान प्राचार्य डा. दिनेश सिंह मार्तोलिया के समक्ष पहुंचीं, तो उन्होंने फौरी तौर पर जांच करते हुए इस संदिग्ध भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार, मेडिकल कालेजों को आवंटित बजट की 80 प्रतिशत औषधियों की आपूर्ति यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन से सुनिश्चित करनी होती है, जबकि शेष 20 प्रतिशत खरीद ही आपातकालीन स्थिति में स्थानीय स्तर (लोकल परचेज) से की जा सकती है। इसके उलट, आरडी मेडिकल कालेज में वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियमों का उल्लंघन किया गया। यहां यूपी मेडिकल कारपोरेशन से सिर्फ एक करोड़ 50 लाख रुपये (करीब 30 प्रतिशत) की दवाएं खरीदी गईं, जबकि स्थानीय स्तर से तीन करोड़ 75 लाख नौ हजार रुपये (करीब 70 प्रतिशत) की भारी-भरकम खरीद कर डाली गई।

"पूर्व में नियम विरुद्ध खरीदी गई दवाओं की जानकारी कंपनी की ओर से शेष भुगतान की मांग किए जाने के बाद हुई है। फाइल देखने पर बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से भुगतान पर रोक लगा दी गई है। सभी फाइलों की गहनता से जांच की जा रही है। शासन को इस पूरे प्रकरण और गड़बड़ी से जल्द ही लिखित रूप में अवगत कराया जाएगा।"

- डा. डीके मार्तोलिया, प्राचार्य, राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज

चौंकाने वाली बात यह है कि इस अनियमित खरीद का करीब 90 प्रतिशत भुगतान भी पूर्व प्राचार्य डा. सत्यजीत वर्मा व वित्त नियंत्रक रवि सिंह द्वारा अप्रैल 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 के बीच आनन-फानन में कर दिया गया। दवाओं की उपलब्धता और पारदर्शिता को लेकर दो जनवरी 2020 को तत्कालीन प्रमुख सचिव डा. रजनीश दुबे तथा छह सितंबर 2023 को आलोक कुमार की ओर से महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को स्पष्ट दिशा-निर्देश भेजे गए थे। इसमें साफ कहा गया था कि कारपोरेशन से 80 फीसद और स्थानीय स्तर से केवल 20 फीसद खरीद की जाए, जिसे इस मामले में पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया।

उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापी लेने की तिथि 23 मई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर आ रही तकनीकी समस्याओं को देखते हुए लिया
- तकनीकी दिक्कतों के कारण छात्र स्कैन कापी के लिए नहीं कर पा रहे थे आवेदन

सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा की जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने पहले यह तिथि 22 मई तक तय की थी। अब विद्यार्थी स्कैन कापी के लिए 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 26 से 29 मई के बीच अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापी देख सकेंगे। बोर्ड ने यह फैसला वेबसाइट पर आ रही तकनीकी समस्याओं को देखते हुए लिया है।

सीबीएसई ने 12वीं में कापियों की जांच के लिए आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम लागू किया था। इसके बाद जारी परिणाम में उम्मीद से कम अंक मिलने की शिकायतें विद्यार्थियों द्वारा की गईं। अब सीबीएसई के पुर्नमूल्यांकन और स्कैन कापी हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि वे न तो पोर्टल पर लागिन कर पा रहे हैं और न ही आवेदन प्रक्रिया पूरी हो रही है।

ब्लैंक पेज दिखने और कैप्चा कोड नहीं आने की शिकायत : मंगलवार को सीबीएसई ने पोस्ट-रिजल्ट (परिणाम के बाद) सुविधा शुरू की है। इसमें विद्यार्थी अपनी जांची हुई उत्तर पुस्तिका की स्कैन कापी लेकर पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि कभी वेबसाइट ब्लैंक पेज दिखा रही है तो कभी कैप्चा कोड नहीं आ रहा। कई मामलों में भुगतान कटने के बाद भी आवेदन पूरा नहीं हो रहा है। एक छात्र ने बताया कि कई बार कोशिश करने के बाद भी वह पंजीकरण नहीं कर पाया, क्योंकि बार-बार वेबसाइट हैंग हो रही थी। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी छात्रों ने स्क्रीनशाट साझा करते हुए बोर्ड की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। एक छात्र ने कहा कि कि रुपये कट गए पर वेरिफिकेशन फेल हो गया।

बोर्ड ने तकनीकी विफलता से किया इन्कार : इस मामले में सीबीएसई ने किसी बड़ी तकनीकी विफलता से इन्कार किया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि उन्हें सुबह कुछ छात्रों के फोन आए थे, जो लागिन नहीं कर पा रहे थे। उनके अनुसार कई बार पुराना सेव पेज खुल जाता है, जिसे कंप्यूटर रीस्टार्ट करने से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने छात्रों को कुछ देर बाद दोबारा से लागिन करने की सलाह दी है। वैसे इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

झारखंड में गंगा की मुख्य धारा सातवें साल भी प्रदूषण मुक्त

- नमामि गंगे से संबंधित रिपोर्ट से मिली जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : गंगा की मुख्य धारा का सबसे छोटा हिस्सा झारखंड से होकर गुजरता है। यह हिस्सा लगातार सात वर्षों से प्रदूषण मुक्त नदी खंड (पीआरएस) का रिकार्ड बनाए हुए है। यह जानकारी नमामि गंगे से संबंधित रिपोर्ट से मिली है। गंगा बेसिन के पांच राज्यों में झारखंड शामिल है। केंद्र के इस प्रमुख नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत झारखंड के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए नमामि गंगे ने कहा कि इस राज्य का मॉडल इसलिए अलग है, क्योंकि इसमें दूषित नदी के किसी हिस्से के पुनरुद्धार के बजाय प्रदूषण रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नमामि गंगे ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि जहां अधिकतर नमामि गंगे अभियान की कहानियां सफाई से जुड़ी होती हैं, वहीं झारखंड में नदी को गंदा होने से रोका जाता है। उसने कहा कि वर्ष 2018 में झारखंड से गुजरने वाली गंगा की मुख्यधारा प्रदूषण-मुक्त मिली थी और नमामि गंगा अभियान के सात साल बाद 2025 में भी, इसमें प्रदूषण नहीं मिला। राज्य ने इस दिशा में दृढ़ संकल्प दिखाया है। इस संदर्भ में साझा किए गए एक ग्राफिक के अनुसार राज्य में गंगा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए 261.5 एमएलडी की स्वीकृत शोधन क्षमता और कुल 1,310 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पांच सीवेज ट्रीटमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

त्रिशूर में पटाखा विस्फोट मामले में केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

कोच्चि, प्रेट्र : केरल हाई कोर्ट ने त्रिशूर जिले की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के संबंध में राज्य सरकार और कोचीन तथा तिरुवंबडी देवस्वमों को मंगलवार को नोटिस जारी किया। इस विस्फोट में 17 लोगों की जान चली गई थी। मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और श्याम कुमार वीएम. की पीठ ने सरकार और देवस्वोम बोर्डों को 16 जून तक इस घटना के संबंध में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर यह नोटिस जारी किया। 21 अप्रैल को हुए विस्फोट में पटाखे की फैक्ट्री में मौजूद 38 लोगों में से 17 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा एक शेड में हुआ था जहां त्रिशूर पूरम पर्व से पहले थिरुवंबडी देवास्वोम के लिए पटाखे बनाए जा रहे थे।

अदालत ने ईडी को ढोंगी बाबा खरात को गिरफ्तार करने की दी अनुमति

6 अप्रैल को खरात के खिलाफ पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया था मामला

अशोक खरात।

दुष्कर्म और महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित कई प्राथमिकी भी हैं दर्ज

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई की एक विशेष अदालत ने ईडी को ढोंगी बाबा अशोक खरात को 70 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी। दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे खरात को नासिक जेल से एक पेशी वारंट पर विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया। यहां वह न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने खरात को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी, इसे अदालत ने मंजूर कर लिया। ईडी अब उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार करेगी और बुधवार को अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। ईडी ने छह अप्रैल को खरात के खिलाफ मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। उसने खरात के खिलाफ नासिक पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी का संज्ञान लिया था। खरात के विरुद्ध दुष्कर्म और महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित कई प्राथमिकी भी दर्ज है।

केरलम में पटाखे फोड़ने के दौरान बच्चे की मौत

कन्नूर, प्रेट्र : केरलम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मनाने के बाद शेष रह गए पटाखों को फोड़ने के दौरान 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि यह घटना सोमवार तड़के करीब 11 बजे उस समय हुई। इस घटना में तीन अन्य बच्चे भी घायल हो गए। इस घटना के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि वीडी सतीशन ने सोमवार को राज्य की कमान संभाली है। सतीशन और उनके मंत्रिमंडल के 20 सदस्यों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद यूडीएफ कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया था।

सास-बहू ने घर में बसा दिया 'कश्मीर' खिलखिलाई केसर की फसल

धान और मूंगफली की फसल के लिए प्रसिद्ध मैनपुरी में परंपरागत खेती करने वालों के समक्ष पेश किया अनुकरणीय उदाहरण

चंद्रशेखर गौड़ • जागरण

जागरण विशेष

घर में खेती शुरू होने पर मंजरी ने नौकरी फिर ज्वाइन कर ली और वर्क फ्राम होम कर रही हैं। घर में उगी फसल के साथ शुभा व मंजरी। स्वयं

मैनपुरी : धान और मूंगफली की फसल के लिए प्रसिद्ध मैनपुरी में विपरीत मौसम में केसर की फसल उगाकर सास-बहू की जोड़ी ने परंपरागत खेती करने वालों के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। घर को ही 'कश्मीर' बना खेती करने वाली इस जोड़ी का चार साल में टर्नओवर 25 लाख रुपये के पार हो गया। नीति आयोग ने सास-बहू की इस जोड़ी को सम्मानित किया है।

रघुवीर शीतगृह के मालिक संजीव भटनागर की पत्नी शुभा ने इंटरनेट मीडिया पर केसर की खेती से संबंधित वीडियो देखा तो उन्होंने भी इसकी खेती के बारे में तय किया। चूंकि, तकनीकी जानकारी कम थी, पर इरादा मजबूत था, इसलिए अपनी कंप्यूटर इंजीनियर बहू मंजरी से बात की। शुभा बताती हैं कि बहू के साथ मिलकर छह माह तक केसर की खेती के बारे में जानकारियां जुटाईं। इसके लिए अनुकूल पर्यावरण, तापमान, नमी और रोशनी के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद कश्मीर के केसर उत्पादकों से संपर्क किया। 2023 में 560 वर्ग फीट के वातानुकूलित हाल से इसकी शुरुआत की। अगस्त 2023 में लकड़ी की ट्रे में केसर की पौध को रोपा और तीन माह बाद नवंबर में जब फसल तैयार हुई तो उम्मीदें आसमान छूने लगीं। मंजरी बताती हैं कि काम शुरू करने के लिए बेंगलुरू में मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर वह ससुराल आ गईं। इसके साथ ही हाल को 1200 वर्ग फीट का बनाकर खेती शुरू की।

1200 वर्ग फीट का हाल घर में ही बनाया है फसल के लिए

25 लाख रुपये से अधिक का है अब इनका टर्नओवर

800 रुपये तक कीमत मिलती है एक ग्राम की

इस तरह बढ़ा उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (किलो में)
2023	2.2
2024	3.8
2025	4.9
2026	6.0+ (उम्मीद है)

90% उपज की बिक्री आनलाइन प्लेटफार्म के जरिये की जाती है

90-110 दिनों में केसर की फसल हो जाती है तैयार

25 लाख रुपये से हुई कारोबार की शुरुआत

एमए पास शुभा भटनागर बताती हैं कि उन्होंने शुरू में ही स्थायी सेटअप लगाया था। वातानुकूलित हाल व लकड़ी की ट्रे तैयार कराने से लेकर पौध तैयार करने में करीब 25 लाख रुपये की लागत आई। दो साल में लागत निकल आई। एक फसल पर सबको मिलाकर करीब नौ लाख रुपये का खर्च आता है। अब शुद्ध मुनाफा एक साल में लगभग 15 लाख रुपये से ज्यादा आ रहा है। फसल का सीजन अगस्त से नवंबर होता है। दिसंबर से जुलाई तक इस हाल का प्रयोग सेब या नींबू स्टोरेज के लिए किया जाता है।

एमेजोन के साथ अपनी वेबसाइट से बेचती हैं केसर

मंजरी बताती हैं कि 90 प्रतिशत बिक्री आनलाइन होती है। इसमें ई-कामर्स प्लेटफार्म एमेजोन के अलावा खुद की वेबसाइट शुभावनी डाट काम बनाई हुई है। वह कहती हैं कि शुरू में दिल्ली, जयपुर आदि शहरों में लगने वाले ट्रेड फेयर में शिरकत की। वहां से सार्थक परिणाम मिलने के बाद केसर गिफ्ट बाक्स तैयार कराए। अब 50 मिलीग्राम और एक ग्राम की पैकिंग बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक ग्राम की कीमत 800 रुपये है।

नीति आयोग ने किया सम्मानित, अब पति व पुत्र का भी मिला साथ

शुभा भटनागर के पति और पुत्र भी उनके इस काम को देखने लगे हैं। कंप्यूटर इंजीनियर बेटे अंकित भटनागर ने बताया कि वह देशभर के अकेले ऐसे केसर उत्पादक हैं, जिनका नीति आयोग की वेबसाइट पर जिक्र किया गया है। उनके फोटो सहित उनके ब्रांड शुभावनी स्मार्टफार्म्स के बारे में जानकारी दी गई है। वर्ष 2024 में स्टार्टअप महाकुंभ में एग्रीटेक स्टार्टअप का पुरस्कार भी मिला था।

एरोपोनिक्स तकनीक से होता है उत्पादन

मंजरी भटनागर बताती हैं कि एरोपोनिक्स तकनीक का प्रयोग करते हुए खेती शुरू की। इसमें मिट्टी की जगह कस्टमाइज्ड खाद, तापमान नियंत्रण और ड्रिप सिंचाई का प्रयोग होता है। लकड़ी की ट्रे में कस्टमाइज्ड खाद में अगस्त में बीज बोया जाता है। 15 दिनों तक स्प्रे के माध्यम से हल्की सिंचाई की जाती है। 25 से 30 दिन में बीज अंकुरित हो जाता है। नवंबर में पर्पल रंग का फूल तैयार हो जाता है। फूल तैयार होने के दो से तीन दिन में पुष्प क्रम यानि केसर निकालकर सुखाया जाता है। वह बताती हैं कि शुरुआत में कश्मीर से बीज मंगाए गए थे। अब इसी फसल में से बीज तैयार करते हैं। बीज बुवाई के दौरान तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। फसल तैयार होने के दौरान यह घटकर पांच से छह डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है।

बिहार में विक्रमशिला सेतु के हिस्से 16 दिन बाद आपस में जुड़े, बेली ब्रिज बना सहारा

- सेतु के दोनों हिस्सों को जोड़कर गर्डर का किया गया इंस्टालेशन
- अगले माह पांच जून के बाद पुल पर वाहनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद

भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के गिरे हिस्से पर रखा गया बेली ब्रिज का फाउंडेशन। सौ : जिला प्रशासन

जागरण संवाददाता, भागलपुर

बिहार के भागलपुर में क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु के दोनों हिस्से 16 दिनों बाद आपस में जुड़ गए। सोमवार रात बार्डर रोड आर्गनाइजेशन ने 50 मीटर लंबे और पांच मीटर चौड़े गर्डर का इंस्टालेशन (स्थापन) कर बेली ब्रिज का मुख्य कार्य पूरा कर लिया। गर्डर को दोनों हिस्सों पर चढ़ाया गया, जिससे सेतु के टूटे हिस्से को अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया। अब बेली ब्रिज पर वाहनों के परिचालन के लिए लोहे की राइडिंग, डेक और रैंप तैयार किए जाएंगे। इसके बाद उत्तर दिशा में कमजोर स्लैब वाले हिस्से पर 12 मीटर और दक्षिण दिशा में 24 मीटर लंबे दो और बेली ब्रिज बनाए जाएंगे। इन दोनों बेली ब्रिज का निर्माण कार्य अगले दो दिनों में शुरू हो जाएगा, जिसे पूरा करने में तीन से चार दिन लग सकते हैं।

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साथ हुआ है अन्याय

प्रथम पृष्ठ से आगे

हाई कोर्ट ने भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद कर दिया था और प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि इस शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को मूल चयन सूची के रूप में आरक्षण के सभी नियमों के अनुसार तीन महीने के भीतर फिर से तैयार किया जाए।

रद हुई चयन सूची के अनुसार, सामान्य वर्ग के जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी, उन्होंने नौकरी पर खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ही हाई कोर्ट के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आरक्षण के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जियां दाखिल की हैं और वे मूल याचिका में प्रतिवादी भी हैं। पिछली सुनवाई पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के वकील मनीष गोस्वामी ने कहा था कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साथ इस मामले में अन्याय हुआ है और वे न्याय के लिए 2020 से भटक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मांग यह नहीं है कि जिन शिक्षकों की भर्ती हो गई है और जो पांच साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से बाहर किया जाए। इस सिलसिले में मंगलवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ में हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और अंकित गोयल ने राज्य सरकार का प्रस्ताव कोर्ट के समक्ष रखा। भाटी ने कहा कि राज्य सरकार मामले पर विचार करने के लिए राजी है और प्रक्रिया पूरी करके कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट देगी। कोर्ट ने उनके प्रस्ताव को रिकार्ड पर लेते हुए राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 20 मई, 2026

दैनिक जागरण

संतोष ही आनंद का आधार है

आवारा आतंक पर सख्ती

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस लेने से मना कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों, बस एवं रेलवे स्टेशनों, खेल परिसरों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उनकी नसबंदी की जाए। इस आदेश में संशोधन-परिवर्तन करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि लोगों को कुत्तों के काटने के खतरे के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। निःसंदेह पशु प्रेमियों और विशेष रूप से डाग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती रास नहीं आएगी, पर आखिर ऐसे लोग इसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं कि आवारा कुत्ते आतंक का पर्याय बन गए हैं? हर दिन ऐसी खबरें आती हैं कि आवारा कुत्तों ने किसी बच्चे, महिला या बुजुर्ग को दौड़ाकर काट खाया। कुछ दिल दहलाने वाली खबरें तो ऐसी भी आती हैं कि आवारा कुत्ते किसी शिशु को नोचकर खा गए या फिर किसी दोपहिया वाहन वाले को दौड़ाने के चलते वह दुर्घटना का शिकार होकर या तो गंभीर रूप से घायल हो गया या फिर उसकी मौत ही हो गई। एक सच्चाई यह भी है कि रेबीजग्रस्त कुत्तों के काटने से भी तमाम लोगों की जान जा रही है। साफ है कि ऐसी घटनाओं से मुंह फेरकर आवारा कुत्तों को हर जगह विचरने की आजादी चाहने वाले मानव जीवन की महत्ता समझने से इन्कार कर रहे हैं। वे आवारा कुत्तों को हर जगह घूमने देने के तो पक्षधर हैं, पर उनकी देखभाल करने को तैयार नहीं। आखिर यह दोहरा मानदंड नहीं तो और क्या है?

आवारा कुत्तों की समस्या केवल शहरों तक सीमित नहीं है। उनकी तेजी से बढ़ती आबादी कस्बों और गांवों के लोगों को भी आतंकित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रूप से बीमार और रेबीजग्रस्त आवारा कुत्तों को मारने पर विचार करने की भी बात कही। यह टिप्पणी कठोर लग सकती है, लेकिन आखिर मानव समाज के लिए खतरा बने कुत्तों का निदान क्या है? आवारा कुत्तों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का यह मतलब नहीं हो सकता कि उन्हें मनुष्यों से अधिक महत्व दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो दोहरा दिया कि उसके आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन यह ध्यान रहे कि हमारे नगर निकाय आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के मामले में अत्यंत सुस्त और संसाधनहीन हैं। यही कारण है कि सार्वजनिक स्थलों पर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उनके काटने की घटनाएं बेतहाशा बढ़ रही हैं। उचित यह होगा कि राज्य सरकारें अपने स्थानीय निकायों को ऐसे संसाधनों से लैस करें, जिससे वे आवारा आतंक पर काबू पा सकें। उन्हें आवारा कुत्तों के साथ-साथ अन्य बेसहारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए भी सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि वे भी समस्या बन गए हैं।

खंडूड़ी का योगदान

उत्तराखंड राज्य गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (सेनि) अब हमारे बीच नहीं रहे। उत्तराखंड राज्य गठन के लिए आंदोलन को गति देने समेत निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पांच बार गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद रहे खंडूड़ी को राजनीति में एक सख्त, अनुशासित और स्पष्टवादी नेता के रूप में याद रखा जाएगा। वर्ष 2011 में उत्तराखंड के लिए प्रभावी लोकायुक्त विधेयक पारित कराना उनकी उपलब्धि रहा। यह कानून उस समय देश के सबसे सशक्त और व्यापक लोकायुक्त कानूनों में गिना गया। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधायकों को भी जांच के दायरे में लाने का प्रविधान था। इस विधेयक ने राज्य को पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में अलग पहचान दिलाई। सैन्य पृष्ठभूमि से राजनीति में आए खंडूड़ी ने प्रशासन में अनुशासन और नियम-आधारित कार्यशैली को प्राथमिकता दी। केंद्रीय परिवहन मंत्री रहते सड़कों और आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिली। इतना ही नहीं, इन्होंने राज्य में सख्त भू-कानून लागू किया। इससे बेतहाशा प्लाटिंग और जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिशों पर अंकुश लगा। बेनामी संपत्तियों के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाया। पारदर्शी तबादला नीति लागू की, ताकि सिफारिश व दबाव की मानसिकता को खत्म किया जा सके। सेवा का अधिकार कानून लागू किया। राजनीति में आने से पहले 36 वर्षों के सैन्य जीवन में 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया। इंजीनियर के रूप में सेना के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को बखूबी अंजाम दिया। 1983 में उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। धरतीपुत्र खंडूड़ी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व सभी के लिए मिसाल है।

अमेरिका-चीन संबंधों के नए समीकरण

श्रीराम चौलिया

सामरिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनते हुए आर्थिक मामलों में सूझबूझ से कदम उठाए जाएं तो चीन और अमेरिका के बीच बदले रिश्तों का भारत बड़ा लाभार्थी बन सकता हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया चीन दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसका सरोकार भारत और अन्य एशियाई देशों की विदेश नीति एवं रणनीतिक दशा-दिशा से भी है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ ट्रंप की भाव-भंगिमाओं से यह भी आभास हुआ कि वाशिंगटन नए शीत युद्ध की तीखी प्रतिद्वंद्विता के दायरे से बाहर निकलकर बीजिंग के साथ कुछ मामलों में सह-अस्तित्व की संभावनाएं तलाशने में जुटा है। चीन के प्रति अमेरिका की इस नरमी का मूल कारण है कि ट्रंप प्रशासन दक्षिण अमेरिका को अपना प्रमुख प्रभुत्व क्षेत्र मानता है और एशिया में अनुकूल शक्ति संतुलन बनाए रखने के प्रति उतना उत्साहित नहीं, जितना पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन था। हालांकि अभी चीन ही ऐसा एकमात्र देश है, जो अमेरिका को वैश्विक स्तर पर चुनौती दे रहा है। प्रतीत होता है कि इस प्रतिद्वंद्वी से पार पाने में ट्रंप पारंपरिक अमेरिकी दृष्टिकोण में भरोसा नहीं रखते। जैसे कि ताइवान के मुद्दे को ही लें। ताइवान की स्वतंत्रता और अस्तित्व को चीन के अतिक्रमण से बचाने के लिए अमेरिका दशकों से सैन्य सहायता और सुरक्षा आश्वासन देता आ रहा है, लेकिन इस बीच पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी एशिया के युद्धों में उलझने के बाद और चीन के साथ रिश्तों की नजाकत को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान को स्वीकृत, लेकिन अभी तक वितरित न किए गए हथियारों में 21 अरब डालर का बकाया रखा है।

ताइवान के संदर्भ में बीजिंग में चिनफिंग ने एक लक्ष्मण रेखा खींचते हुए ट्रंप को चेताया कि अगर इस मुद्दे को गलत तरीके से आगे बढ़ाया गया तो इससे चीन और अमेरिका के बीच खतरनाक संघर्ष हो सकता है। बीजिंग से लौटकर ट्रंप ने मानो चिनफिंग के प्रभाव में आकर यह कहा कि चीन बहुत शक्तिशाली देश है, जो नन्हें ताइवान से मात्र 59 मील दूर है, जबकि अमेरिका की ताइवान से दूरी 9,500 मील है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि अगर ताइवान की ताकत माना जाने वाला सेमीकंडक्टर उद्योग अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया जाए तो ताइवान की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी और चीन उसे जब चाहे अपने चंगुल में ले सकता है। ताइवान पर किसी संभावित चीनी हमले की सूरत में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को लेकर भी ट्रंप ने कोई आश्वासन नहीं दिया। ताइवान के साथ जापान की सुरक्षा के जुड़ाव को देखते हुए इसे लेकर और अनिश्चितता पैदा हो गई है कि अमेरिका समूचे पूर्वी एशिया को उसके अपने हाल पर छोड़ सकता है, जिससे चीनी वर्चस्व की आशंका ही बढ़ेगी। पहले ऐसा लग रहा था कि जापान, आस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलकर अमेरिका चीनी आक्रामकता के सापेक्ष शक्ति का संतुलन बनाए रखने में सहायक बना रहेगा, लेकिन अब यह धारणा ध्वस्त होती दिख रही है। कहने को तो अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर अभी भी गंभीर है और उसकी सैन्य सक्रियता भी जारी है, लेकिन चीन को पीछे धकेलने के उसके इरादे विश्वसनीय नहीं लग रहे हैं।

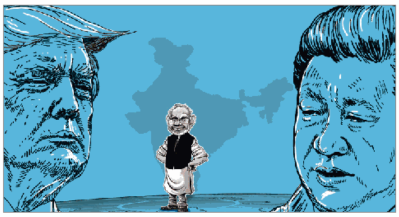

अवधेश राजपूत

भू-राजनीति के हिसाब से अमेरिका चीन के प्रति भले ही ढुलमुल रवैया अपना रहा हो, लेकिन आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा में दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव में कोई खास कमी नहीं दिख रही। ट्रंप मूल रूप से हैं तो एक व्यापारी ही और व्यापारिक दबाव की रणनीति को समझते हुए ही उन्होंने चीन को निर्यात होने वाली उच्च तकनीक पर न तो नियंत्रण में कोई ढील दी और न ही उस पर कायम 31 प्रतिशत के व्यापार शुल्क में कोई रियायत दी। चीन ने दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोककर अमेरिका को थोड़ा बहुत मजबूर जरूर किया था, लेकिन वाशिंगटन ने बीजिंग पर वाणिज्यिक दबाव पूरी तरह नहीं हटाया है। चीन दौरे पर ट्रंप के साथ अमेरिका के दिग्गज उद्योगपतियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी गया था, लेकिन वहां ऐसी महत्वाकांक्षी घोषणाएं नहीं हुईं, जिनसे लगे कि उन सुनहरे दिनों की कोई वापसी हो पाएगी, जब अमेरिकी पूंजीवादी चीन में निवेश बढ़ाकर दोनों देशों के बीच परस्पर निर्भरता को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। ऐसे रुझानों को देखें तो चीन-अमेरिका संबंधों की मिश्रित तस्वीर उभरी है। ट्रंप युग में चीन के साथ अमेरिका का भू-राजनीतिक टकराव तो कम हो रहा है, जिससे एशिया में चीन के अनियंत्रित क्षेत्रीय विस्तारवाद को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं। जबकि दूसरी ओर, चीन के साथ अमेरिका का आर्थिक और तकनीकी टकराव जारी रहना तय है, जिससे भारत जैसी उभरती शक्तियों के लिए अमेरिकी निवेश और विशेषज्ञता प्राप्त करने के अवसर खुलते हैं।

इस परिदृश्य से साफ है कि आक्रामक चीन के विरुद्ध प्रतिरक्षा और प्रतिरोध के लिए भारत को मुख्यतः अमेरिका से आस लगाए रखना आत्महत्या के समान होगा। हमें अपनी सैन्य क्षमताओं को प्राथमिकता देकर उन्हें धार देनी होगी और चीनी आक्रामकता से परेशान पड़ोसियों के साथ मिलकर सुरक्षा का मजबूत ढांचा खड़ा करना होगा। क्वाड जैसे संगठनों से अगर अमेरिका किनारा भी करे तो अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उसे सशक्त करने के उपाय किए जाएं। इस परिदृश्य के दूसरे पहलू को देखें तो अमेरिका और चीन के बीच जारी आर्थिक एवं तकनीकी टकराव का लाभ भारत जैसे देश को पश्चिमी दिग्गज कंपनियों से निवेश आकर्षित करने के लिए उठाना चाहिए।

इस दिशा में कुछ प्रयास फलीभूत होते भी दिख रहे हैं, जहां एमेजोन, माइक्रोसाफ्ट और गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने बीते साल के दौरान भारत में 67.5 अरब डालर के निवेश की घोषणा की है। 28 प्रतिशत आइफोन भारत में बन रहे हैं। यह घटनाक्रम चीन में व्यापार को लेकर अमेरिकी पूंजीवादी हलकों में व्याप्त शंकाओं का ही परिणाम है। यदि भारत चीन से दूर जा रहे अमेरिकी पूंजी निवेश को हासिल कर पाता है, तो इससे विकसित राष्ट्र बनने के हमारे सपने को साकार करने में भारी मदद मिलेगी। वहीं, सामरिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनते हुए आर्थिक मामलों में सूझबूझ से कदम उठाए जाएं तो चीन और अमेरिका के बीच बदलते समीकरणों का भारत एक बड़ा लाभार्थी बन सकता है।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)
response@jagran.com

इंदौर हाई कोर्ट के फैसले का संदेश

अवधेश कुमार

अयोध्या और उसके बाद भोजशाला पर आए न्यायालय के फैसले ने आने वाले मामलों को भी आधार दे दिया हैं

मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला परिसर को मां वाग्देवी यानी सरस्वती माता का प्राचीन मंदिर मानकर हिंदुओं के पक्ष में इंदौर उच्च न्यायालय का फैसला भले अयोध्या की तरह व्यापक विमर्श का विषय न बने, पर इसका महत्व कम नहीं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का संघर्ष 1529 में मीर बकी द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद आरंभ हुआ तो भोजशाला का सन 1305 से ही। यानी इसका संघर्ष अयोध्या, मथुरा, काशी और ऐसे अनेक स्थलों से भी पुराना है। अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद यह दूसरा ऐसा बड़ा फैसला है, जिसके आधार पर विचार करने से मंदिर-मस्जिद विवादों के संदर्भ में आगामी न्यायिक फैसलों का पूर्वाभास हो जाता है। यह ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर गंभीरता से विचार की आवश्यकता होगी। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय के 2019 के अयोध्या फैसले के सिद्धांतों (जैसे-पुरातात्विक साक्ष्य और निरंतर आस्था के महत्व) को भी आधार बनाया गया है। मुस्लिम पक्षकार अयोध्या की भांति ही इस फैसले को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं और उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं। हालांकि इतिहास से परिचित आम मुसलमानों से बात करें तो उन्हें लगता है कि उच्च न्यायालय के फैसले में परिवर्तन असंभव है। इंदौर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ के फैसले को पढ़ने से पता चलेगा कि मुस्लिम पक्षकार ने हिंदुओं के दावों, तर्कों, साक्ष्यों आदि को नकारने के लिए तमाम दलीलें तो दीं, पर ऐतिहासिक दावों, हजारों दस्तावेजों से प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यों, पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमाण और मौके की स्थितियों को स्पष्ट देखने के बाद न्यायालय को यह स्वीकार करने में समस्या नहीं आई कि वास्तव में भोजशाला हिंदुओं के धर्म और ज्ञान का ही स्थल था।

वस्तुतः मध्य भारत पर 1010 से 1055 तक शासन करने वाले परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने 1034 में धारानगरी में एक विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सरस्वती सदन के नाम से विख्यात विश्वविद्यालय उस काल में संस्कृत, प्राकृत, दर्शन, व्याकरण और वेदों की शिक्षा का बड़ा केंद्र था, जिसे विद्या की काशी भी कहा जाता था। यह संस्थान नालंदा और तक्षशिला की समृद्ध परंपरा का हिस्सा था, जहां दुनिया भर से छात्र आते थे। इसी परिसर में राजा भोज ने 1035 में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां वाग्देवी (सरस्वती) की एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित करवाई। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने धार पर हमला किया, परमार वंश की पराजय हुई, सरस्वती सदन यानी भोजशाला के बड़े हिस्से को ध्वस्त करने की शुरुआत हुई, जो आगे भी जारी रही। 1401 से 1514 के बीच दिलावर खान और महमूद खिलजी द्वितीय ने मंदिर के अवशेषों से ही परिसर को मस्जिद में बदलने की कोशिश की। परिसर के बाहर एक मकबरा बनाया गया, जिसे कमाल मौलाना से जोड़ा गया, जबकि रिकार्ड बताते हैं कि मौलाना की मृत्यु भोजशाला परिसर को मस्जिद में बदलने से दो सदी पहले ही हो चुकी थी। अंग्रेजों ने इसकी खोदाई करवाई और उसमें मिली सरस्वती देवी की मूर्ति साथ ले गए, जो ब्रिटिश म्यूजियम में है।

भोजशाला के साथ न्याय में लग गए हजार वर्ष। फाइल

अंग्रेजी राज से ही भोजशाला में पूजा को लेकर संघर्ष हुए और स्वतंत्रता के बाद कर्फ्यू तक की नौबत आई। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने बीच का रास्ता निकालते हुए हिंदुओं को हर मंगलवार पूजा करने और मुस्लिमों को हर शुक्रवार नमाज की इजाजत दी। हिंदू फ्रंट फार जस्टिस सहित अन्य याचिकाओं पर न्यायालय ने मार्च, 2024 को एएसआइ को परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। उसने जुलाई, 2024 को 2000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट पेश की। न्यायालय में मस्जिद के पक्षकारों ने इसे खंडित करने के लिए सर्वेक्षण के तरीके, उसकी वैज्ञानिकता, टीम के सदस्यों, मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति आदि सारे तर्क दिए, जो तथ्यों के विरुद्ध थे। एएसआइ ने बताया कि सर्वेक्षण की वैज्ञानिक प्रक्रिया में तीन मुस्लिम जानकारों के साथ सर्वेक्षण के दौरान इस समुदाय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। कोई भी जाकर देख सकता है कि भोजशाला के स्तंभों पर देवी-देवताओं की मूर्तियां, संस्कृत के श्लोक, दीवारों पर लगी शिलाओं पर संस्कृत व्याकरण, संज्ञाएं, क्रियाएं उत्कीर्ण हैं। जो स्थान कालिदास, बाणभट्ट और भवभूति जैसे विद्वानों की महान परंपरा का केंद्र रहा हो, उसे पूरी तरह नकारने की कोशिश होती रही।

प्रश्न है कि मुस्लिम पक्षकार हठधर्मिता पर क्यों अड़ते हैं? वे आम मुसलमानों में यह भाव क्यों पैदा करते हैं कि न्यायालय, हिंदू संगठन, सरकारें जानबूझकर मुसलमानों की मस्जिदें, मकबरे आदि छीन रही हैं और भारत में इस्लाम के अस्तित्व पर खतरा है? सच इसके विपरीत है। जो स्थिति भोजशाला की है, वैसी ही अनेक विवादित स्थलों के संदर्भ में है। दरअसल मंदिरों को ध्वस्त करने या उन्हें मस्जिद में बदलते समय ज्यादातर को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। अनेक जगह उनके स्तंभ ही इस्तेमाल किए गए। अयोध्या और उसके बाद भोजशाला के फैसलों ने आने वाले मामलों को भी आधार दे दिया है। यह सच्चाई मुस्लिम समाज के लोगों को समझनी होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अहिंसा

अहिंसा को धर्मों का मूल बताया गया है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी मतावलंबियों ने हिंसा को महापाप माना है। मानव के प्रति मानव द्वारा हिंसा तो सभी धर्म ग्रंथों में अस्वीकार्य है। किसी भी विद्वान एवं मनीषी ने हिंसा का समर्थन नहीं किया है, वह चाहे शारीरिक हिंसा हो या मानसिक। पारिवारिक हिंसा हो या सामाजिक हिंसा, यह मानव सभ्यता के विरुद्ध है। देश के भीतर या बाहर, यह एक आपराधिक कृत्य है। नैतिकता के विपरीत इसका मूल्यांकन करने वाले घने अंधकार में भटके हुए हैं। ऐसे भ्रमित लोगों का वैचारिक आधार शून्य है। अहिंसा देव गुण है, तो हिंसा रक्ष संस्कृति है। हिंसा कभी कोई सही मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकती, यह असत्य और भय की नींव पर खड़ा परिणामी दुख है। हिंसा पापयुक्त तामसी रोग है। यह अप्राकृतिक कायरता के कारण उत्पन्न विषाक्त दोष है, अशुद्ध भावना जनित कुत्सित प्रयास है।

बच्चों के प्रति अनुचित व्यवहार, महिलाओं का शोषण एवं संताप, वृद्धों के प्रति अन्याय-पारिवारिक हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत असामाजिक कृत्य है। मनोविज्ञानी कहते हैं कि अबोध एवं निर्दोष जनों को हिंसा का शिकार बनाना अमानवीय कार्य है। जिस देश में हिंसा विभिन्न रूपों में व्याप्त हो, उसका पतन सुनिश्चित है। पृथ्वी पर अनेक देशों का अस्तित्व इसी हिंसा की काली छाया में विलुप्त हो गया। जबकि अहिंसा ने समय-समय पर हिंसा को परास्त या नियंत्रित किया। हिंसा का नकारात्मक प्रभाव अधिक समय तक ठहर नहीं सका।

रावण, कंस एवं दुर्योधन हिंसा की मूर्ति थे, पापी थे। वे अपने पापों के कारण मिट गए, अत्याचारों के कारण श्रापित हुए। फिर भी, कोई सुधार युगों तक नहीं हो सका। हिंसा एक राक्षस के समान चट्टान बन कर मानवता का मार्ग रोके हुए है। दैवीय गुणों से हिंसा के दैत्य को पराजित किया जा सकता है।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

वनों का दायरा बढ़ाने में पिछड़ती दुनिया

सुधीर कुमार

वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2026 के अनुरूप वनावरण का दायरा बढ़ाने की प्रगति संतोषजनक नहीं हैं

पिछले लंबे समय से समूचे विश्व में वनावरण को बढ़ाने की कवायद की जा रही है। अनेक देश इस दिशा में अपने-अपने स्तर पर प्रयासों में जुटे हुए हैं। परंतु स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2026 जारी किया है, जिसके अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वनावरण के दायरे को बढ़ाने और उपलब्ध वनों को सहेजने की दिशा में दुनिया की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने वन संबंधी रणनीतिक योजना (2017-2030) को 27 अप्रैल, 2017 को अपनाया था, जिसके तहत छह वैश्विक वन लक्ष्य और इससे संबंधित 26 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसमें 2030 तक दुनियाभर में जंगल का दायरा तीन प्रतिशत तक बढ़ाना था, जो फ्रांस के क्षेत्रफल के दोगुना से भी अधिक होता। हालांकि रिपोर्ट देखकर हैरानी होती है कि विगत नौ वर्षों में हम उक्त लक्ष्यों में से केवल सात ही पूरी तरह हासिल कर पाए हैं। चिंताजनक यह कि इनमें से 17 लक्ष्यों को आंशिक रूप से हासिल किया जा सका है, जबकि दो लक्ष्य तो ऐसे हैं, जो पटरी से पूरी तरह उतर चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि दुनिया के जिन 48 देशों में कुल वनों का 51 प्रतिशत हिस्सा आच्छादित है, वहां 2015 से 2025 के बीच वैश्विक वन क्षेत्र में चार करोड़ हेक्टेयर से अधिक की गिरावट देखी गई है। अब जबकि निर्धारित लक्ष्य वर्ष तक पहुंचने में महज चार वर्ष का समय ही शेष है, तब यह सवाल जायज हो उठता है कि वनों के संरक्षण की दिशा में दुनिया इतनी सुस्त क्यों है? जबकि पर्याप्त क्षेत्रफल पर स्वस्थ वनों का होना स्वच्छ पर्यावरण, जीवन और मानवता का आधार समझा जाता है।

वस्तुतः वनों का होना केवल सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण, खाद्य व आजीविका की सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, आक्सीजन की निरंतरता, मृदा संरक्षण, कार्बन अवशोषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1.6 अरब लोगों के लिए जंगल भोजन, पानी, ईंधन और रोजगार के स्रोत हैं। हालांकि बढ़ते शहरीकरण, उद्योगीकरण, भूमि उपयोग में बदलाव, दावानल, वनोन्मूलन और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण वनों का अस्तित्व खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक वन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वनों की कटाई को रोकने, सतत वन प्रबंधन पर जोर देने, प्रशासन एवं कानून प्रवर्तन को मजबूत करने का आह्वान किया है। समझना होगा कि वनों को सहेजना मानवता के अस्तित्व को सहेजने से कम नहीं है। देश के अनेक हिस्सों में भीषण गर्मी जारी है। इससे राहत प्रदान करने में वनों की बड़ी भूमिका हो सकती है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

समग्रता में विचार आवश्यक

'जेल और जमानत' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूएपीए जैसे गंभीर कानून के मामलों में 'जेल अपवाद और बेल नियम' के सिद्धांत को लेकर दिए गए अलग-अलग फैसलों ने नई बहस को जन्म दिया है। एक ओर न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानते हुए अनिश्चितकाल तक किसी को जेल में रखने के खिलाफ है, वहीं दूसरी ओर गंभीर अपराधों और आतंकवाद से जुड़े मामलों में समाज की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण चिंता है। इस संदर्भ में हर मामले को एक ही दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता तथा आरोपित के आचरण को ध्यान में रखते हुए ही जमानत पर निर्णय होना चाहिए। कई बार यह देखा गया है कि जमानत मिलने के बाद आरोपित पुनः आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो जाता है, जिससे न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब भी एक बड़ी समस्या है। अनेक मामलों में वर्षों तक ट्रायल पूरा नहीं हो पाता है। यह स्थिति न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सुनवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करे।

himanshushekhar.mca@gmail.com

न्याय व्यवस्था में खामियां

संपादकीय लेख 'जेल और जमानत' जेल अपवाद और जमानत नियम की समीक्षा करते हुए इसके

मेलबाक्स

दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की जरूरत को रेखांकित करता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में 'जेल अपवाद है और जमानत नियम' सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध सिद्ध होने से पहले किसी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक रूप से जेल में न रखा जाए। किंतु वर्तमान में इस व्यवस्था की कई कमियां सामने आ रही हैं। एक ओर गरीब और कमजोर वर्ग के लोग मामूली अपराधों में भी लंबे समय तक जेल में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रभावशाली और आर्थिक रूप से सक्षम लोग गंभीर मामलों में भी आसानी से जमानत प्राप्त कर लेते हैं। कई बार हत्या, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध या प्रभावशाली अपराधियों द्वारा जमानत का दुरुपयोग कर गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने तथा समाज में भय का वातावरण बनाने की घटनाएं भी सामने आती हैं। अतः आवश्यक है कि जमानत देते समय अपराध की गंभीरता, आरोपी का प्रभाव, पीड़ित की सुरक्षा तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का संतुलित मूल्यांकन किया जाए। साथ ही, गरीबों के लिए सरल जमानत व्यवस्था, त्वरित सुनवाई तथा कठोर मामलों (जैसे हत्या, आतंक और तस्करी) में सख्त निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू की जानी चाहिए। यदि समय रहते सुधार नहीं किए गए, तो 'जमानत नियम' का सिद्धांत न्याय और सुरक्षा दोनों के लिए चुनौती बन सकता है।

मोहित सोनी, कुक्षी, मध्य प्रदेश

भारत-स्वीडन संबंध

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का लेख "सहयोग की नई भावना" शीर्षक तहत पढ़ा। हमारा देश दुनिया के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध मधुर करने की कोशिश करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि देश के विकास के लिए दूसरे देशों के साथ रिश्ते मजबूत होने से व्यापार का दायरा बढ़ता है जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिलती है। हमारे देश के स्वीडन के साथ संबंध ठीक-ठाक ही रहे हैं, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन की यात्रा और इस दौरान दोनों देशों के आपसी व्यापार और अन्य मुद्दों पर जो बातचीत हुई उससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। लेकिन दुनिया के सभी देशों को इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि कहीं भी युद्ध न हो, आतंकवाद पालक देशों की मदद न की जाए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

127 विमान औसतन खरीदता था चीन प्रत्येक वर्ष, 2005 से 2017 के बीच, वहीं 2018 के बाद से यह संख्या घटकर केवल छह रह गई है। इसे अमेरिका और चीन के व्यापारिक एवं भू-राजनीतिक तनावों का परिणाम कहा जा सकता है।

आजकल

महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का नतीजा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बीजिंग यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वैश्विक संकट के दौर में दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत कई वैश्विक चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकती थी, लेकिन इनके बीच कोई उल्लेखनीय समझौता नहीं हुआ। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की यह यात्रा नवंबर, 2017 के बाद पहली यात्रा है। भारत के लिए यह बेहतर होता यदि दोनों देशों के नेता अमेरिका-ईरान संघर्ष को रोकने पर पूर्ण सहमति बना लेते। वस्तुत: होर्मुज समुद्री मार्ग में बाधा का दुष्प्रभाव भारत पर अपेक्षाकृत कहीं अधिक है, लिहाजा भारत के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मसला है

राहुल पाण्डेय
रिसर्च एसोसिएट, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली

बीते सप्ताह अमेरिकी और चीन के राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात में कोई विशेष समझौता नहीं हो सका। फाइल

अमेरिका और चीन वर्तमान में विश्व राजनीति के दो ध्रुवों पर हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का चीन की यात्रा पर जाना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर के बाद जो बाइडन अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जो अमेरिका और चीन के बीच सहज हुए रिश्तों के बावजूद अपने कार्यकाल में चीन यात्रा पर नहीं गए। हालांकि दोनों देशों के प्रमुख नेताओं की वार्ता कई अन्य मंचों पर होती रही है जिसमें पिछले साल 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुई थी। मूल रूप से यह बैठक मार्च में होनी थी, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध की विभीषिका ने इसे स्थगित करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे महाशक्ति प्रतिस्पर्धा की वजह से दुनिया के कई महत्वपूर्ण शक्ति संपन्न देश स्वयं को अलग थलग पा रहे हैं जिस कारण से वैश्विक चुनौतियों को हल करने पर कोई निर्णय ले पाना संभव नहीं हो पा रहा।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका और चीन के बीच संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद स्तंभ हमेशा से व्यापार रहा है। ट्रंप के व्हाइट हाउस में दोबारा आगमन के बाद व्यापारिक टकराव एक नए स्तर पर पहुंच गया है जिसमें पिछले साल अप्रैल में 'लिबरेशन डे' कर लगाकर पूरी दुनिया के बाजार में हाहाकार मचा दिया था और चीन पर लगभग 146 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिया था और इसके जवाब में चीन ने भी लगभग 132 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया था। हालांकि इस साल फरवरी में अमेरिकी उच्च न्यायालय ने उस फैसले को गैरकानूनी करार दिया। पिछले साल दक्षिण कोरिया के बुसान में अक्टूबर में हुए समझौते के बाद दोनों ने टैरिफ को कम किया था, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच कई अहम विषयों पर गहरे मतभेद खुलकर सामने आते रहते हैं।

चीन के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर प्रस्तावित प्रतिबंधों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चिंता पैदा कर दी है। दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन उन व्यापारिक प्रथाओं की जांच कर रहा है जो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस आर्थिक खींचतान के बीच फेंटानिल तस्करी को रोकने के लिए चीन का सहयोग एक सकारात्मक संकेत के रूप में उभरा है। नशीले पदार्थों के खिलाफ इस संयुक्त अभियान ने यह दिखाया है कि गहरी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद, मानवीय और सामाजिक मुद्दों पर सहयोग की गुंजाइश बनी हुई है।

चीनी निवेश के प्रति सतर्कता : व्यापारिक वार्ता के समानांतर, निवेश और खरीद प्रतिबद्धताओं का मुद्दा भी इस शिखर सम्मेलन का एक बड़ा विषय था, लेकिन सिवाय एक बोर्ड आफ ट्रेड और बोर्ड आफ इन्वेस्ट बनाकर दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश से जुड़े मतभेदों को काफी हद तक कम करना है। दोनों देश एक दूसरे पर काफी हद तक निर्भर हैं। ट्रंप की रणनीति हमेशा से लेन-देन पर आधारित रही है। जापान और दक्षिण कोरिया की तरह, अब चीन पर भी यह दबाव है कि वह अमेरिका से बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादों, विमानों और ऊर्जा की खरीद करे। वाशिंगटन के रणनीतिकार इसे फाइव बी (बोइंग, बीन्स, बीफ, बोर्ड आफ ट्रेड, बोर्ड आफ इनवेस्टमेंट) के ढांचे के भीतर देख रहे हैं। हालांकि व्यापारिक प्रवाह को औपचारिक रूप देने के लिए बोर्ड आफ ट्रेड जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन निवेश के मोर्चे पर प्रगति अभी भी धीमी है। अमेरिका में चीनी निवेश को लेकर वाशिंगटन अभी सतर्क है और किसी बड़े नए कार्यक्रम की योजना नजर नहीं आती। यह आर्थिक अविश्वास ही है जो दोनों देशों के बीच एक स्थायी और स्थिर संबंध की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है।

दोनों देशों के बीच समझौते के मामले में अमेरिकी कृषि और बोइंग विमान लेने के संकेत दिए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि चीन की तरफ से हुई नहीं है। वैसे अमेरिकी व्हाइट हाउस ने चीन द्वारा 200 विमानों की खरीद की बात कही है, लेकिन चीन ने किसी तरह के विमान खरीदने की बात नहीं की है, परंतु इतना संकेत दिया है कि इन विषयों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। 2005 से 2017 के बीच जहां चीन हर वर्ष 127 विमान खरीदता था, वहीं 2018 के बाद यह संख्या घटकर मात्र छह रह गई है। यह गिरावट अमेरिका-चीन के बढ़ते व्यापारिक और भू-राजनीतिक तनावों का परिणाम थी।

कृषि क्षेत्र में भी यह समझौता महत्वपूर्ण है। चीन ने 2026 से 2028 तक हर वर्ष कम से कम 17 अरब डालर के अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने की बात कही है। इससे अमेरिकी किसानों को राहत मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब ट्रंप को महंगाई और घरेलू असंतोष के कारण राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि यह समझौता आगामी अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर, चीन ने अमेरिकी बीफ आयात पर लगी कई पाबंदियां हटाने की बात पर भी चर्चा की है, लेकिन किसी तरह के एक सटीक नंबर देने की बात नहीं की है।

ईरान संकट का प्रभाव : वर्तमान में अमेरिका-चीन संबंधों के बीच सबसे बड़ा और नया भू-राजनीतिक कांटा ईरान युद्ध है। वाशिंगटन और बीजिंग के बीच तनाव का यह नया केंद्र केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि सामरिक और ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ईरान, चीन का एक प्रमुख ऊर्जा भागीदार है और बीजिंग लंबे समय से तेहरान को राजनयिक और आर्थिक कवच प्रदान करता रहा है। युद्ध से पहले चीन ईरान का 90 प्रतिशत तेल खरीदता था और इसी कारण ईरान काफी हद तक चीन पर निर्भर रहा है, लेकिन होर्मुज के बंद होने से और अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के कारण यह भी बंद हो गया है।

इस बीच ट्रंप पर घरेलू स्तर पर इस युद्ध को समाप्त करने का भारी दबाव है, क्योंकि इसने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए आरोप कि उसने ईरान को घातक युद्ध सामग्री प्रदान की है, उसने आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि बीजिंग ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान को होने वाला चीनी निर्यात और तेल की खरीद सीधे तौर पर संघर्ष को लंबा खींच रही है। बीजिंग ने अपनी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों के विरुद्ध खड़े होने का आदेश देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप शी चिनफिंग को ईरान पर दबाव बनाने के लिए राजी कर पाते हैं या यह मुद्दा संबंधों में और अधिक कड़वाहट पैदा करेगा। ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति ने ईरान पर दबाव बनाकर होर्मुज समुद्री मार्ग को खोलने की बात की है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान संकट बातचीत से ही हल किया जा सकता है।

तकनीकी क्षेत्र में नेतृत्व की होड़ ने एक 'डिजिटल शीत युद्ध' जैसी स्थिति पैदा कर दी है। यह भी समझा जाना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप्स अब केवल व्यापार का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे सैन्य और रणनीतिक श्रेष्ठता के मानक बन गए हैं। लेकिन इन विषयों पर भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया। अमेरिका को इस बात की गहरी चिंता है कि चीन उसकी उन्नत तकनीक का उपयोग करके कम लागत पर समान प्रणालियां विकसित कर रहा है। लिहाजा वह इस ओर भी सतर्कता बरत रहा है।

अमेरिका-चीन की निकटता का भारत पर प्रभाव

इस जटिल अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका और चीन के बीच का यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए अवसरों और चुनौतियों का एक मिला-जुला पिटारा है। यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध और अधिक तीव्र होता है, तो भारत 'चाइना प्लस वन' रणनीति के तहत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।

तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए प्रतिबंध भारतीय स्टार्टअप्स और आइटी क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं खोल सकते हैं। हालांकि, ईरान युद्ध और उसके कारण तेल की कीमतों में अस्थिरता भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए संतुलन बनाए रखना होगा। इसके अलावा, यदि अमेरिका और चीन के बीच ताइवान या दक्षिण चीन सागर को लेकर तनाव बढ़ता है, तो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर और अधिक बढ़ जाएगी। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इन दो महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के बीच अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' को हर हाल में बनाए रखे।

दोनों देशों के नेताओं के बीच यह मुलाकात एक ऐसे समय में हुई है, जब दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। जहां एक ओर आर्थिक लाभ के लिए सहयोग की मजबूरी है, वहीं दूसरी ओर वैचारिक एवं सामरिक प्रभुत्व की जंग है। ईरान युद्ध और ऊर्जा संकट ने इस कूटनीति को और अधिक अनिश्चित बना दिया है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात को किसी बड़े समझौते के परिणाम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के नेताओं के बीच बातचीत के रास्ते का खुला होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह महत्वपूर्ण होता कि दोनों बड़े देश ईरान पर दबाव बनाएं, ताकि युद्ध को रोका जा सके, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा की समस्याएं बड़े देशों के बीच कूटनीतिक समझौते से ही हो सकती हैं।

(राहुल पाण्डेय)

खरी-खरी

महंगाई के विकल्प

निर्मल गुप्त

अपने प्रिय डागी को लेकर मार्निंग वाक के लिए निकले खन्ना साहब ने बड़ा अहम सवाल उठाया कि कब तक ये महंगाई बढ़ती रहेगी। यह सवाल उन्होंने तब उठाया जब एक चाकलेट बेचने वाले डीलर का मैसेज आया कि तत्काल प्रभाव से उनके लाडले डागी की मनपसंद चाकलेट 38 प्रतिशत महंगी हो गई है।

इस संदेश को पा वह आगबबूला टाइप हो गए। डागी ने मालिक की बेचैनी पर आदतन थोड़ी कूंकू की और अपनी दुम इस अदा से लहराई जैसे वह किसी कार का वाइपर हो। वह बोल तो नहीं पाया पर उसने संभवतः यह कहना चाहा कि दाम बढ़ते हैं तो बढ़ें। हमें क्या। सानू की। मालिक की पेंशन भी तो हाल ही में बढ़ी है। बढ़ोतरी कुदरत का नियम है। एक के बाद दूसरी चीज के दाम बढ़ते ही हैं। लेकिन अपनी किसी प्रिय वस्तु के दाम इस तरह से बढ़ जाएं तो यह बात जरा खल जाती है।

इसी बीच खन्ना जी को उनके किसी सहकर्मी ने बताया कि दूध की कीमत भी बढ़ गई। उसकी बात सुन उन्होंने आदतन अपने कान फड़फड़ाए और कहा कि बढ़ते हैं तो बढ़ें, क्या फर्क पड़ता है। उनके मित्र ने तुरंत पूरक सूचना दी कि एक ब्रांड ने दो रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए तो दूसरे ने तीन रुपये प्रति लीटर। यह सुन खन्ना जी बोले, 'हम अब डिब्बाबंद हाई प्रोटीन मिल्क का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। जनता को चाहिए कि महंगाई को लेकर चिल्लपों मचाने के बजाय उसका कोई हेल्दी विकल्प खोज ले।'

उनकी यह बात सुन सहकर्मी बड़ी देर तक मन ही मन हंसता रहा। मौखिक बातचीत के दौरान इमोजी चिपकाने की तकनीक अभी बाजार में आई नहीं है। यदि ऐसा कोई विकल्प होता तो वह फीलिंग थ्रिल्ड वाली इमोजी खन्ना जी की तस्वीर सहित उनके कथोपकथन के साथ चस्पा कर झोली भर भर व्यू बटोर ले जाता।

खन्ना जी बढ़ती हुई महंगाई से चिंतित तो नहीं पर बेचैन थे कि डागी वाली चौकलेट 38 प्रतिशत महंगी हुई, हमारा वाला दूध केवल दो-तीन रुपये लीटर। बड़ी बेइंसाफी है यह तो। इस सरकार को तो ढंग से महंगाई तक बढ़ाना भी नहीं आता।

पोस्ट

ऐसा लगता है कि अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर माडल नाकामी की ओर है। फलता से तृणमूल प्रत्याशी जहांगीर खान ने राज्य सरकार के विशेष पैकेज का स्वागत करते हुए चुनाव लड़ने से ही इन्कार कर दिया। हालांकि स्पष्ट नहीं कि यह उनका फैसला है या अभिषेक बनर्जी का?
पंकज झा@pankajjha_

आप किसी राजनयिक से कड़े सवाल पूछ सकते हैं तो यह पत्रकारिता में गिना जाएगा। राजनयिक अपने तरीके से उस सवाल का जवाब दे तो यह कूटनीति कही जाएगी, लेकिन अगर आप राजनयिक को लगातार परेशान करने पर अड़े हों और बायकाट पर उतर आएं तो यह पत्रकारिता नहीं, बल्कि एक्टिविज्म है।
हैप्पीमान जैकब@HappymonJacob

प्रधानमंत्री किसी भी देश की आधिकारिक यात्रा पर हों तो वहां वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दौरान सवाल पूछने के नाम पर चिल्लाना अपमान ही है। नार्वे में जो प्रयोग हुआ, उसकी आने वाले दिनों में पुनरावृत्ति होती दिखेगी। फर्जी सर्वेक्षणों और रिपोर्टों के माध्यम से माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा। शिवम शर्मा@shiva_m2912

उत्तराखंड डायरी

चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर कलह

रविंद्र बड़थ्वाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, उत्तराखंड

समूह से जुदा दिखते हरीश रावत। फाइल

उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन सामूहिक नेतृत्व बनाम गुटीय खींचतान के नए फेर में उलझ गया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डा. हरक सिंह रावत की चौकड़ी सामूहिक नेतृत्व के रूप में अगले विधानसभा चुनाव के लिए मोर्चा संभाले हुए है। दूसरी ओर, इस चौकड़ी से अलग पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उर्फ हरदा हैं। अभी तक हरदा इस चौकड़ी से अलग राह पर चल रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर डेढ़ माह के भीतर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा उत्तराखंड का दो बार दौरा कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने चौकड़ी को साथ रखा। एकजुटता को लेकर प्रभारी के संदेश और नसीहत के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी हिलाने की ऐसी कहानी सामने आई, जिसने पार्टी को भी चिंता में डाल दिया है। ऐसे में सामूहिक नेतृत्व को आगे बढ़ाने का पार्टी हाईकमान का प्रयोग कामयाब रहेगा या इसकी राह मुश्किलों से भरी रहने वाली है, इस पर कयास लगने शुरू हो गए हैं।

उत्तराखंड की सत्ता में वापसी कांग्रेस के लिए अस्तित्व से जुड़कर करो या मरो का रूप ले चुकी है। अगले वर्ष होने वाला विधानसभा चुनाव यह भी तय करेगा कि लगातार तीसरी बार हार का सिलसिला टूटेगा या नहीं। इसमें कांग्रेस का सत्ताधारी दल भाजपा से सीधा मुकाबला होना है। कांग्रेस का पूरा दारोमदार एंटी इनकंबेंसी पर है। इसके लिए नैरेटिव सेट करने की जी-तोड़ कोशिशें भी हो रही हैं। अति उत्साह में कभी-कभी यह दांव उल्टा भी पड़ रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के अलावा महिलाओं के खिलाफ होने वाली अन्य आपराधिक वारदातों, भर्ती प्रक्रिया में शुचिता आदि मुद्दों को लेकर पार्टी ने कई बार आक्रामक तेवर अपनाए। हाल ही में चंपावत में नाबालिग के उत्पीड़न के मामले को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यह उलटा पड़ गया। पुलिस जांच में कांग्रेस के स्थानीय नेता का नाम आते ही पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा। इसी प्रकार ऊधम सिंह नगर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे की नाराजगी को भुनाने की कोशिशें भी परवान नहीं चढ़ पाईं। कुल मिलाकर कांग्रेस अभी तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं बना पाई है, जिसे चुनाव तक खींचा जा सके।

मुद्दों की इस कश्मकश के बीच पार्टी एकजुट और लयबद्ध भी नजर नहीं आ रही है। संगठन में आपसी खींचतान के चलते पार्टी चुनावी मोड में भी आती नहीं दिख रही है। केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश संगठन के नेताओं के बीच चल रहे अहं के इस टकराव को टालने की कोशिशें कर रहा है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के अब तक हुए दो दौरे चुनावी तैयारियों से ज्यादा संगठन को एकजुट करने की ही कवायद मानी जा रही है। इन सबके बीच हरीश रावत स्वयं को पार्टी में हाशिये पर महसूस कर रहे हैं। अगले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं दी गई है। सामूहिक नेतृत्व की चौकड़ी के लिए जिन चेहरों को आगे किया गया है, उन्हें लेकर हरीश रावत पहले भी न तो आश्वस्त रहे और न ही सहज।

पिछले घटनाक्रमों पर नजर डालें तो यह साफ है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह या फिर पूर्व मंत्री डा. हरक सिंह रावत के साथ उनकी पटरी शायद ही कभी बैठी हो। वहीं, गढ़वाल में भाजपा के किले में सेंधमारी के लिए गणेश गोदियाल की डा. हरक सिंह रावत के साथ पहलकदमी पार्टी के अंदर एक नए गठजोड़ की झलक भी दिखा रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भले कभी हरदा कैंप के माने जाते थे, लेकिन इस रिश्ते पर समय के साथ परत जमती चली गई।

प्रदेश प्रभारी सैलजा के दौरे से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के नाम पर ठगी का मामला उजागर हुआ। उसने पार्टी के अंदर अविश्वास के वातावरण को और गहरा कर दिया है। यह ठीक है कि मामला ठगी का निकला, लेकिन इसने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश संगठन में भीतर ही भीतर काफी कुछ पक रहा है। इसे प्रदेश की चौकड़ी को ही नहीं, बल्कि हाईकमान के लिए भी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इस कांड के उजागर होने के बाद प्रदेश या केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी जुबान बंद रखना ही बेहतर माना। ऐसे में यह प्रश्न अनसुलझा ही रहा गया कि आखिर ठगी के प्रकरण का सूत्रधार कौन या कौन-कौन थे?

दूसरी ओर सत्तारूढ़ भाजपा की धामी सरकार समान नागरिक संहिता, मदरसा बोर्ड समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा को प्राधिकरण के अंतर्गत लाने, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के जरिये वक्फ की बढ़ती संपत्तियों को नियंत्रित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर देशभर में चर्चा में है। स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ भाजपा इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अंतरकलह और अविश्वास के असहज माहौल से उबरने की कोशिश कर रही कांग्रेस चुनावी मैदान में प्रतिद्वंद्वी भाजपा की मजबूत सांगठनिक एकजुटता और आक्रामकता का किस तरह मुकाबला करेगी!

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या बीसीसीआइ को आरटीआइ के दायरे से बाहर रखने का फैसला सही है?

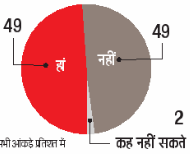

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

रिषभ पंत को वनडे टीम से बाहर और टेस्ट की उपकप्तानी से हटाने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

नाम बदलकर गलतियां जो तुम रहे सुधार,
कर दो पूरे पाक को 'भारत' ही इक बार।
'भारत' ही इक बार रही जो 'लव' की नगरी,
बोलेगी ही राम वहां की झारी-झारी।
गलती से लाहौर पाक में गया फिसलकर,
करिए 'लव पुर' आप शीघ्र ही नाम बदलकर!
-ओम प्रकाश तिवारी

मंथन

कैलोरी भरपूर, पोषण कमजोर

आत्मनिर्भर होते भारत में भोजन में अनाज और वसा की मात्रा बढ़ रही है, परंतु पोषण विविधता की भारी कमी है। इसलिए हमें कैलोरी के साथ ही पोषण पर भी ध्यान देना होगा

सुहानी गुप्ता
रिसर्च एनालिस्ट, सीईईडब्ल्यू
अपूर्व खंडेलवाल
फेलो, सीईईडब्ल्यू

जैसा अन्न, वैसा मन- कहावत भोजन की गुणवत्ता का सेहत से रिश्ता बताती है। हमारे सामने आज भी यह सवाल है कि भारतीय वास्तव में क्या खा रहे हैं? जैसे-जैसे गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं, देश के सामने एक कड़वा सच यह है कि हमने औसतन पेट भर खाने की समस्या तो सुलझा ली है, लेकिन पोषण की चुनौती अभी बाकी है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी खपत अब 2,200 किलोकैलोरी से अधिक है, जो जरूरी औसत कैलोरी खपत से अधिक है। इसके बावजूद भारत के सामने तिहरी चुनौती है, पांच वर्ष से कम उम्र का प्रत्येक तीसरा बच्चा बौनेपन का शिकार है, प्रत्येक चार में से एक वयस्क मोटापे से जूझ रहा है, प्रत्येक नौ में से एक वयस्क मधुमेह से पीड़ित है, और प्रत्येक सात में से एक व्यक्ति प्री-डायबिटिक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का आकलन बताता है कि भारत में बीमारियों के बोझ में अस्वस्थकर खानपान की हिस्सेदारी 56 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के नए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2023-24) पर आधारित काउंसिल आन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) का विश्लेषण बताता है कि भारतीयों के लिए पोषक आहार में विविधता आज भी सीमित है। भोजन में औसत कैलोरी और प्रोटीन का लगभग आधा हिस्सा केवल चावल और गेहूं से आता है। यह दालों, मोटे अनाजों, डेयरी, अंडे, मछली, मांस, फल और सब्जियों जैसे पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करने का सुझाव देने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यूट्रिशन (एनआइएन) के सुझाए मानकों से लगभग डेढ़ गुना अधिक है। भोजन में अनाज आवश्यक है, लेकिन उसमें ऐसे प्रमुख अमीनो एसिड की कमी होती है, जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा दालों, दूध से बने उत्पादों, अंडे या मांस से मिलने वाले प्रोटीन की तुलना में अनाज के प्रोटीन को पचाने में हमारे शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब हमारी थाली में अनाज की अधिकता हो जाती है, तब यह सूक्ष्म पोषक तत्वों और डाइटरी फाइबर की जगह छीन लेता है। इससे आहार की संपूर्ण गुणवत्ता कमजोर हो जाती है।

भोजन में पोषक तत्वों वाली खाद्य सामग्री की बहुत कमी है। भारतीय घरों में प्रतिदिन कैलोरी की खुराक में फल और सब्जियां दसवें हिस्से से भी कम है। यह मुश्किल से आधा कटोरी फल और एक चौथाई कटोरी से कम हरी पत्तेदार सब्जियों के बराबर होता है, जबकि संतुलित भोजन में लगभग एक-एक कटोरी फल और हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। प्रतिदिन दालों का औसत सेवन एक कटोरी से भी कम है, जबकि यह तीन कटोरी होना चाहिए।

भोजन में एकरसता होना समस्या को और गहरा कर देता है। अक्सर सब्जियों का सेवन आलू और प्याज तक, जबकि दालों का सेवन सिर्फ एक या दो किस्मों तक सिमटा रहता है। इससे शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल्स और फाइबर नहीं मिलते, जो पाचन स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं और डायबिटीज व हृदय रोग का जोखिम घटाते हैं। इसकी कीमत डायबिटीज, हाइ ब्लड प्रेशर, एनीमिया, मोटापा और बाल कुपोषण के बढ़ते मामलों के रूप में हम पहले से देख रहे हैं। इसलिए हमें अपने खानपान को बदलना चाहिए।

सबसे पहले, विविधतापूर्ण आहार को अपनाना चाहिए। वसा, नमक और चीनी के संयमित सेवन पर जोर देने की जरूरत है। सेहत और खानपान से जुड़ी सलाह और जानकारियां देने वाले मंच तेल, नमक और चीनी का सेवन घटाने के लिए 'किचन आडिट' और 'पोर्शन बेंचमार्क' (मात्रा के मानक) को बढ़ावा दे सकते हैं। पैकेज्ड खाने में छिपे वसा, चीनी और नमक को घटाने पर एफएसएसएआइ और एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से ध्यान देने की जरूरत है। पैकेट पर बहुत स्पष्ट लेबलिंग भी सेहतमंद विकल्पों के चुनाव को प्रोत्साहित कर सकती है।

भारत की खाद्य नीति को खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की दिशा में ले जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), आंगनवाड़ी राशन और स्कूलों के मध्याह्न भोजन में धीरे-धीरे दालों और मोटे अनाजों को शामिल करना चाहिए। उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के अनुरूप होना चाहिए, जबकि विविधतापूर्ण आहार की मांग को मजबूत किया जाना चाहिए।

हमारे खान-पान की विविधता तय करेगी कि भारत क्या उगाएगा। मोटे अनाजों, दालों और मौसमी सब्जियों से भरपूर थाली उन कृषि प्रणालियों की मदद करती है, जो पानी की खपत में किफायती और जलवायु के प्रति अधिक लचीली हैं। भारत के स्वास्थ्य और जलवायु संकट का असर पहले से हमारी थाली पर दिखाई दे रहा है। हम रोजाना जो खाएंगे, वही हमारे देश के भविष्य को आकार देगा।

(लेखकों के विचार निजी हैं)

2035 तक सात प्रतिशत की दर से बढ़ेगा पर्यटन क्षेत्र

नई दिल्ली: आनंद राठी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने ताजा रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि वर्ष 2035 तक भारत का यात्रा और पर्यटन क्षेत्र सात प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014-14 के दौरान घरेलू यात्राओं की संख्या 18.6 अरब तक पहुंच गई, जबकि विदेशी मुद्रा से होने वाली कमाई लगभग तीन गुना बढ़कर लगभग 18.8 लाख करोड़ रुपये हो गई। कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान यूरोप के सबसे अधिक लोगों ने भारत की यात्रा की है। (प्रेट्र)

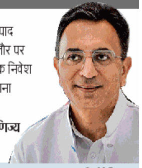

भारत को केवल उत्पाद बेचने की जगह के तौर पर नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक निवेश साझेदार के रूप में देखा जाना चाहिए।

– जितिन प्रसाद, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलो ग्राम)	डालर	क्रूड (प्रति बैरल)
75,200.85 ▼ 114.19	23,618 ▼ 31.95	₹ 1,63,600 ▲ ₹ 800	₹ 2,71,000 ▼ ₹ 5,000	₹ 96.70 ▲ 0.50	$ 110

एक नजर में

विस्तार पर 5,700 करोड़ का निवेश करेगी पेप्सिको

नई दिल्ली: खाद्य एवं पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी पेप्सिको वर्ष 2030 तक भारत में 5,700 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी के भारत एवं दक्षिण एशिया के सीईओ जागृत कोटेचा ने कहा कि खाद्य कारोबार की क्षमता विस्तार पर यह निवेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह निवेश खासतौर पर मध्य प्रदेश, असम और तमिलनाडु में किया जाएगा। कटेचा ने कहा कि भारत पेप्सिको के शीर्ष-13 बाजारों में से एक है और कंपनी यहां लगातार अपनी निवेश प्रतिबद्धता जारी रखे हुए हैं। (प्रेट्र)

पांच हजार रुपये घटी चांदी, सोना बढ़ा

नई दिल्ली: कमजोर औद्योगिक मांग और वैश्विक बाजारों में नरमी के चलते मंगलवार को राजधानी दिल्ली में चांदी के मूल्य में पांच हजार रुपये की गिरावट दर्ज की गई। आल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, अब दिल्ली में चांदी का मूल्य 2.71 लाख रुपये किलोग्राम रह गया है। हालांकि, अमेरिका-ईरान वार्ता में सफलता के संकेतों से महंगाई से जुड़ी चिंताएं कम होने से सोने के मूल्य में 800 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई और अब यह 1,63,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। (प्रेट्र)

बीपीसीएल का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में स्थिर रहा

नई दिल्ली: भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) का शुद्ध लाभ 2025-26 की मार्च तिमाही में 3191.49 करोड़ रुपये पर स्थिर रहा। वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में कंपनी को 3,214.06 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। वहीं दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में लाभ 7,545.27 करोड़ रुपये था। मार्च तिमाही में कंपनी की आय 1.34 लाख करोड़ रुपये रही। 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ 75 प्रतिशत बढ़कर 23,303.22 करोड़ रहा जो एक साल पहले 13,275.26 करोड़ रुपये था। आलोच्य वित्त वर्ष में आय 5.22 लाख करोड़ रुपये रही। (प्रेट्र)

मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाकर विदेशी मुद्रा बचाएगी सरकार

दो दर्जन से अधिक उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम ला सकता है केंद्र

राजीव कुमार • जागरण

- मशीनरी, केमिकल्स, प्लास्टिक व इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर में मैन्यूफैक्चरिंग की बड़ी गुंजाइश
- नए बूस्टर डोज की तैयारी, केंद्र और राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त औद्योगिक पार्क लगेंगे

नई दिल्ली: कोरोना काल की तरह पश्चिम एशिया संकट को भी अवसर में बदलने की तैयारी में सरकार जुट गई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) की तरह सरकार इस बार भी दो दर्जन से अधिक उत्पादों की घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम ला सकती है। औद्योगिक सेक्टर के साथ मिलकर आइटम की पहचान शुरू कर दी गई है। इनमें मुख्य रूप से मशीनरी, मशीन टूल्स, ट्रांसपोर्ट उपकरण, प्रोफेशनल्स उपकरण, केमिकल्स, इलेक्ट्रानिक्स गुड्स से जुड़े आइटम शामिल है। भारत इलेक्ट्रानिक्स और गैर इलेक्ट्रानिक्स मशीनरी का बड़ा आयातक है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, क्लस्टर आधारित मशीनरी की घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाई जा सकती है। औद्योगिक क्लस्टर में केंद्र और राज्य दोनों सरकार से मंजूरी के लिए सिंगल प्वाइंट बनाए जाएंगे। मशीनरी के साथ केमिकल्स और प्लास्टिक का भी भारत बड़ा आयातक देश है। सिर्फ मशीनरी, उपकरण और केमिकल्स को मिलाकर भारत 140 अरब डालर से अधिक का आयात करता है। इलेक्ट्रानिक्स आइटम का 116 अरब डालर का आयात किया जाता है। ये मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े आइटम है जिनका निर्माण घरेलू स्तर पर किया जा सकता है और निर्माण शुरू होने से बड़ी संख्या में रोजगार भी निकलेंगे। साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

60-70 लाख लैपटाप का भारत सालाना आयात करता है: वर्ष 2020 में पीएलआइ स्कीम की घोषणा के बाद बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन और कुछ इलेक्ट्रानिक्स आइटम का निर्माण भारत में शुरू हुआ। हालांकि, अब भी मोबाइल फोन से जुड़े अधिकतर आइटम का भारत आयात करता है। 60-70 लाख लैपटाप का भारत सालाना आयात करता है। लैपटाप की कुल बिक्री में सिर्फ 30 प्रतिशत हिस्सेदारी घरेलू निर्माण की है।

गन्ने व कार्न स्टार्च से बायोप्लास्टिक का होगा उत्पादन: सूत्रों का कहना है कि उन सभी आइटम की पहचान की जा रही है जिनकी मैन्यूफैक्चरिंग घरेलू स्तर पर हो सकती है। वाणिज्य एवं वित्त मंत्रालय के बीच इस मामले को लेकर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। प्लास्टिक के आइटम प्लास्टिक के दाने से बनाए जाते हैं, जो पेट्रोलियम का सह उत्पाद है। अब घरेलू स्तर पर ही चीनी मिल में गन्ने व कार्न स्टार्च से पालिलैक्टिक एसिड (पीएलए) बायोप्लास्टिक का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। बलरामपुर चीनी मिल ने हाल में रिन्युएबल प्लास्टिक निर्माण की शुरुआत की घोषणा की है।

2025-26 में मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों का आयात

मशीनरी	61.7 अरब डालर
मशीन टूल्स	6.4 अरब डालर
ट्रांसपोर्ट उपकरण	34.7 अरब डालर
केमिकल्स से जुड़े उत्पाद	16 अरब डालर
कृत्रिम रेजिन और प्लास्टिक मैटेरियल	22.7 अरब डालर
आर्गेनिक व इनआर्गेनिक केमिकल्स	28 अरब डालर
इलेक्ट्रानिक्स	116 अरब डालर

(स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय)

50 पैसे टूट 96.70 के रिकार्ड निचले स्तर पर बंद हुआ रुपया

मुंबई, प्रेट्र: मंगलवार को रुपया लगातार आठवें कारोबारी दिन भी गिरा और डालर के मुकाबले 50 पैसे घटकर 96.70 के अपने अब तक के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति, मजबूत डालर से घरेलू मुद्रा पर बना हुआ है। एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रुपया सात मई को 94.22 के बंद स्तर के बाद से पिछले आठ कारोबारी दिनों में डालर के मुकाबले 2.48 रुपये गिरा है।

रुपया डालर के मुकाबले 96.38 पर खुला और कारोबार के दौरान इसने 96.27 के उच्चस्तर को छुआ। कारोबार के अंत में यह डालर के 96.70 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद स्तर से 50 पैसे की गिरावट थी। सोमवार को भारतीय रुपया डालर के मुकाबले 96.20 पर बंद हुआ था।

अदाणी समूह के शेयर चढ़े

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिग्गज कारोबारी गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ अमेरिका में सभी आपराधिक आरोप हमेशा के लिए हटाए जाने के बाद मंगलवार को उनके समूह (अदाणी समूह) की कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। बीएसई में एनडीटीवी के शेयर सबसे अधिक पांच प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए। इसके अलावा, अदाणी टोटल गैस 2.07 प्रतिशत, अदाणी एंटरप्राइजेज 1.17 प्रतिशत, अदाणी ग्रीन एनर्जी 0.81 प्रतिशत, अंबुजा सीमेंट 0.42 प्रतिशत, अदाणी एनर्जी साल्यूशंस 0.06 प्रतिशत और एसीसी के शेयर 0.03 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए।

भारत-ईयू एफटीए से घरेलू वाहन मैन्यूफैक्चरिंग को मिलेगी मदद

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारत में अधिक निवेश आकर्षित करने और देश में वाहन मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में मददगार होगा। दोनों पक्षों ने 27 जनवरी को व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी होने की घोषणा की। यह समझौता अगले वर्ष से लागू होने की संभावना है। वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन ने कहा कि समझौते पर बातचीत के दौरान वाहन क्षेत्र एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के रूप में सामने आया। इसकी वजह यह है कि भारत में आयात शुल्क अधिक है, लेकिन देश ने समझौते के माध्यम से उन चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया है।

उद्योग संगठन फिक्की के कार्यमक्रम में जैन ने कहा कि भारत ने इस क्षेत्र में कोटा-आधारित, दीर्घकालिक समाधान प्रदान किए हैं ताकि यूरोपीय संघ को भी रियायतें मिलें और भारतीय उद्योग को पर्याप्त संरक्षण भी प्राप्त हो।

आर्थिक अनिश्चितता को अवसर में बदलें कारोबारी

पीयूष गोयल।

- वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग को वर्तमान स्थिति से नहीं घबराने की दी सलाह
- जापानी मैन्यूफैक्चरिंग सिस्टम सहित वैश्विक स्तर पर मौजूद अच्छी प्रथाएं अपनाने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों को मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को अवसर में बदलने की सलाह दी है। साथ ही इस स्थिति से नहीं घबराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए तेजी से सुधार करने और सप्लाई चेन को मजबूत करने के मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए।

एसोचैम के इंडिया बिजनेस रिफार्म समिट 2026 को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा, 'वर्तमान स्थिति सच में एक मौका है, जिससे हमें और गहराई से जुड़ना चाहिए। पश्चिम एशिया संकट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) जैसी उभरती टेक्नोलाजी भारतीय इंडस्ट्री के लिए मौके लेकर आई है।' गोयल ने इंडस्ट्री से जापानी मैन्यूफैक्चरिंग सिस्टम सहित वैश्विक स्तर पर मौजूद अच्छी प्रथाओं को अपनाने का आग्रह किया है। टैरिफ, यूक्रेन विवाद और पश्चिम एशिया संकट जैसे वैश्विक चुनौतियों के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में भारत का निर्यात 863 अरब डालर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया है।

खाद्य तेल आयात बीते वर्ष तीन प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र: बीते वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का खाद्य तेल आयात तीन प्रतिशत बढ़कर 166.51 लाख टन हो गया। इसकी मुख्य वजह नेपाल से शुल्क मुक्त आयात में तेज उछाल है। 2024-25 में आयात 161.82 लाख टन था। नेपाल ने इस साल भारत को 7.36 लाख टन खाद्य तेल का निर्यात किया और यह पिछले वित्त वर्ष में भेजे गए 3.45 लाख टन से दोगुना से भी ज्यादा है। नेपाल से भारत को होने वाले निर्यात में रिफाइंड सोयाबीन तेल का एक बड़ा हिस्सा था जबकि सूरजमुखी तेल, आरबीडी पामोलिन और रेपसीड तेल का कम मात्रा में निर्यात किया गया।

उद्योग संगठन साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कहा, नेपाल से रिफाइंड तेलों के शुल्क मुक्त निर्यात में बढ़ोतरी ने इस साल भारत के कुल खाने के तेल के आयात में बढ़ोतरी में काफी योगदान दिया है। भारत अभी भी विदेशी आपूर्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर है। घरेलू उत्पादन जरूरत का 40 प्रतिशत ही पूरा करता है।

बिजली मांग 2.60 लाख मेगावाट के पार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: लगातार बढ़ती गर्मी और एयर कंडीशनरों-कूलरों की मांग में वृद्धि के चलते देश में बिजली की अधिकतम मांग प्रतिदिन नया रिकार्ड बना रही है। मंगलवार दोपहर 3:40 बजे अधिकतम बिजली मांग 260.45 गीगावाट (2.604 लाख मेगावाट) पहुंच गई है, जो अब तक का सर्वोच्च रिकार्ड है। गत सोमवार को अधिकतम मांग 2.573 लाख मेगावाट रही थी। देश के अधिकांश हिस्से में गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग में लगातार वृद्धि की संभावना है। बिजली मंत्रालय ने इस दौरान बिजली की मांग 2.71 लाख मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया है।

आंकड़ों से साफ है कि 2.60 लाख मेगावाट रिकार्ड मांग को भी पूरा करने में कोई समस्या नहीं आई है। इसकी एक बड़ी वजह सौर ऊर्जा का प्रदर्शन है। पीक आवर्स (सोलर घंटों) में डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ने लगभग 20,000 मेगावाट का योगदान दिया है। इससे थर्मल पावर संयंत्रों पर दबाव काफी कम रहा। विशेषज्ञों के अनुसार, दिन के पीक टाइम में सौर ऊर्जा कुल बिजली पूर्ति का करीब 20 प्रतिशत संभालने से संकट की आशंका लगभग समाप्त हो गई है।

बिजली मंत्रालय के अनुसार, देश में बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है और ग्रीष्मकालीन मांग को पूरा करने के लिए मजबूत तंत्र मौजूद हैं। पिछली गर्मियों में बिजली की अधिकतम मांग 242.77 गीगावाट थी, जो जून, 2025 में रिकार्ड की गई थी। हालांकि, यह सरकार के 277 गीगावाट के अनुमान से कम रही। मई 2024 में, बिजली की अधिकतम मांग 250 गीगावाट तक पहुंच गई थी, जो उस समय का रिकार्ड था और सितंबर, 2023 के 243.27 गीगावट की पिछली अधिकतम मांग से ज्यादा थी।

- मंगलवार दोपहर 3:40 बजे सर्वाधिक बिजली मांग रिकार्ड की गई
- सोमवार को अधिकतम मांग 2.573 लाख मेगावाट रही थी

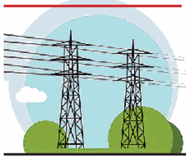

ताप बिजली संयंत्रों के पास 17 दिन का कोयला

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक, 7 मई तक देश के ताप बिजली संयंत्रों के पास 5.38 करोड़ टन कयला उपलब्ध था, जो उनकी खपत के औसतन 17 दिनों के बराबर है। अभी भी तकरीबन यहीं स्थिति है। कोयला आपूर्ति की स्थिति पिछले साल की समान अवधि की तुलना में बेहतर है और ग्रीष्मकालीन पीक डिमांड को देखते हुए पर्याप्त माना जा रहा है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय फलक

अदाणी, रिलायंस व एनटीपीसी लगाएंगे महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

ओमप्रकाश तिवारी • जागरण

- मुख्यमंत्री कार्यालय में इस समझौते को दिया गया अंतिम रूप
- इन संयंत्रों के निर्माण से बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा महाराष्ट्र

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार राज्य की भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए कोंकण क्षेत्र में तीन नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र (न्यूक्लियर पावर प्लांट) स्थापित करने जा रही है। ये संयंत्र कोंकण के दो तटीय जिलों रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग में लगाए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए देश के दो बड़े निजी औद्योगिक घरानों अदाणी समूह, रिलायंस समूह व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी (एनटीपीसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है, जहां बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। भविष्य की औद्योगिक क्रांति, बढ़ते शहरीकरण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक संकल्प को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा एक सुरक्षित और स्वच्छ विकल्प है। उन्होंने भरोसा जताया कि इन तीन संयंत्रों के निर्माण से न केवल महाराष्ट्र बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि कोंकण क्षेत्र में हजारों नए रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा। गौरतलब है कि देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र (टीएपीएस) भी महाराष्ट्र के ही तारापुर में 1969 में चालू किया गया था। इस वर्ष फरवरी में इसकी पहली यूनिट का जीर्णोद्धार कर उसे नवजीवन प्रदान किया गया है। अब 10 वर्ष तक वह 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकेगा। फडणवीस द्वारा एक्स पर दी गई जानकारी के अनुसार, रत्नागिरि जिले के बारसू में अदाणी पावर लिमिटेड करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपयों की लागत से 6000 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाएगी। रत्नागिरि के ही पूर्णागढ़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 220 और 1200 मेगावाट के कई संयंत्र लगाने की तैयारी में है। उसका कुल निवेश 8000 करोड़ से दो लाख करोड़ रुपयों तक होगा। एनटीपीसी भी करीब एक लाख करोड़ रुपयों का निवेश करके 4000 मेगावाट से 7200 मेगावाट तक की कुल छह इकाइयां सिंधुदुर्ग जिले देवगढ़ में लगाएगी। अर्थात, तीनों विकासकर्ता कंपनियां अलग-अलग संयंत्रों का निर्माण और संचालन करेंगी। तीनों परियोजनाओं के पूरी होने के बाद महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र परमाणु ऊर्जा उत्पादन का देश में सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है।

अब तक अटकी हैं जैतापुर और नाणार परियोजनाएं

कोंकण क्षेत्र में परमाणु और बड़े ऊर्जा संयंत्रों की घोषणा होते ही इलाके का पुराना इतिहास भी चर्चा में आ गया है। यह पहला मौका नहीं है, जब कोंकण में इतने बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की गई है। इससे पहले रत्नागिरी जिले के जैतापुर में 9,900 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की योजना बनाई गई थी। इस प्रोजेक्ट का भारी विरोध हुआ। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और मछुआरों की आजीविका के नुकसान के डर से स्थानीय जनता सड़कों पर उतर आई थी। इसलिए यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन सरकार इसे अभी भी जिंदा मान रही है। इसी तरह कोंकण के ही नाणार में एक विशाल अंतरराष्ट्रीय रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स बनाने की योजना थी। इस परियोजना को भी राजनीतिक और स्थानीय विरोध के कारण रद करना पड़ा था। अतीत के अनुभवों को देखते हुए फड़णवीस सरकार के लिए रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में इन तीन नए परमाणु संयंत्रों को जमीन पर उतारना एक बड़ी अग्निपरीक्षा होगी।

राशि जमा करने का समय बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट जाए स्पाइसजेट: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पाइसजेट एयरलाइन को निर्देश दिया कि वह 144 करोड़ जमा करने के लिए समय बढ़ाने की अपनी मांग लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जाए।

यह मामला मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन और केएएल एयरवेज के साथ चल रहे कानूनी विवाद से जुड़ा है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने स्पाइसजेट की ओर से पेश अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा दी गई इस दलील पर गौर किया कि पश्चिम एशिया में जारी संकट ने एयरलाइन के संचालन व वित्तीय स्थिति पर असर डाला है। हाल में सरकार द्वारा विमानन कंपनियों के लिए शुरू 5,000 करोड़ के राहत पैकेज का हवाला देते हुए रोहतगी ने राशि जमा करने के लिए तीन माह का समय देने का अनुरोध किया था। शीर्ष न्यायालय ने समय देने से इन्कार कर दिया व हाई कोर्ट में अपील करने को कहा।

शादी का दबाव बना रही थी युवती, सिपाही के बेटे ने गोली मार दी जान

जागरण संवाददाता, अलीगढ़

सात साल बड़ी युवती के शादी का दबाव बनाने से हेड कांस्टेबल का बेटा विशेष तनाव में आ गया कि उसने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह वारदात से परिवार में कोहराम मच गया।

विशेष का फाइल फोटो। सौ. स्वजन

पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल अनिल कुमार का छोटा बेटा 22 वर्षीय विशेष कुमार कंप्यूटर कोर्स कर रहा था। मंगलवार सुबह 10:30 बजे विशेष कुमार ने कमरे में तमंचे से खुद को गोली मार ली। आवाज सुनकर मां स्नेहलता व स्वजन कमरे में पहुंचे तो युवक खून से लथपथ मिला। स्नेहलता के अनुसार, एक माह पहले विशेष परीक्षा देने ट्रेन से मुरादाबाद गया था। ट्रेन में उसकी मुलाकात संभल की युवती से हुई थी। वह अपने माता-पिता के साथ यात्रा कर रही थी और उसने विशेष का मोबाइल नंबर ले लिया था। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। 15 दिन पहले विशेष कुमार ने मां को बताया कि युवती शादी का दबाव बना रही है। उम्र में वह सात साल बड़ी है। परिवार ने युवक को समझाया कि जब मेल नहीं खा रहा तो शादी क्यों? इस बात को लेकर वह मानसिक तनाव में रहने लगा था। युवक की मां ने बताया कि सोमवार को उसने लड़की से घंटों बात की थी। चेहरे से नहीं लग रहा था कि परेशान है। रात को वह मां के पास सोया। बहन से भी बात की। मंगलवार को सभी काम में लगे हुए थे। तमंचा कहां से लाया, यह किसी को नहीं पता। सीओ सर्वम सिंह का कहना है कि स्वजन ने युवक के मानसिक तनाव में होने की बात बताई है। तमंचा कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है।

कनाडा से आए प्रेमी ने की पंजाबी गायिका की हत्या, शव नहर में फेंका

जागरण संवाददाता, लुधियाना

- शादी से इन्कार करने पर नेपाल के रास्ते पंजाब आया, हत्या कर हुआ फरार

अपहृत 29 वर्षीय पंजाबी गायिका यशविंदर कौर उर्फ इंदर कौर का शव मंगलवार को खन्ना के गांव कुबा के पास नहर से बरामद हुआ। पुलिस जांच में पता चला है कि शादी से इन्कार करने पर गायिका की हत्या प्रेमी सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा ने उसी की कार में गोली मारकर की और शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मोगा निवासी सुखविंदर के पिता प्रीतम सिंह और उसके साथी करमजीत सिंह को गिरफ्तार किया है, सुखविंदर कनाडा फरार हो गया है। तीनों के खिलाफ हत्या और अपहरण का मामला दर्ज किया गया है।

13 मई की रात करीब 8:30 बजे यशविंदर घर से कार में किराने का सामान लेने के लिए निकली थीं, लेकिन लौटीं नहीं। परिवार ने जब संपर्क की कोशिश की तो उसका मोबाइल बंद था। इसके बाद भाई ज्योतिंदर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में आरोपित सुखविंदर अपने साथियों के साथ गायिका का उसी की कार में पिस्तौल की बल पर अपहरण करते दिखा। छह दिन बाद पुलिस को नहर से इंदर कौर का शव मिला। एक किलोमीटर दूर मिली कार में खून के धब्बे मिले।

यशविंदर कौर उर्फ इंदर कौर। सौ. स्वजन

हवाई सुरक्षा के लिए डीजीसीए और रक्षा एजेंसियां मिलकर बनाएंगी नया सिस्टम

- एएआइबी ने डीजीसीए और रक्षा एजेंसियों के समन्वय में नया तंत्र बनाने का दिया सुझाव
- पोर्ट ब्लेयर में एअर इंडिया विमान और नौसेना हेलीकाप्टर के करीब आने का मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र: विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआइबी) ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और रक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक औपचारिक व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश फरवरी 2024 में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर हुई एक गंभीर घटना की जांच रिपोर्ट में की गई है, जिसमें एअर इंडिया का विमान और भारतीय नौसेना का हेलीकाप्टर हवा में बेहद करीब आ गए थे।

रिपोर्ट के अनुसार, दो फरवरी 2024 को एअर इंडिया का ए319 विमान पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता जा रहा था। उसी समय भारतीय नौसेना का एएलएच एमके-3 हेलीकाप्टर प्रशिक्षण मिशन पर उड़ान भर रहा था। जांच में पाया गया कि अप्रोच कंट्रोलर द्वारा हवाई यातायात की स्थिति का सही आकलन नहीं किया गया, जिसके कारण दोनों विमानों के बीच दूरी बेहद कम रह गई।

स्थिति गंभीर होने पर चेतावनी जारी की गई, जिसके बाद हेलीकाप्टर ने तुरंत दाईं ओर मुड़कर विमान के रास्ते से खुद को अलग किया। बाद में एअर इंडिया का विमान अपने तय मार्ग पर आगे बढ़ गया, जबकि हेलीकाप्टर सुरक्षित रूप से वापस उतर गया। एएआइबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डीजीसीए, एएआइबी और रक्षा एजेंसियों विशेषकर वायुसेना, नौसेना और सेना के बीच सुरक्षा संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान का कोई स्पष्ट और औपचारिक तंत्र नहीं है। ब्यूरो ने याद दिलाया कि इससे पहले भी ग्वालियर और उमरी में हुई घटनाओं की जांच रिपोर्टों में ऐसी सिफारिशें की गई थीं, लेकिन अब तक उन्हें लागू नहीं किया गया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पोर्ट ब्लेयर में बढ़ते हवाई यातायात को देखते हुए भारतीय नौसेना वहां द्वितीयक रडार प्रणाली लगाने पर विचार करे, ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को विमानों की निगरानी और संचालन में बेहतर मदद मिल सके।

एएआइबी ने यह भी कहा कि डीजीसीए को अपने नियमों में संशोधन कर रक्षा विमानों या रक्षा हवाई अड्डों से जुड़ी घटनाओं की जांच प्रक्रिया को और स्पष्ट करना चाहिए। इसके अलावा, एअर इंडिया को अपने पायलटों और उड़ान कर्मचारियों को रेडियो संचार अनुशासन का पालन करने के प्रति और अधिक जागरूक करने की सलाह दी गई है। इस घटना को एएआइबी ने 'गंभीर घटना'' की श्रेणी में रखा था।

टेलीकालिंग की आड़ में 98 विश्वविद्यालयों तक नेटवर्क, सरगना का भांजा गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर

- फर्जी डिग्री गिरोह से जुड़े मामले में पुलिस टीम ने की नौवीं गिरफ्तारी

65 डिग्रियां अलग-अलग स्थानों पर डिलीवर करने की वात स्वीकारी

फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने-बेचने के गिरोह का सरगना डा. मनीष कुमार देशभर के 98 विश्वविद्यालयों से टेलीकालिंग की आड़ में संपर्क में था। उसने हैदराबाद में इंस्टीट्यूट के साथ काल सेंटर बना रखा था। वहां 20 युवक-युवतियों को टेलीकालिंग के लिए रखा था, जिनका काम फेल होने वाले छात्रों, बेरोजगारों को नौकरी के लिए डिग्री व सर्टिफिकेट तैयार कराने को प्रोत्साहित करने का था। वह उन्हें 25 से 30 हजार प्रतिमाह वेतन देता था।

वहीं, मंगलवार को पुलिस ने गिरोह के सरगना डा. मनीष के भांजे फरीदाबाद निवासी राघव सर्राफ को भी कानपुर में गिरफ्तार कर लिया। राघव फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद समेत अन्य स्थानों में घर-घर जाकर डिग्रियां डिलीवरी करने का काम करता था। पूछताछ में आरोपित ने अब तक 65 डिग्रियां अलग-अलग स्थानों पर डिलीवर करने की बात स्वीकारी है।

फर्जी मार्कशीट मामले में पकड़े गए आरोपित राघ व सर्राफ के बारे में जानकारी देते डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी। जागरण

डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि हैदराबाद में रहने वाले राजस्थान के सीकर के मूल निवासी सरगना डा. मनीष कुमार व उसके साथी उन्नाव के कोचिंग संचालक अर्जुन यादव को सोमवार को जेल भेजा था।

4 लोग मारे गए और कई घायल हो गए रूस के यूक्रेन के चेरनिह्वि और सुमी प्रांतों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले में। यूक्रेन ने भी रूस में एक तेल रिफाइनरी व पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाने और मास्को की तरफ कई ड्रोन से हमले का दावा किया।

रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली

नरेन्द्र मोदी जर्जिया मेलोनी

भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है

भारत और इटली के संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व तेजी से विस्तार हुआ है। ये संबंध केवल सौहार्दपूर्ण मित्रता तक सीमित नहीं, बल्कि अब स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य के साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। जब पूरी दुनिया की व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, तब इटली और भारत की साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद से आगे बढ़ रही है। आपसी संबंध अब एक नए और अधिक व्यापक स्तर पर पहुंच रहे हैं, जिसमें दोनों देशों की आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत विरासत शामिल है।

हमारा सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा इस पर निर्भर करेगी कि देश कितनी क्षमता से नवाचार करें, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करें और अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करें। इसी उद्देश्य से हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा तथा विविधतापूर्ण बनाने का संकल्प लिया है, ताकि नए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और दोनों देशों की पूरक शक्तियों का बेहतर उपयोग हो सके। हम इटली की डिजाइन क्षमता, बेहतरीन विनिर्माण कौशल और विश्वस्तरीय सुपरकंप्यूटर तकनीक, जो उसे एक औद्योगिक महाशक्ति बनाती है, को भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग प्रतिभा, बड़े पैमाने की क्षमता, नवाचार और 100 से अधिक यूनिकार्न तथा 2 लाख स्टार्टअप वाले उद्यमी इकोसिस्टम के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली तालमेल बनाना चाहते हैं। यह ऐसा साझा मूल्य निर्माण है, जिसमें दोनों देशों की औद्योगिक ताकतें एक-दूसरे को और अधिक मजबूत बनाती हैं।

यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश बढ़ाने का रास्ता खोलता है। हमारा लक्ष्य 2029 तक भारत और इटली के बीच व्यापार को 20 अरब यूरो से आगे ले जाना है। इसमें रक्षा एवं एयरोस्पेस, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, मशीनरी, आटोमोबाइल पुर्जे, रसायन, दवाइयां, वस्त्र, कृषि-खाद्य क्षेत्र और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा। ''मेड इन इटली'' हमेशा से दुनिया भर में उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है और आज इसका स्वाभाविक तालमेल ''मेक इन इंडिया' पहल के उच्च गुणवत्ता वाले लक्ष्यों के साथ दिखाई देता है। इसी संदर्भ में भारत के लिए उत्पादन में इतालवी कंपनियों की बढ़ती रुचि और इटली में भारतीय उद्योगों की बढ़ती मौजूदगी, जो अब दोनों पक्षों की ओर से मिलाकर 1000 से अधिक हो चुकी है, एक सकारात्मक संकेत है। यह हमारी सप्लाई चेन के एकीकरण को और मजबूत करेगी।

तकनीकी नवाचार हमारी साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आने वाले दशकों में दुनिया एक बड़े तकनीकी बदलाव के दौर से गुजरेगी, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के बीच साझेदारी भी इसे मजबूती देगी।

भारत का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआइ) पहले से ही दुनिया के कई देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। विशेष रूप से एआइ आज हमारे समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इटली और भारत लंबे समय से इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं, ताकि एआइ का विकास जिम्मेदार और मानव-केंद्रित हो। भारत और इटली एआइ को समावेशी विकास का एक शक्तिशाली माध्यम मानते हैं, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और आसान, बहुभाषी तकनीक के जरिए एआइ सामाजिक और डिजिटल खाइयों को कम कर सकता है। भारत की तकनीक के केंद्र में मानव को रखने की सोच और इटली की मानव-केंद्रित ''एल्गोर-एथिक्स'' की अवधारणा, जो उसकी मानवतावादी परंपरा पर आधारित है, पर आगे बढ़ते हुए हमारी साझेदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआइ सामाजिक सशक्तीकरण का माध्यम बने।

हर क्षेत्र में भारत और इटली के बीच बढ़ रहा है सहयोग फाइल

हमारा दृष्टिकोण भारत की विशाल डिजिटल क्षमता को इटली की नैतिक और औद्योगिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है, ताकि तकनीक मानव गरिमा की सेवा कर सके। सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण और मजबूत साइबर ढांचे से जुड़ी श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करके हम एक ऐसा खुला, भरोसेमंद और समान डिजिटल वातावरण बनाना चाहते हैं, जिसमें हर देश एआइ का उपयोग कर सके और उससे लाभ उठा सके। यही सोच इटली की जी7 अध्यक्षता और 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआइ इंपैक्ट समिट के निष्कर्षों का मुख्य आधार है। एआइ को इंसानों की ओर से इंसानों के लिए बनाई गई तकनीक मानने का अर्थ है यह स्पष्ट करना कि तकनीक न तो मनुष्य की जगह ले सकती है और न ही उसके मूल अधिकारों को कमजोर कर सकती है। इसका उपयोग जनमत को प्रभावित करने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए भी नहीं होना चाहिए। आज की तेजी से जुड़ी हुई दुनिया में स्वतंत्रता और मानव गरिमा की रक्षा का हमारा दृष्टिकोण इसी चुनौती पर आधारित है। हमारा सहयोग अंतरिक्ष क्षेत्र तक भी फैला हुआ है। अंतरिक्ष अनुसंधान और सैटेलाइट तकनीक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति तथा इटली की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता, संयुक्त परियोजनाओं और नई पीढ़ी की तकनीक के विकास के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है।

राष्ट्रों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और स्थिरता बेहद आवश्यक हैं। इसलिए इटली और भारत रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक तकनीक जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारा सहयोग महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और साइबर अपराध जैसी चुनौतियों के खिलाफ मजबूती बढ़ाने में मदद करेगा।

ऊर्जा हमारी साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण आधार है। दुनिया में ऊर्जा के विविध स्रोतों की ओर बढ़ रहे बदलाव के लिए नवाचार, निवेश और सहयोग की आवश्यकता है। भारत और इटली नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हाइड्रोजन तकनीक तथा स्मार्ट ग्रिड से लेकर मजबूत बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनने की भारत की पहल अपार संभावनाएं रखती है। यह इटली की नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में उन्नत तकनीक और यूरोप के लिए ऊर्जा प्रवेश द्वार के रूप में उसकी रणनीतिक भूमिका के साथ पूरी तरह मेल खाती है। इस संदर्भ में भारत की अगुवाई वाली प्रमुख पहलों-अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आइएसए), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआइ) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (जीबीए) में अन्य देशों के साथ हमारा सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण है।

भौतिक, डिजिटल और मानवीय संपर्क ही वह कड़ी है, जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती है। भारत और इटली दोनों वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों-इंडो-पैसिफिक और भूमध्यसागर के केंद्र में स्थित हैं। अब इन क्षेत्रों को अलग-अलग नहीं, बल्कि आपस में जुड़े हुए क्षेत्रों के रूप में देखा जा रहा है। हम एक नए 'इंडो-मैडिटेरेनियन'' क्षेत्र को उभरते देख रहे हैं, जो व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और विचारों का एक महत्वपूर्ण गलियारा बन रहा है और हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ता है। इसी आपस में जुड़े हुए क्षेत्र में हमारा संबंध स्वाभाविक रूप से एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित होता है- ऐसी साझेदारी, जो दो महाद्वीपों को जोड़ती है और नई वैश्विक परिस्थितियों को आकार देती है। इस संदर्भ में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आइएमईसी) एक ऐसी दूरदर्शी योजना है, जिसका उद्देश्य आधुनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा प्रणालियों और मजबूत सप्लाई चेन के माध्यम से हमारे क्षेत्रों को जोड़ना है। भारत और इटली अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

हम अपनी साझा चुनौतियों का समाधान दोनों देशों के गहरे संबंधों और लंबे सांस्कृतिक जुड़ाव के आधार पर कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में ''धर्म'' का विचार उस जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, जिसे हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। वहीं ''वसुधैव कुटुंबकम्'' अर्थात ''पूरी दुनिया एक परिवार है'' का सिद्धांत आज के आपस में जुड़े डिजिटल युग में और भी अधिक प्रासंगिक लगता है। ये मूल्य इटली की मानवतावादी परंपरा से भी मेल खाते हैं, जिसकी जड़ें पुनर्जागरण काल में हैं। यह परंपरा हर व्यक्ति की गरिमा और संस्कृति की उस शक्ति पर जोर देती है, जो समाजों और लोगों को एकजुट कर सकती है। इसलिए हमारी साझा दृष्टि का उद्देश्य लोगों को केंद्र में रखते हुए भारत-इटली साझेदारी को मजबूत, आधुनिक और भविष्य उन्मुख आधार प्रदान करना है।

(लेखकद्वय भारत और इटली के शासनाध्यक्ष हैं)

नार्वे में प्रेस स्वतंत्रता के सवाल पर भारत का दो टूक जवाब, बोला- लोकतंत्र पर हमें गर्व

- **पीएम मोदी से सवाल पूछने की कोशिश करने वाली नार्वे की पत्रकार के पोस्ट पर भी भारत ने दिया जवाब**
- **विदेश मंत्रालय बोला- भारत की व्यापकता समझे बिना एनजीओ रिपोर्ट के आधार पर धारणा बनाना गलत**

नई दिल्ली में मंगलवार को प्रेसवार्ता को संबोधित करते विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जार्ज। प्रेट्र

ओस्लो, प्रेट्र: नार्वे दौरे पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा एक पत्रकार का सवाल न लेने से उठे प्रेस स्वतंत्रता व मानवाधिकारों के सवाल पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जार्ज ने कहा, भारत अपने संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गर्व करता है। उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, भारत को लेकर कई लोग सीमित और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टों के आधार पर राय बना लेते हैं।

विवाद तब शुरू हुआ जब नार्वे की पत्रकार हेला लेंग स्वेंडसन ने पीएम मोदी व नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में प्रश्न पूछने की कोशिश की। हालांकि पहले ही बता दिया गया था कि दोनों नेता मीडिया के सवाल नहीं लेंगे। जिसके बाद यह मुद्दा इंटरनेट मीडिया पर चर्चा में आ गया।

पूर्व अमेरिकी संवाददाता और वर्तमान में नार्वे के समाचारपत्र 'डाग्साविसेन' में कार्यरत स्वेंडसन ने बाद में एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि नार्वे निरंतर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर है, जबकि भारत काफी नीचे है। यह भी लिखा कि मोदी ने उनके प्रश्न का जवाब नहीं दिया। इस पर नार्वे स्थित भारतीय दूतावास ने प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें प्रेस ब्रीफिंग में आने व प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया।

बाद में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में जार्ज ने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, भारत दुनिया की कुल आबादी का छठा हिस्सा है, पर दुनिया की समस्याओं में उसका योगदान उतना नहीं है। भारतीय संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देता है। कहा, ''1947 में स्वतंत्रता के साथ ही भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल गया था। कई देशों में यह अधिकार दशकों बाद मिला।'' भारत जैसे विशाल, त्रिविधतापूर्ण देश को समझे बिना कुछ अनजान व भ्रामक एनजीओ रिपोर्टों के आधार पर निष्कर्ष निकालना गलत है। जार्ज ने कहा, सिर्फ दिल्ली में ही 200 से ज्यादा समाचार चैनल हैं। भारत की लोकतांत्रिक ऊर्जा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पैमाना दुनिया के कई देशों से कहीं बड़ा है।

राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा का पलटवार

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पत्रकार हेला लेंग द्वारा एक्स पर जारी वीडियो का जिक्र करके पीएम पर घबराकर वहां से चले जाने का आरोप लगाया। कहा, "जब छिपाने को कुछ नहीं होता, तब डरने की भी जरूरत नहीं होती। जब दुनिया एक समझौता कर चुके पीएम को सवालों से घबराकर जाते देखती है, तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है?" राहुल की टिप्पणी पर भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा-कांग्रेस को पता होना चाहिए कि प्रेस ब्रीफिंग में नार्वे के पीएम भी मौजूद थे। उन्होंने भी मीडिया के सवाल नहीं लिए, पर राहुल के नेतृत्व वाला कांग्रेस का उन्मादी इकोसिस्टम अनुशासनहीन पत्रकार की बेसिर-पैर की बयानबाजी पर जश्न मना रहा है। क्या उस पत्रकार की तरह कांग्रेस नेतृत्व भी उन्हीं के प्रभाव में है जो मजबूत, शक्तिशाली भारत नहीं देखना चाहते।

नार्डिक देशों ने सुप में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दोहराया

प्रथम पृष्ठ से आगे

इस दौरान आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रोस्टाडाटिर ने कहा,''मुझे आज सुबह भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक करने का अवसर मिला, जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि हमारे दोनों देशों के बीच बताने लायक एक शानदार कहानी है। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय पर आया है, जहां हम यह दिखा सकते हैं कि भले ही हम नॉर्डिक देश और भारत के रूप में मीलों दूर हैं और आइसलैंड जैसे छोटे देश का स्केल और आकार अलग है, फिर भी कई चीजें हमें एक साथ जोड़ती हैं।' बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जार्ज ने बताया कि नार्डिक देशों के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (सुप) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया।

नार्डिक देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार चार गुणा बढ़ा :

भारत नार्डिक देशों के साथ पिछले एक दशक से अपने संबंधों को गढ़ने में लगा है। एक दशक में इन देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार चार गुणा बढ़ चुका है। इन देशों से भारत में होने वाला निवेश 200 गुना हो चुका है। इन देशों के फंड भारत में जम कर निवेश कर रहे हैं।

भारत इन फंड्स को आकर्षित करने की कई कोशिशें भी कर रहा है। अक्टूबर 2025 में भारत ने नार्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ कारोबारी और आर्थिकी साझेदारी समझौते को लागू किया है। इसके बाद भारत ने यूरोपियन यूनियन (ईयू) के साथ मुक्त कारोबार समझौता किया है, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, और स्वीडन भी भागीदार हैं।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह बताया कि नार्डिक देशों में भी संबंध शब्द का वहीं मतलब होता है जो भारत में होता है। मोदी ने कहा कि वैसे तो हम सभी अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन कभी-कभी एक शब्द भी हमारी परस्पर संबंधों को रेखांकित करने के लिए काफी होता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को नार्वे की अपनी बेहद सफल यात्रा और ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत-नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद मंगलवार देर रात(भारतीय समयानुसार) रोम पहुंच गए। उल्लेखनीय है कि नार्डिक देश उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे, स्वीडन के संप्रभु राष्ट्र शामिल हैं। पांच देशों के इस समूह के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। इन देशों ने हर मौके पर भारत का खुलकर समर्थन किया है।

ट्रंप का दावा, घंटेभर में होने वाला था ईरान पर हमला, अरब देशों की अपील पर टाला

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- **अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी चेतावनी- ईरान ने समझौता न किया तो कार्रवाई तय**
- **ईरान की चेतावनी- किसी भी हमले का मिलेगा त्वरित और निर्णायक जवाब**

पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान के बीच तनाव फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान पर नए सैन्य हमले से ''सिर्फ एक घंटे दूर'' था, पर अंतिम समय में उन्होंने इसे टालने का फैसला किया। ट्रंप के मुताबिक, यह निर्णय ईरान की ओर से मिले नए शांति संकेतों और कतर, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात जैसे अरब देशों की अपील के बाद लिया गया। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि यदि अगले दो-तीन दिनों में स्वीकार्य परमाणु समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका पूरी ताकत से हमला कर सकता है। कहा,ज्यादा से ज्यादा रविवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, अमेरिकी सेना को फिलहाल प्रस्तावित कार्रवाई रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं, पर उसे तैयार रहने को कहा गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, यह हमला कथित तौर पर ''आपरेशन स्लेजहैमर'' के तहत किया जाना था। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा, उन्हें लोकप्रियता से मतलब नहीं है। जो लोग मेरे फैसले की आलोचना कर रहे हैं,

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

जब वे सुनेंगे कि ईरान से उन परमाणु हथियारों की क्षमता छीन ली गई है, जिससे वे लास एंजलिस जैसे बड़े शहरों पर हमला कर सकते थे, तो उन्हें मेरे फैसले की अहमियत का पता चलेगा। मुझे ये काम हर हाल में करना है। मैं दुनिया उजड़ते हुए नहीं देख सकता। इस बीच, अमेरिकी प्रशासन ने सैन्य तैयारी भी तेज कर दी थी।

ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर चर्चा की, व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की और अमेरिका ने हथियारों व सैन्य उपकरणों से भरे कई विमान इजरायल भेजे। रायटर के अनुसार, पश्चिम एशिया में तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट आई, पर कीमतें अब भी 110 डालर प्रति बैरल बनी हुई हैं। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार, देश का रणनीतिक तेल भंडार घटकर 37.4 करोड़ बैरल रह गया है, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे निचला स्तर है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए अमेरिका को पिछले सप्ताह करीब 10 लाख बैरल तेल जारी करना पड़ा। एएनआइ के अनुसार, ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरानी सेना की संयुक्त कमान 'खातम अल-अनबिया' के प्रमुख अली अब्दोल्लाही ने चेतावनी दी कि अमेरिकी हमले का ''त्वरित, व्यापक व निर्णायक'' जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा, ईरानी सेना के ''लोहे के पंजे'' अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मो. अक्रमिनिया ने कहा, हमले की स्थिति में नए मोर्चे खोले जाएंगे। नए हथियारों का प्रयोग होगा। कहा, ईरान को न घेरा जा सकता है न हराया जा सकता है। उन्होंने अमेरिका को इजरायली झांसे में आने से बचने की सलाह भी दी।

दक्षिण कोरिया पहुंचे राजनाथ, रक्षा संबंध मजबूत करने पर होगा फोकस

- **इससे पूर्व ने राजनाथ ने हनोई में वियतनामी समकक्ष से भेंट कर द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की**

<< हनोई में मंगलवार को वियतनाम के अपने समकक्ष जनरल फान वान जियांग के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

सियोल, आइएएनएस : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार दोपहर तीन दिनी दौरे पर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे। राजनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, "कोरिया गणराज्य में आधिकारिक दौरे पर पहुंचा हूं। इसका उद्देश्य भारत-कोरिया रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।"

दौरे पर राजनाथ कोरियाई रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक संग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नए पहलों की खोज करेंगे। राजनाथ इस दौरान भारत-कोरिया व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। राजनाथ ने इससे पहले हनोई का दो दिनी दौरा पूरा किया, जहां भारत-वियतनाम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया। राजनाथ ने हनोई में मंगलवार को अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान जियांग से भेंट की, जिसमें दोनों देशों में साझेदारी की समीक्षा की गई और समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण व क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। राजनाथ ने वियतनाम के राष्ट्रपिता हो ची मिन्ह को 136वीं जयंती पर उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

ओपनएआइ से हारे मस्क बौखलाए, जज को बता दिया एक्टिविस्ट

ओकलैंड (अमेरिका), एपी: चैटजीपीटी की मूल कंपनी ओपनएआइ एलन मस्क के साथ चली कानूनी लड़ाई में बड़ी राहत पाने में सफल रही है। कैलिफोर्निया की नौ जजों की ज्यूरी ने मस्क का मुकदमा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने मामला दायर करने में बहुत देर कर दी और वैधानिक समय सीमा पार कर दी थी। इस फैसले के बाद ओपनएआइ के संभावित बड़े आइपीओ की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं मस्क के लिए दो माह से भी कम समय में यह दूसरी बड़ी अदालती हार थी।

मस्क, जो ओपनएआइ के सह-संस्थापक और शुरुआती निवेशकों में रहे हैं, ने अदालत में कहा-उन्होंने कंपनी को खड़ा करने के लिए ''मुफ्त फंडिंग'' दी थी। ओपनएआइ ने मानवता के हित में एआइ विकसित करने वाली गैर-लाभकारी संस्था बने रहने के मूल

- **कोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा- मुकदमा दायर करने की समयसीमा पार कर गए मस्क**

एलन मस्क। फाइल

ओपनएआइ के सह-संस्थापक थे एलन मस्क, 1.8 करोड़ डालर का किया था निवेश

उद्देश्य से समझौता किया और इसे कारोबारी माडल में बदल दिया।

फैसले के बाद मस्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की बात कही और फैसला सुनाने वाली जज यवोन गोंजालेज रोजर्स को एक्टिविस्ट ओकलैंड बताकर उनकी आलोचना की। मस्क ने कहा,खराब उदाहरण प्रस्तुत करने को जज ने ज्यूरी का सिर्फ दिखावा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जज ने चैरिटी संस्थाओं को लूटने का खुला लाइसेंस दे दिया है। बता दें कि मस्क व आल्टमैन के बीच अदालती जंग तीन हफ्ते तक चली। मस्क ने ओपनएआइ में 1.8 करोड़ डालर का निवेश किया था, जो अब 852 अरब डालर की कंपनी बन चुकी है। मस्क चाहते थे कि ओपनएआइ के सीईओ सैम आल्टमैन को उनके पद से हटा दिया जाए। दूसरी ओर आल्टमैन ने मस्क के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, यह प्रतिस्पर्धी एआइ कंपनी एक्सएआइ के हित में ओपनएआइ की प्रगति रोकने की कोशिश है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला सिर्फ मस्क और आल्टमैन की लड़ाई नहीं, बल्कि उस दौर की तस्वीर है जिसमें दुनिया की सबसे प्रभावशाली तकनीक निजी कंपनियों और उनके मालिकों के हाथों में तेजी से केंद्रित होती जा रही है।

अमेरिका में मस्जिद पर गोलीबारी, पांच की मौत

अमेरिका के सैन डिएगो में सोमवार को इस्लामिक सेंटर में गोलीबारी के बाद पूरे क्षेत्र को घेरे पुलिस वाहन। रायटर

सैन डिएगो, रायटर: अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद इस्लामिक सेंटर आफ सैन डिएगो में सोमवार को दो किशोर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। बाद में दोनों संदिग्ध किशोर भी एक वाहन में मृत पाए गए। पुलिस के अनुसार दोनों ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

सैन डिएगो के पुलिस प्रमुख स्काट वाहल ने बताया कि हमले की जांच हेट क्राइम यानी घृणा अपराध के तौर पर की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, एक संदिग्ध की मां ने घटना से दो घंटे पूर्व पुलिस को सूचना दी थी कि उसका बेटा आत्मघाती प्रवृत्ति का है और घर से कई हथियार लेकर फरार हो गया है। हमले में मस्जिद के सुरक्षा गार्ड की भी मौत हुई, जिसने हमलावरों को रोकने की कोशिश कर कई लोगों की जान बचाई। घटना के समय मस्जिद परिसर में मौजूद स्कूल के सभी बच्चे सुरक्षित बचा लिए गए।

अमेरिका ने अपाचे हेलीकाप्टर की संभावित बिक्री को दी मंजूरी

- **अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा- कुल 42.82 करोड़ डालर का है ब्रिकी पैकेज**
- **भारत की सैन्य क्षमता में होगा इजाफा, क्षेत्रीय खतरों से निपटने में मिलेगी मदद**

वाशिंगटन, प्रेट्र अमेरिका ने भारत के लिए 42.82 करोड़ डालर के दो संभावित विदेशी सैन्य बिक्री पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत अपाचे हेलीकाप्टरों के लिए सहायक सेवाएं और संबंधित उपकरण 19.82 करोड़ अमेरिकी डालर की अनुमानित लागत पर बेचने की स्वीकृति देने के साथ-साथ एम 777 ए2 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपों की रखरखाव सेवाओं के लिए लगभग 23 करोड़ अमेरिकी डालर की अनुमानित लागत पर स्वीकृति दी गई है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि अपाचे सहायक सेवाएं मूल निर्माता बोइंग और लाकहीड मार्टिन प्रदान करेंगे। वहीं होवित्जर की सहायक सेवाओं के लिए ब्रिटेन के कंब्रिया स्थित 'बीएई सिस्टम्स' होगा। कहा, भारत ने एएच-64ई अपाचे रखरखाव सहायता सेवाएं, अमेरिकी सरकार और अनुबंध इंजीनियरिंग, तकनीकी व रसद सहायता सेवाएं, तकनीकी डाटा और प्रकाशन, कर्मियों का प्रशिक्षण तथा रसद और इससे संबंधित अन्य चीजों को खरीदने का अनुरोध किया था। इसके अलावा एम777ए2 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर के लिए भी दीर्घकालिक रखरखाव सहायता सेवाएं खरीदने का अनुरोध किया था। अपाचे हेलिकाप्टरों और होवित्जरों के लिए सहायक सेवाओं की संभावित बिक्री विदेशी सैन्य बिक्री व्यवस्था के तहत की जाएगी।

विदेश विभाग ने कहा, हेलीकाप्टरों और एम777ए2 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपों की सहायक सेवाओं के लिए प्रस्तावित बिक्री अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने में सहायक होगी।

बल्लेबाज	रन
वैभव सूर्यवंशी	579
मिशेल मार्श	563
हेनरिक क्लासेन	555

गेंदबाज	विकेट
भुवनेश्वर कुमार	24
कैगिसो रबादा	21
अंशुल कंबोज	20

जयपुर में उगा राजस्थान की जीत का 'सूर्य'

राजस्थान रायल्स ने लखनऊ को सात विकेट से हराया मार्श की पारी पर भारी सूर्यवंशी की बल्लेबाजी

वैभव सूर्यवंशी ● एपी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: रन वही जो टीम की जीत में काम आए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मंगलवार को लखनऊ सुपरजायंट्स और राजस्थान रायल्स के बीच खेले गए मुकाबले में एक ओर मिशेल मार्श ने 57 गेंदों में करीब 168 के स्ट्राइक रेट से 96 रनों की पारी खेली तो वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों में 10 छक्के जड़ते हुए 244 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 93 रनों की पारी खेली। वैभव की पारी के आगे मार्श की पारी फीकी साबित हुई और इसी ने मैच में अंतर साबित किया। राजस्थान रायल्स ने लखनऊ को सात विकेट से हराकर प्लेआफ की ओर कदम बढ़ाया। लखनऊ ने राजस्थान के सामने 221 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने पांच गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इसके साथ ही सूर्यवंशी की इस पारी की बदौलत राजस्थान को घरेलू मैदान जयपुर में लगातार तीन हार के बाद जीत के दर्शन हुए।

राजस्थान की इस जीत के नायक 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने शुरुआती दबाव से उबरते हुए विस्फोटक पारी खेली। वैभव शुरुआत में थोड़े नर्वस दिखे, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसा गियर बदला कि लखनऊ के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। उन्होंने अपनी पारी में 10 छक्के लगाए और केवल सात रन से अपना तीसरा आइपीएल शतक चूक गए। वैभव की बल्लेबाजी पर कमेंट्री करते हुए इयान बिशप ने कहा, 'वह तैयार है', और यह लाइन शायद लंबे समय तक याद रखी जाएगी। वैभव (53 छक्के) अब एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल (59 छक्के) के रिकार्ड के करीब पहुंच गए हैं। वह 600 रन पूरे करने से भी सिर्फ 26 रन दूर हैं।

कार्यवाहक कप्तान यशस्वी जायसवाल ने भी टीम को तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने 23 गेंदों में 43 रन बनाए और वैभव के साथ मिलकर पावरप्ले में ही लखनऊ पर दबाव बना दिया। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने जिम्मेदारी संभालते हुए नाबाद 53 रन की संयमित पारी खेली और टीम को जीत तक पहुंचाया। राजस्थान की बल्लेबाजी पूरे मुकाबले में लखनऊ के गेंदबाजों पर हावी रही। लखनऊ की फील्डिंग बेहद खराब रही। मोहसिन खान ने 14वें ओवर में वैभव को रनआउट करने का आसान सा मौका गंवा दिया। हालांकि अंतिम गेंद पर उन्होंने वैभव को आउट कर इसकी भरपाई करने की कोशिश की। लखनऊ के गेंदबाज भी लगातार गलत लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करते नजर आए। इससे पहले लखनऊ ने मार्श और जोश इंग्लिस (60) की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 220 रन बनाए। एक समय लखनऊ की टीम 240-250 के स्कोर तक पहुंचती दिख रही थी, लेकिन अंतिम ओवर में जोफ्रा आर्चर की कसी हुई गेंदबाजी अहम साबित हुई।

स्कोर बोर्ड

टास: राजस्थान रायल्स (गेंदबाजी)

लखनऊ सुपर जायंट्स: 220/5 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
मार्श रन आउट	96	57	11/5
इंग्लिस बो. यश	60	29	7/3
पूरन का. फरेरा बो. यश	16	11	0/2
रिषभ रन आउट	35	23	2/2
समद अविजित	0	0	0/0
बडोनी बो. आर्चर	0	1	0/0

अतिरिक्त : 13 (लेबा :3, वा : 9, नोबा : 1)

विकेटपतन : 1-109 (इंग्लिस, 8.2), 2-151 (पूरन, 12.2), 3-215 (रिषभ, 19.1), 4-220 (मार्श, 19.5), 5-220 (बडोनी, 19.6)

गेंदबाजी : आर्चर 4-0-39-1, सुशांत 4-0-46-0, संदीप 3-0-43-0, ब्रिजेश 4-0-44-0, यश 4-0-35-2, शनाका 1-0-10-0

राजस्थान रायल्स: 225/3 (19.1 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
जायसवाल का. पंत बो. आकाश	43	23	8/1
सूर्यवंशी का. समद बो. मोहसिन	93	38	7/10
जुरैल अविजित	53	38	3/3
प्रिटोरियस रन आउट	7	6	0/0
फरेरा अविजित	16	10	1/1

अतिरिक्त : 13 (लेबा : 3, वा: 10,)

विकेटपतन : 1-75 (जायसवाल, 6.3), 2-180 (सूर्यवंशी, 13.6), 3-196 (प्रिटोरियस, 16.2)

गेंदबाजी : आकाश 3-0-54-1, मोहसिन 4-0-31-1, मयंक 4-0-50-0, प्रिंस 4-0-43-0, दिग्वेश 4-0-38-0, सहबाज 0.1-0-6-0

अंक तालिका		मैच	जीत	हार	रद	नेट रन रेट	अंक
1	आरसीबी (Q)	13	9	4	0	+1.065	18
2	गुजरात (Q)	13	8	5	0	+0.400	16
3	हैदराबाद (Q)	13	8	5	0	+0.350	16
4	राजस्थान	13	7	6	0	+0.083	14
5	पंजाब	13	6	6	1	+0.227	13
6	चेन्नई	13	6	7	0	-0.016	12
7	दिल्ली	13	6	7	0	-0.871	12
8	कोलकाता	12	5	6	1	-0.038	11
9	मुंबई (E)	12	4	8	0	-0.504	8
10	लखनऊ (E)	13	4	9	0	-0.702	8

बिशप के सवाल पर कंफ्यूज दिखे रिषभ पंत

टास के दौरान रिषभ पंत भी कंफ्यूज दिखे। प्रजेंटर इयान बिशप ने उनसे बदलाव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा शमी बाहर हैं, मोहसिन खेलेंगे। बिशप ने पंत से पूछा कि शमी के साथ क्या दिक्कत है तो पंत ने कहा, हां मोहसिन। बिशप ने फिर पूछा शमी के साथ कोई समस्या है तो पंत ने फिर दोहराया शमी बाहर हैं, मोहसिन खेलेंगे। बिशप ने फिर कहा मैं शमी के बारे में पूछ रहा हूं तो पंत ने कहा, मार्करैम बाहर हैं, बडोनी खेलेंगे। इस पर बिशप ने कहा कि छोड़ो, इसे यहीं समाप्त करते हैं।

विराट आइपीएल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने

विराट कोहली

मुंबई, प्रेट्र: भारतीय क्रिकेट और आइपीएल की लोकप्रियता लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। फैनैटिक स्पोर्ट्स और हुरुन की एक रिपोर्ट के अनुसार, विराट कोहली आइपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के साथ अपने 18 साल लंबे जुड़ाव से कोहली ने अब तक लगभग 230 करोड़ रुपये की कमाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शर्मा 227.2 करोड़ रुपये की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी करीब 200 करोड़ रुपये की कमाई के साथ तीसरे नंबर पर हैं। हुरुन इंडिया के संस्थापक अनस रहमान जुनैद के अनुसार, भारत इस समय खेल उद्योग में तेजी से उभरते निवेश और प्रतिभा विकास के दौर से गुजर रहा है।

कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी

रिपोर्ट के अनुसार, आइपीएल फ्रेंचाइजियों की संयुक्त वैल्यूएशन 1.63 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई है। अभिनेता शाह रुख खान की सह-मालिकाना वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी हुई है, जिसकी वैल्यूएशन 19,200 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। इसके बाद मुंबई इंडियंस और सीएसके (18,400 करोड़ रुपये) हैं।

आराम की स्थिति में डाल सकता है आइपीएल का पैसा : कोहली

बेंगलुरु, प्रेट्र: दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने युवा पीढ़ी के खिलाड़ियों से अपील की कि वे आइपीएल से मिलने वाली तुरंत शोहरत के लालच से ऊपर उठें, ताकि वे लंबे समय तक खेल के प्रति समर्पित रह सकें और क्रिकेट की दुनिया में व्यापक सम्मान हासिल कर सकें। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ वनडे प्रारूप खेलने वाले कोहली ने उभरते हुए क्रिकेटरों से कहा कि वे सभी प्रारूप के सच्चे खिलाड़ी बनने के लिए अपने अंदर का जज्बा तलाशें। यह जज्बे की बात है। आजकल बहुत से लोग जज्बे को पैसे से जोड़कर देखते हैं। हां, यह एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब कोई प्रारूप आपको शोहरत और पहचान देता है, जैसे 20 गेंदों में 40-50 रन बनाकर मिलने वाली प्रसिद्धि। आज आइपीए में लोग जिस तरह का पैसा कमा सकते हैं, वह आपको बहुत ही आरामदायक स्थिति में डाल सकता है।

महिला क्रिकेटरों में मंधाना की कमाई सबसे ज्यादा

महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी हैं। डब्ल्यूपीएल में अब तक उनकी कुल कमाई 13.7 करोड़ रुपये रही है। वहीं डब्ल्यूपीएल की शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की कुल कमाई अभी तक 90 करोड़ रुपये ही पहुंची है, जो पुरुष आइपीएल खिलाड़ियों की तुलना में काफी कम है।

उम्मीदें जिंदा रखने उतरेगी केकेआर

जासं, कोलकाता: एक अनार, सौ बीमार। आइपीएल में इस समय कुछ ऐसी ही स्थिति है। तीन टीमें रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेआफ में पहुंच चुकी हैं। बची है सिर्फ एक जगह और दौड़ में हैं पांच टीमें पंजाब किंग्स, राजस्थान रायल्स, चेन्नई सुपरकिंग्स, दिल्ली कैपिटल्स व कोलकाता नाइटराइडर्स। अंकों के आधार पर कोलकाता इसमें सबसे पीछे है। इस सूरत में वह बुधवार को ईडन गार्डेंस स्टेडियम में एक और 'करो या मरो' का मैच खेलने उतरेगी। सामने हैं मुंबई, जो खिताबी दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर गिरकर मौजूदा सत्र समाप्त करना नहीं चाहेगी। उसके लिए यह सम्मान रक्षा की लड़ाई है, इसके साथ ही वह आइपीएल से नाइटराइडर्स की विदाई भी कराना चाहेगी। मुंबई पिछले मैच में पंजाब को छह विकेट हराकर उसके लिए मुश्किलें पैदा कर चुकी है। अब कोलकाता का भी खेल बिगाड़ना चाहेगी। सत्र के पहले मैच में उसने कोलकाता को छह विकेट से हराया था। दोनों टीमों के बीच अब तक 36 मैच हुए हैं, जिनमें मुंबई ने 25 तो कोलकाता ने 11 जीते हैं।

मुश्किल डगर: क्रिकेट पंडित कोलकाता के प्लेआफ में पहुंचने की महज 10 प्रतिशत संभावना बता रहे हैं। कोलकाता के इस वक्त 12 मैचों में 11 अंक हैं। सिर्फ दो मैच बचे हैं। दोनों जीतने पर अधिकतम 15 अंक होंगे, जो काफी नहीं होगा। कोलकाता को दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। विशेषकर पंजाब व राजस्थान के अपने बाकी मैच हारने पर कोलकाता के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। यहीं नहीं, नेट रन रेट भी अहम भूमिका निभाएगा।

रिषभ पंत की वनडे टीम से छुट्टी, टेस्ट में उपकप्तानी भी छिनी

- अफगानिस्तान के विरुद्ध एक टेस्ट व तीन वनडे के लिए भारतीय टीम घोषित
- गिल संभालेंगे दोनों टीमों की कमान, टेस्ट में राहुल तो वनडे में श्रेयस डिप्टी
- मानव सुथार और गुरनूर बराड़ टेस्ट टीम में नए चेहरे, वनडे टीम में प्रिंस यादव को मिला मौका

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: अगले महीने अफगानिस्तान के विरुद्ध होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच और तीन वनडे मैचों के लिए मंगलवार को भारतीय टीम की घोषणा की गई। आइपीएल 2026 में कुछ खास नहीं करने वाले रिषभ पंत की वनडे टीम से छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ ही टेस्ट में पंत से उपकप्तानी भी छीन ली गई है। टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे।

टेस्ट में केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है, जबकि वनडे में श्रेयस अय्यर इस भूमिका में होंगे। पंत इस सीजन 12 आइपीएल मैचों में 27.89 की औसत से 251 रन ही बना पाए हैं और उनके नाम केवल एक अर्धशतक है। उनकी कप्तानी में लखनऊ की टीम का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा और टीम 12 मैचों में आठ हार के साथ प्लेआफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। गुवाहाटी में मंगलवार को अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने छह जून से 20 जून तक अफगानिस्तान से होने वाली सीरीज के लिए टीम चुनी। आगामी इंग्लैंड दौरे को देखते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के तहत टेस्ट और वनडे सीरीज से विश्राम देने का फैसला किया गया। वहीं आलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी वनडे सीरीज से विश्राम दिया गया है।

बैठक के बाद अगरकर ने कहा, इंग्लैंड दौरे पर बुमराह की टीम में वापसी होगी। वह कार्यभार पर काम कर रहे हैं। अगरकर ने कहा कि रवींद्र जडेजा टीम का एक अहम हिस्सा हैं। उन्हें इस टेस्ट मैच के लिए आराम दिया गया है। हम दूसरे खिलाड़ियों को मौके देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उन्हें सिर्फ इसी टेस्ट मैच के लिए टीम में नहीं चुना है। वनडे में केएल राहुल के बाद इशान किशन दूसरे विकेटकीपर होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी वनडे टीम का हिस्सा होंगे। वहीं हार्दिक पांड्या का वनडे सीरीज के लिए चयन उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। टेस्ट टीम में मानव सुथार और गुरनूर बराड़ को पहली बार मौका मिला है। ये दोनों खिलाड़ी आइपीएल में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से इस सीजन 16 विकेट ले चुके दिल्ली के प्रिंस यादव को वनडे टीम में मौका दिया गया है। सुथार और दुबे को टीम में शामिल करने से चयन समिति का यह इरादा झलकता है कि वे रेड बाल क्रिकेट में भारत के स्पिन गेंदबाजी संसाधनों का विस्तार करना चाहते हैं। ताकि इससे भविष्य में टीम को फायदा मिले।

मानव सुथार

हर्ष दुबे

टेस्ट टीम : शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, रिषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरैल।

वनडे टीम : शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़।

कार्यक्रम

मैच	स्थान	तिथि
एकमात्र टेस्ट	मुल्लांपुर	छह से 10 जून
पहला वनडे	धर्मशाला	14 जून
दूसरा वनडे	लखनऊ	17 जून
तीसरा वनडे	चेन्नई	20 जून

रिषभ पंत

कभी गिल ने जिला टीम में दिलाई थी जगह, अब टेस्ट टीम में मिला मौका

गुरनूर बराड़

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ का क्रिकेट सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कभी स्कूल में फुटबाल और टेनिस खेलने वाले गुरनूर आज भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए तेज गेंदबाजों में गिने जा रहे हैं। छह फीट पांच इंच लंबे इस गेंदबाज को भारत के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भविष्य का खिलाड़ी तक बताया है।

गुरनूर ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज डेल स्टेन को देखकर ही उन्होंने गेंदबाजी शुरू की थी। बचपन में वह स्टेन, ब्रेट ली और शोएब अख्तर की गेंदबाजी एक्शन की नकल किया करते थे। हालांकि शुरुआत में क्रिकेट को उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। स्कूल के एक दोस्त ने उनकी लंबाई देखकर क्रिकेट ट्रायल देने की सलाह दी और वहीं से उनका सफर शुरू हुआ। दो साल के भीतर ही उनकी मुलाकात शुभमन गिल से हुई, जो उस समय भारत अंडर-19 टीम का हिस्सा थे। गुरनूर की रफ्तार से प्रभावित होकर गिल ने उन्हें जिला टीम में जगह दिलाने में मदद की। इसके बाद उन्होंने पंजाब अंडर-23 टीम तक का सफर तय किया। 2021 में पंजाब के लिए लिस्ट-ए पदार्पण करने वाले गुरनूर को पंजाब किंग्स ने नेट गेंदबाज के रूप में मौका दिया। उनकी गेंदबाजी से शिखर धवन प्रभावित हुए और उन्हें आइपीएल में मौका मिला।

खेल डायरी

चालिहा मुख्य ड्रा में, अम्साकरुनन-अर्जुन जीते

कुआलालम्पुर, प्रेट्र: भारत की अश्मिता चालिहा ने चीनी ताइपै की पाइ यू पो को तीन गेम के मुकाबले में हराकर मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल मुख्य ड्रा में प्रवेश कर लिया। चालिहा ने यू पो पर 21-23, 21-16, 21-16 से जीत दर्ज की। अब उनका सामना दुनिया की 56वें नंबर की खिलाड़ी इंडोनेशिया की टी रामाधानी वीर्यावान से होगा। आकर्षि कश्यप को कोरिया की पार्क गा युन के हाथों 21-15 20-22 7-21 से पराजय झेलनी पड़ी। पुरुष युगल में हरिहरन अम्साकारुनन और एम आर अर्जुन ने सातवीं वरीयता प्राप्त क्रिस्टो पोपोव और फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव को 21-19, 21-15 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब उनका सामना इंडोनेशिया की जोड़ी और चीन की जोड़ी के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

बिली जीन ने 82 वर्ष की उम्र में ली डिग्री

कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री ग्रहण करतीं बिली जीन (बाएं) ● एपी

लास एंजिलिस, एपी : महान टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग ने जश्न मनाते हुए खुशी में अपना दाहिना हाथ उठाया लेकिन यह टेनिस कोर्ट पर एक और जीत की खुशी नहीं थी। इस बार वह अपनी पढ़ाई शुरू करने के 65 साल बाद कालेज की डिग्री हासिल करने का जश्न मना रही थीं। इस 82 वर्षीय दिग्गज ने सोमवार को एक समारोह में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से इतिहास में कला स्नातक की उपाधि हासिल की। बिली जीन ने बाद में कहा, किसी भी काम को पूरा करने के लिए देर कभी नहीं होती फिर चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आपकी क्षमता जो भी हो, अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करें। मैंने जितना सोचा था यह मेरे लिए उससे कई अधिक मायने रखता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं डिग्री हासिल करने में सफल रही। बिली जीन किंग ने 1961 में कालेज में दाखिला लिया था। यह वही वर्ष था जब उन्होंने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता था। यह खिताब उन्होंने महिला डबल्स में जीता था। विंबलडन में उन्होंने 20 खिताब जीते। उन्होंने इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी।

चोट के कारण विंबलडन से हटे अलकराज

लंदन, एपी: दो बार के विंबलडन चैंपियन कार्लोस अलकराज अगले महीने होने वाले ग्रास-कोर्ट ग्रैंड स्लैम इवेंट विंबलडन से अपनी कलाई की पुरानी चोट के कारण हट गए हैं। अलकराज ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

अलकराज को पिछले महीने बार्सिलोना ओपन में अपनी दाईं कलाई में चोट लग गई थी और वह पहले ही इस सप्ताहांत में शुरु होने जा रहे फ्रेंच ओपन से हट चुके थे। उन्होंने पिछले दो वर्षों में यह क्ले-कोर्ट टूर्नामेंट जीता था। अलकराज ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट किया कि मेरी रिकवरी अच्छी चल रही है और मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। लेकिन, दुर्भाग्य से मैं अभी भी मुकाबले के लिए तैयार नहीं हूं।

कभी क्रिकेट छोड़ने को कहा, चयन पर भर आई मां की आंखें

लोकेश शर्मा ● जागरण

- देर रात घर आने से मां से पड़ती थी पिटाई, मां को सताती थी बेटे की पढ़ाई की चिंता
- पिता के कहने पर बल्लेबाज से तेज गेंदबाज बना प्रिंस यादव, पूरा दिन मैदान पर बिताते थे

नई दिल्ली: जिस मां को कभी अपने बेटे के देर रात तक घर लौटने की चिंता सताती थी, आज वही बेटे के भारतीय टीम में चयन पर सबसे ज्यादा खुश है। कभी क्रिकेट खेलने के लिए घर से सुबह पांच बजे निकलने और रात नौ-दस बजे लौटने पर डांट खाने वाले दिल्ली के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव अब टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के विरुद्ध तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए उनका चयन हुआ है। अब उनके चयन से परिवार में उत्साह और त्योहार जैसा माहौल है।

पिता रामनिवास यादव ने बताया कि प्रिंस का सफर संघर्ष, जिद और जुनून की कहानी है। शुरुआती दिनों में उनका पूरा दिन क्रिकेट मैदान पर बीतता था। घरवालों को चिंता रहती कि बेटा पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में डूब गया है। एक दिन उनकी मां ने परेशान होकर मुझे फोन कर शिकायत की। इसके बाद बहन ने भी उन्हें डांटा और रस्सी से पिटाई कर घर से बाहर न जाने की चेतावनी दी। लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका जुनून इतना मजबूत था कि अगले ही दिन वह फिर मैदान पहुंच गए। जिस बेटे के लिए मां रात भर चिंता करती थीं, वही बेटा देश के लिए, गेंदबाजी कर परिवार और दिल्ली का नाम रोशन करने जा रहा है। पिता ने बताया कि प्रिंस ने करीब 17 साल की उम्र तक टेनिस बाल क्रिकेट खेला।

प्रिंस यादव

शुरुआत में वह बल्लेबाज के रूप में पहचान रखते थे। उनके पिता स्वयं तेज गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने बेटे की प्रतिभा को पहचानते हुए उसे पेशेवर क्रिकेट की ओर मोड़ा। 19 वर्ष की आयु के बाद प्रिंस ने तेज गेंदबाजी को गंभीरता से अपनाया।

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज प्रदीप सांगवान ने नजफगढ़ के एक गांव में खेलते हुए प्रिंस को देखा और बेहतर कोचिंग की सलाह दी। इसके बाद उन्हें कोच अमित वशिष्ठ के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण मिला। गांव के तालाब के पास बनी पिच पर घंटों अभ्यास करने वाले प्रिंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। 2026 सत्र में उनकी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। पिता ने बताया कि भरत अरुण के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलते हुए प्रिंस ने अपने खेल को काफी बदला है।

प्रगनानंद ने पांचवें दौर में वेस्ली से खेला ड्रा

बुखारेस्ट, प्रेट्र: भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रगनानंद ने सुपर शतरंज क्लासिक के पांचवें दौर में अमेरिकी वेस्ली सो के साथ अंक बांटे और इस तरह से इस टूर्नामेंट में चौथी बाजी ड्रा खेली। यह प्रतियोगिता ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट का हिस्सा है जिसके पांचवें दौर में किसी भी बाजी का हार या जीत के रूप में परिणाम नहीं निकला। इस तरह से जर्मनी के विन्सेंट कीमर ने अपनी आधे अंक की बढ़त बरकरार रखी। उनके 3.5 अंक हो गए हैं। कीमर के बाद प्रगनानंद तथा नीदरलैंड्स के अनीश गिरी और जार्डन वैन फोरेस्ट का नंबर आता है। इन तीनों खिलाड़ियों के तीन-तीन अंक हैं । फ्रांस के मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव और वेस्ली सो 2.5-2.5 अंक के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

सीरीज जीतने से तीन विकेट दूर बांग्लादेश

दूसरे टेस्ट में 437 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 316 रन पर गंवाए सात विकेट, बांग्लादेश के स्पिनर ताइजुल इस्लाम ने लिए चार विकेट

सलमान आगा का विकेट लेने पर साथियों संग जश्न मनाते ताइजुल (बाएं) ● एएफपी

सिलहट, एपी: बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम के चार विकेट की मदद से बांग्लादेश मेहमान टीम पाकिस्तान के विरुद्ध न सिर्फ टेस्ट सीरीज जीतने बल्कि क्लीन स्वीप से सिर्फ तीन विकेट दूर रह गया है। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन, 437 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने मेहमान टीम पाकिस्तान के 316 रन तक सात विकेट चटका दिए।

पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर खेल रहे थे, और दिन का खेल खत्म होने पर साजिद खान आठ रन पर थे। सलमान आगा और कप्तान शान मसूद ने 71-71 रन बनाकर पाकिस्तान को टेस्ट मैच पांचवें दिन तक ले जाने में मदद की। आगा और रिजवान ने छठे विकेट के लिए 134 रन जोड़कर पाकिस्तान को जीत की थोड़ी उम्मीद जगाई थी। पाकिस्तान का स्कोर एक समय छह विकेट पर 162 रन हो गया था।

बांग्लादेश पहली पारी में 278 रन बनाने के बाद पाकिस्तान को 232 रनों पर समेट दिया था। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की हार अब इसलिए भी पक्की लग रही है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जीत के लिए 418 रनों से ज्यादा का लक्ष्य कोई भी दूसरी टीम सफलतापूर्वक हासिल नहीं कर पाई है।

22 साल बाद खिताब के करीब आर्सेनल

फुटबाल डायरी

बर्नले के विरुद्ध गोल करते आर्सेनल के हावर्ट्ज (25 नंबर जर्सी) ● एपी

लंदन, एपी: काई हावर्ट्ज के पहले हाफ में किए गए गोल की मदद से आर्सेनल ने कुछ तनाव भरे पलों से गुजरने के बाद आखिरकार बर्नले पर 1-0 से जीत हासिल की। आर्सेनल 22 साल में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबाल टूर्नामेंट का खिताब जीतने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है।

इस जीत से आर्सेनल के 37 मैच में 82 अंक हो गए हैं और अगर वह रविवार को होने वाले अंतिम दौर के मैच में क्रिस्टल पैलेस को हरा देता है तो वह चैंपियन बन जाएगा। लीग में मैनचेस्टर सिटी 36 मैच में 77 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है और उसे खिताब की दौड़ में बने रहने के लिए के लिए अपने अगले मैच में बोर्नमाउथ को हराना होगा। आर्सेनल की टीम इस सत्र में दो प्रमुख खिताब जीतने के करीब है। वह 30 मई को चैंपियंस लीग के फाइनल में पेरिस सेंट-जर्मेन का सामना भी करेगी। ।

फिटनेस की अटकलों के बीच नेमार विश्व कप टीम में: स्टार स्ट्राइकर नेमार को उनकी फिटनेस को लेकर संदेह के बावजूद ब्राजील की विश्व कप टीम में शामिल किया गया है। वह चौथा विश्व कप खेलेगा। **टीम:** गोलकीपर: एलिसन, एडर्सन, वेवर्टन, डिफेंडर: सैंड्रो, डैनिलो, लियो परेरा, ब्रेमर, वेस्ले, मार्क्विनहोस, मैगलहेस, सैंटोस, मिडफील्डर: ब्रूनो गुइमारेस, कासेमिरो, डेनिलो सैंटोस, फैबिन्हो, पाक्वेटा, फारवर्ड: एंड्रिक, गेब्रियल मार्टिनेली, इगोर थियागो, माथियस कुन्हा, रफिन्हा, विनीसियस जूनियर, लुइज हेनरिक, नेमार, रेयान।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

दैनिक जागरण
सप्तरंग
सेहत भरे जीवन का
बुधवार 20 मई, 2026

5 आसान तरीके स्वस्थ दिनचर्या के

घंटों बैठकर काम करने की आदत और व्यस्त जीवनशैली के चलते वजन बढ़ना स्वाभाविक है। इससे बचने के लिए मेटाबोलिज्म को दुरुस्त रखना होगा, जिसके लिए जीवनशैली में मामूली परिवर्तन भी पर्याप्त होता है। आइए जानें...

1. आपको चाहिए अच्छी नींद
प्रतिदिन अच्छी और पर्याप्त नींद लेने से आप तरोताजा महसूस करते हैं और आपकी सक्रियता बढ़ती है।

2. एक कप ग्रीन टी
इससे रेस्टिंग मेटाबोलिज्म बढ़ेगा, भूख नियंत्रित रहेगी। दिन में दो कप ग्रीन टी ऊर्जावान रखेगी।

3. कैफीन लेने में समझदारी
इससे ऊर्जा मिलती है और यह मेटाबोलिज्म को बढ़ाने में भी सहायक है। वर्कआउट के दौरान इससे कम थकान महसूस होती है।

4. मांसपेशियां बनें मजबूत
सप्ताह में दो से तीन बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कैलोरी बर्न होने के साथ मेटाबोलिज्म में सुधार होता है। मांसपेशियां मजबूत होने से फैट का जमाव कम होता है।

5. पानी पीने का रहे खयाल
पर्याप्त पानी पीने से मेटाबोलिक एक्टिविटी में सुधार होता है। इससे भूख नियंत्रित रहने के साथ ऊर्जा दिनभर बनी रहती है।

इन दिनों

देश के अनेक इलाकों में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के चलते सामान्य जन-जीवन प्रभावित हो रहा है। कुछ लोग इन दिनों हरदम थकान या सुस्ती महसूस करने की शिकायत करते हैं। किन कारणों से महसूस होती है यह थकान और इससे बचाव के लिए दिनचर्या में किन बातों का रखना होगा ध्यान, बता रही हैं सीमा झा...

गर्मी में थकान क्या है समाधान

• फोटो: मैग्नीफिक

धूप से बचने के उपाय ढूंढ़ना, एसी कमरों की तरफ भागना, ठंडी चीजों का सेवन करने की इच्छा, इन दिनों बहुत सामान्य आदत बन जाती है। क्या इसके बाद भी आप बेचैन बने रहते हैं? अगर घंटों की नींद के बाद भी थकान व सुस्ती महसूस होती है और आप इसका कारण रात को कुछ भारी खा लेने या नींद न पूरी होने को मान रहे हैं तो इसमें एक अन्य कारण समर फटीग भी जोड़ सकते हैं। इसे चिकित्सकीय भाषा में हीट एक्जाशन भी कहा जाता है। बता दें कि समर फटीग एक संकेत है जिससे पता चलता है कि आपके शरीर को बढ़े हुए तापमान में समायोजित होने में कठिनाई महसूस हो रही है। ऐसे में समर फटीग से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसके लक्षणों को पहचानें। ऐसे उपाय करें ताकि हीटवेव और बढ़े हुए तापमान में आपकी ऊर्जा बनी रहे।

एसी न बन जाए समस्या

अगर एसी का प्रयोग करते हैं तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान आमतौर पर सबसे आरामदायक और आदर्श इनडोर तापमान माना जाता है। यह न तो बहुत अधिक गर्म होता है और न ही ठंडा। बाहर का तापमान अधिक होने के बाद लोग अक्सर एसी का तापमान बहुत कम कर देते हैं। तापमान का अंतर अधिक रहेगा तो इससे डिहाइड्रेशन, उनींदापन, कमजोरी थकान भी महसूस हो सकती है।

दवा या चाय नहीं है समाधान

यदि इस मौसम में अधिक कमजोरी या थकान हो रही है तो बिना डाक्टर की सलाह के कोई सप्लीमेंट जैसे मल्टीविटामिन, पेन किलर या एनर्जी पिल्स लेने से बचना चाहिए। ध्यान रहे इससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है या किडनी पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। इसी तरह, चाय-काफी या कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल का सेवन भी इस समस्या का समाधान नहीं है। इनसे भी थकान व डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है।

रात को भी रहें सावधान

आमतौर पर रात का तापमान कम होने से राहत मिलती है, पर जब गर्मी के दिनों में रात के तापमान में भी कमी नहीं आती, तो इससे हीट एक्जाशन के साथ शरीर के कई अंगों पर दुष्प्रभाव पैदा करता है। किडनी की समस्या, श्वसन तंत्र पर दबाव व ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। नींद न आने या बार-बार खुलने से शारीरिक व मानसिक थकान हावी रहती है। यह प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा असर डालता है। इसलिए इस मौसम में सोने से पूर्व व उठने के बाद पर्याप्त पानी व ओआरएस का प्रयोग करें। अगर छत पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो कमरे का तापमान ठंडा करने के उपाय करें। रात में भारी खाना खाने से बचें।

छोटी-छोटी आदतों का करें विकास

- पसीने के साथ शरीर से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे आवश्यक मिनरल्स निकल जाते हैं। इसके लिए केवल पानी से काम नहीं चलेगा।
- छाछ को काला नमक व भुने जीरे के साथ लें। कोशिकाओं में पानी की मात्रा बनाए रखने में नमक मदद करेगा और दही के रूप में प्रोबायोटिक से आंतों को अधिक तापमान में ठंडक मिल सकेगी।
- पराठा को छोड़कर दलिया, खीरा आदि चुनें जिससे शरीर हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है।
- दोपहर को चाय के बजाय सत्तू या नारियल पानी, नींबू पानी का सेवन करें।
- छोटे बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि वे नहीं बता सकते कि उन्हें किस तरह की दिक्कत हो रही है। वे सुस्त और अधिक नींद से परेशान हो सकते हैं।
- घरों में ब्लैकआउट कर्टन यानी वे पर्दे जो कमरे में अंधेरा करने में मदद करते हैं, उनका प्रयोग करें, इससे कमरे में ठंडक बनी रहती है।
- कमरे में हर समय कृत्रिम रोशनी से भी गर्मी का एहसास बढ़ता है, इसे कम रखें।

इन संकेतों को जानें

- बालों का पहले की तुलना में अधिक गिरना
- सामान्य से अधिक प्यास महसूस होना
- खड़े होने पर चक्कर आना या अस्थिर महसूस होना
- सीढ़ियां चढ़ना अपेक्षाकृत कठिन होना
- आठ घंटे की नींद के बाद भी सुबह उठने में संघर्ष करना
- कसरत करने के बाद अच्छा महसूस न होना
- भूख न लगना, हर वक्त बीमार या कमजोरी महसूस होना
- सिर दर्द बना रहना
- कोई निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होना आदि

हल्के में न लें यह समस्या

डा. हर्षल साल्वे
प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स, दिल्ली

बढ़ते तापमान के कारण शरीर का सामान्य तापमान भी बढ़ने लगता है। हमारा शरीर उस गर्मी को तुरंत नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में कई प्रकार के लक्षण उभरते हैं। अत्यधिक पसीना आना, मुंह सूखना, प्यास लगने के साथ थकान व कमजोरी महसूस होना। इसे हीट एक्जाशन भी कहते हैं। उचित सावधानी नहीं बरती जाए तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है, पर वे इसके शिकार अधिक हो सकते हैं जिन्हें पहले ही कोई दीर्घकालिक समस्या है जैसे उच्च रक्तचाप के मरीज। यदि वे लंबे समय तक अधिक तापमान के प्रभाव में रहते हैं तो स्ट्रोक भी हो सकता है। साथ ही छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों को भी बढ़े हुए तापमान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

फिटनेस रूटीन से न हो समझौता

मीनल पाठक
फिटनेस एक्सपर्ट

गर्मी के दिनों में भारी-भरकम कसरत टालना गलत नहीं, पर प्रयास करें कि कुछ हल्के व्यायाम व योग बंद न हों। यह रक्तसंचार के लिए जरूरी है और इससे तरोताजा बने रहने में मदद मिलेगी। बेहतर होगा आप सुबह शीतल छांव वाली जगहों पर टहलने जाएं। स्ट्रेचिंग करें ताकि मांसपेशियों में महसूस होने वाली जकड़न कम हो। प्राणायाम से शरीर को ठंडा रखने में मदद मिलती है। साथ ही यह समर फटीग से राहत दिला सकता है।

समर फटीग व हीट स्ट्रोक में अंतर

गर्मी के मौसम में कमजोरी और थकान महसूस होने से शरीर के तापमान में बढ़ोत्तरी अधिक नहीं होती। पसीना भी अधिक आता है, पर हीट स्ट्रोक एक आपातकाल है जिससे शरीर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है और पसीना आना भी बंद हो जाता है। दरअसल, हीट स्ट्रोक में शरीर के तापमान को नियंत्रण करने वाली स्वाभाविक प्रणाली फेल हो जाती है। हीट स्ट्रोक होने पर तुरंत अस्तपाल ले जाने की स्थिति होती है जबकि समर फटीग में व्यक्ति को छांव में या शीतल जगह पर ले जाकर उपचार करें तो वह ठीक हो जाता है।

सतर्कता

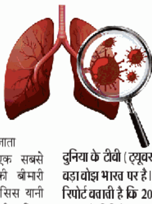

सही न्यूट्रिशन से रुकेगा टीबी का संक्रमण!

दुनिया के टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) संक्रमण का सबसे बड़ा बोझ भारत पर है। लांसेट ग्लोबल हेल्थ की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2023 में कुपोषण से बचाव कर भारत में टीबी के सात लाख मामलों को रोका जा सकता था। इस संक्रमण से बचाव और रिकवरी में क्या है संतुलित पोषण की भूमिका, आइए जानें...

जब शरीर को भोजन के जरिये पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते, तो इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। इससे संक्रमण और बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इसी में एक सबसे गंभीर तरह की बीमारी है- ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। लांसेट की हालिया रिपोर्ट की मानें तो कुपोषण का सही ढंग से निदान कर साल 2023 में दुनियाभर में टीबी के 23 लाख मामलों यानी एक चौथाई टीबी को रोका जा सकता था। भारत में टीबी के 40 प्रतिशत मामले कुपोषण के चलते होते हैं। अगर भोजन में सामान्य तौर पर दाल, चावल और सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी ध्यान रखा जाए, तो टीबी के जोखिम को 49 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

डा. रीतिका समादार
न्यूट्रिशनिस्ट, मैक्स अस्पताल, नई दिल्ली

टीबी में सबसे महत्वपूर्ण थेरेपी है सही पोषण

हमें समझना होगा कि सही पोषण न केवल शरीर को सेहतमंद रखता है बल्कि संभावित बीमारियों से भी बचाता है। टीबी जैसी बीमारियां कमजोर इम्यून सिस्टम के चलते होती हैं। टीबी के निदान में सबसे सपोर्टिव थेरेपी न्यूट्रिशन ही है। इससे रिकवरी में काफी मदद मिलती है।

चूंकि, टीबी ऐसी बीमारी है जिसमें इम्युनिटी कमजोर हो जाती है, मांसपेशियों का तेजी से ह्रास होता है और वजन में कमी आने लगती है। ऐसे में बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए सही पोषण आवश्यक है, ताकि रिकवरी की जा सके। अगर अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो इम्युनिटी अच्छी रहेगी और संक्रमण से लड़ने में शरीर की क्षमता बेहतर बनेगी।

उच्च प्रोटीन और हाइड्रेशन का खयाल : टीबी के चलते होने वाले मांसपेशियों के क्षय को रोकने के लिए उच्च प्रोटीन युक्त आहार सुझाया जाता है। टीबी की दवाओं का साइड इफेक्ट्स होता है, जिससे लिवर और किडनी जैसे अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में सही और संतुलित पोषण के साथ-साथ स्वच्छता और पर्याप्त हाइड्रेशन का ध्यान रखना होता है। इससे शरीर के अन्य अंगों के प्रभावित होने की आशंका कम हो जाती है और इससे साइड इफेक्ट्स को काफी हद तक सीमित रखा जा सकता है।

सही आहार रखेगा संक्रमण से दूर: स्वस्थ व्यक्ति को भी अपने आहार को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी खुराक नहीं मिलने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे टीबी जैसे संक्रमण की आशंका रहती है। कुपोषित लोग टीबी की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। ऐसे लोगों के बचाव और रिकवरी में काफी समय लगता है। इसलिए, स्वस्थ आहार, स्वस्थ आदतें और संतुलित दिनचर्या को जीवन में शामिल करना चाहिए।

बातचीत : ब्रह्मानंद मिश्र

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

संक्रमण रोकने के लिए खानपान

- टीबी के मरीजों के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें भोजन के माध्यम से पर्याप्त प्रोटीन उपलब्ध कराया जाए।
- भोजन में दालें, दूध, दही, अंडा, नान वेज आदि आवश्यक हैं।
- वजन में गिरावट को रोकने के लिए कैलोरी की अधिकता वाला भोजन देना चाहिए।
- कैलोरी की भरपाई के लिए भोजन में पर्याप्त अनाज, खिचड़ी, केले, सूखे मेवे आदि आवश्यक हैं।
- इम्युनिटी के लिए मौसमी फलों व सब्जियों की जरूरत होती है।
- विटामिन सी, आयरन की प्रचुरता वाले फल-सब्जियां जैसे आंवला, संतरा आदि खाने से इम्युनिटी बढ़ती है।
- हाइड्रेशन का खयाल रखना जरूरी है, ताकि साइड इफेक्ट्स कम रहें। इसके लिए पानी, नींबू पानी, नारियल पानी लेते रहना चाहिए।

आज का भविष्यफल: 20 मई, 2026 बुधवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी।
आज का राहुकाल : दोपहर 12 बजे से 01 बजकर 30 मिनट तक।
आज का दिशाशूल : उत्तर
आज का पर्व एवं त्योहार : गणेश चतुर्थी व्रत
आज की भद्रा : प्रातः 11 बजकर 08 मिनट तक।

कल 21 मई, 2026 का पंचांग

कल का दिशाशूल : दक्षिण
विक्रम संवत 2083 शके 1948 उत्तरायण, उत्तरगोल, वसंत ऋतु अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी 08 घंटे 27 मिनट तक, तत्पश्चात षष्ठी पुष्य नक्षत्र 26 घंटे 50 मिनट तक, तत्पश्चात अश्लेषा नक्षत्र गंड योग 10 घंटे 59 मिनट तक, तत्पश्चात वृद्धि योग कर्क में चंद्रमा।

मेष: निजी सुख में व्यवधान आ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी।
वृष: भाई बहन का सहयोग रहेगा। पुरुषार्थ सार्थक होगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी।
मिथुन: पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा।
कर्क: बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।
सिंह: आर्थिक प्रगति होगी। अज्ञात भय से ग्रसित रहेंगे। व्यर्थ की उलझन व तनाव रहेगा।
कन्या: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।
तुला: सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अधिकारी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी।
वृश्चिक: सुखद समाचार मिलेगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।
धनु: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जीवन सुखमय होगा।
मकर: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। संबंधों में निकटता आएगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
कुंभ : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं।
मीन : बुद्धि कौशल से कार्य संपन्न होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सम्मान में वृद्धि होगी।

वर्ग पहेली-3340

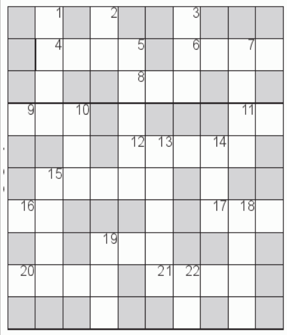

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं:
4. राज्य का शासन केंद्र (4)।
6. फेफड़ों में जख्म हो जाने का दुसाध्य रोग (4)।
8. प्रेम, चाह (3)। 9. तट, तीर, हाशिया (3)। 11. ठिगना (2)।
12. घूमंतु (5)।
15. टन-टन करना (5)।
16. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (2)।
17. छोटा राजा, सरदार (3)।
19. चित्रकार की कूंची, सीक (3)।
20. हंसोड़, मजाकिया (4)।
21. सुंदर, मनोहर (4)।

ऊपर से नीचे:
1. आहें भरना (4)। 2. किसी वस्तु के दो बराबर भागों में से एक (2)। 3. बुरी तरह से घायल (3)।
5. अपमानित करना (2,3)।
7. रोग दूर करना (4)।
10. खाद्य-सामग्री, रसद, अन्न (3)।
13. अनेक ढंग, कई तरह (2,3)।
14. जिसमें दो परतें या तहें हों, दुगुना (3)।
15. ठूंस कर भरा हुआ (4)।
18. वश में करने वाला (4)।
19. मदिरा, सोम (3)। 22. चालीस किलोग्राम एक .... के बराबर होता है (2)।

कल का हल

अ		अ		अ		म	हा	न	ता
व		ज्ञा		भि	क्षु	क			
रो		न	ग	मा		र	ग	पा	ना
ही	न	ता		न			म		
	फी					अ	ला	प	ना
अ	स	ह	न					सं	
		मा			ड		ह	द	स
ग	ह	रा	ई		री	व	त		फा
			मा	न	व		बु		च
प	ह	चा	न		ना		द्धि		ट

सुडोकू-3340

3		5		6		2		9
	9						4	
7			8		3		6	
8			9			1		5
		7			1		9	
1				2				8
	3				9			4
		4						
9			4		5		3	

कल का हल

2	6	4	5	9	7	8	3	1
1	8	3	4	2	6	5	9	7
9	5	7	1	8	3	6	4	2
8	7	9	6	3	2	1	5	4
4	3	1	9	5	8	2	7	6
6	2	5	7	1	4	9	8	3
7	9	8	2	4	1	3	6	5
5	4	2	3	6	9	7	1	8
3	1	6	8	7	5	4	2	9

राष्ट्रीय फलक

मोनालिसा ने लगाया जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी का आरोप

नईदुनिया, इंदौर : प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान रुद्राक्ष की मालाएं बेचकर इंटरनेट मीडिया पर छाने वाली मोनालिसा भोसले ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की है। इसमें उसने आरोप लगाया है कि केरल में फरमान के साथ हुए उसके अंतरधार्मिक विवाह को अपराध साबित करने के लिए उसके जन्म प्रमाण पत्र में फर्जी तरीके से बदलाव किया गया है। याचिका में मोनालिसा के मूल जन्म प्रमाण पत्र को बहाल करने और सरकारी रिकार्ड में की गई कथित गड़बड़ी की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। मामले में जल्द ही सुनवाई हो सकती है। बता दें कि मोनालिसा की शादी का मामला पिछले दिनों उस वक्त विवाद में घिर गया, जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा कि विवाह के समय मोनालिसा की आयु लगभग 16 वर्ष थी। शादी के लिए फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया गया।

योग में भारी पड़ा ज्येष्ठ अधिकमास, 26 मई को गंगा दशहरा

जागरण संवाददाता, वाराणसी

▸ **धर्मकृत्योपयोगी ग्रह गणना आधारित पंचांगानुसार दशमी तिथि 25 मई को प्रातः 8:25 बजे लग रही**

सनातन व्यवस्था में व्रत-पर्व आदि सभी शुद्ध मास में ही निर्धारित होते हैं, लेकिन गंगा दशहरा इस बार ज्येष्ठ अधिकमास में पड़ रहा है। धर्मकृत्योपयोगी (धार्मिक कार्य के लिए उपयोगी) ग्रह गणना पर आधारित पंचांग अनुसार दशमी तिथि सोमवार 25 मई को प्रातः 8:25 बजे लग रही है, जो मंगलवार 26 मई को प्रातः आठ बजे तक रहेगी। उदय काल में दशमी 26 मई को प्राप्त हो रही, अतः मंगलवार 26 मई को गंगा दशहरा मनाया जाना शास्त्र सम्मत है।

शास्त्रों में कहा गया है-'ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता। हरते दश पापानि तस्माद् दशहरा स्मृता।।' अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र आदि शुभ काल में स्वर्ग से गंगा का इस धरा धाम पर आगमन हुआ था। इसीलिए यह तिथि गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त इसी तिथि को दस विशेष शुभ कालखंडों का संयोग भी प्राप्त होता है, जो दस प्रकार के पापों का नाश करता हुआ अनंत शुभ फलों को प्रदान करता है। इसीलिए इसका नाम दशहरा है।

दस विशेष शुभ कालखंडों में ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार दिन, हस्त नक्षत्र, गर करण, आनंद आनंदादि योग, व्यतिपात विष्कुंभादि योग, कन्या राशि पर चंद्र व वृष राशि पर सूर्य की स्थिति शामिल है। इनमें सर्वप्रमुख दशमी तिथि है।

श्रीकाशी विद्वत परिषद के संगठन मंत्री प्रो. विनय पांडेय के अनुसार ज्येष्ठ मास में अधिमास लग रहा तो शुद्ध ज्येष्ठ या अधिक ज्येष्ठ शुक्ला पक्ष की दशमी में से जिस दिन दस शुभ कालखंडों में से अधिक संयोग बन रहे होंगे, उसी दिन गंगा दशहरा पर्व मनाए जाने का शास्त्रों में विधान बताया गया है।

पहाड़ों की ओर सैलानियों का रेला, जाम से बढ़ी चुनौती

जागरण टीम, नई दिल्ली

▸ **मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़**

▸ **जम्मू-कश्मीर में फिलहाल स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य**

देश के मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों का रुख एक बार फिर पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर की ओर तेजी से बढ़ा है। ऐसे में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी आमद के कारण यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है और कई स्थानों पर लंबा जाम लगने लगा है।

जम्मू-कश्मीर में भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां अभी उत्तराखंड और हिमाचल जैसी व्यापक जाम की समस्या सामने नहीं आई है।

उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी, चकराता, रानीखेत और औली जैसे लोकप्रिय स्थलों पर लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। सप्ताहांत पर स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। मसूरी और नैनीताल में निर्बाध यातायात बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है।

मनाली के मशहूर पर्यटन स्थल रोहतांग में मंगलवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। इससे यहां पर रुक-रुक कर जाम लगता रहा। सौजन्य पाठक

नैनीताल में वाहनों का दबाव बढ़ने पर शटल सेवा संचालित की जा रही है। चारधाम यात्रा के चलते ऋषिकेश और अन्य यात्रा मार्गों पर भी वाहनों की संख्या बढ़ गई है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों को जाम का सामना करना पड़ रहा है।

हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, मनाली और धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। मनाली में होटलों की आक्यूपेंसी लगभग 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मनाली से सटे रोहतांग दर्रे में मंगलवार को करीब 10 हजार पर्यटक पहुंचे। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण मनाली, नेहरूकुंड और रोहतांग मार्ग पर रुक-रुक कर जाम लगता रहा।

प्रशासन ने बढ़ती मांग को देखते हुए सप्ताह में एक दिन बंद रहने वाले रोहतांग दर्रे को अब मंगलवार को भी पर्यटकों के लिए खुला रखने का निर्णय लिया है।

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही जारी है, लेकिन अभी वहां उत्तराखंड और हिमाचल जैसी गंभीर यातायात बाधाएं नहीं देखी जा रही हैं। पर्यटन गतिविधियों में तेजी के बावजूद यातायात व्यवस्था अपेक्षाकृत संतुलित बनी हुई है।

समुद्री मार्ग से पहली बार भारत पहुंचे वास्को डी गामा

1498 में आज ही के दिन पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा समुद्री मार्ग के जरिये भारत पहुंचे थे। लिस्बन से आरंभ हुई उनकी यात्रा केरलम के कालीकट (वर्तमान कोझिकोड) तट पर समाप्त हुई। उन्हें भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है।

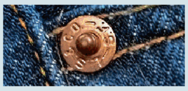

लेवी स्ट्रास व दर्जी जैकब डेविस को मिला ब्लू जींस के लिए पेटेंट

1873 में आज ही अमेरिका के लेवी स्ट्रास व दर्जी जैकब डेविस ने डेनिम जींस का पेटेंट कराया था। तांबे के छोटे बटन वाली इस मजबूत व टिकाऊ जींस को खनिकों और मजदूरों के लिए तैयार किया गया था। आज ब्लू जींस फैशन का प्रतीक बन चुकी है।

पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में पीरू सिंह ने दिखाई असाधारण वीरता

पीरू सिंह शेखावत का जन्म 1918 में आज ही राजस्थान के चूरू जिले में हुआ था। बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखने वाले पीरू सिंह 20 मई 1936 को भारतीय सेना में भर्ती हुए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी सेवाएं दीं और बाद में छठी राजपूताना राइफल्स का हिस्सा बने। 1948 के भारत-पाक युद्ध में जम्मू-कश्मीर में उन्होंने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। भीषण गोलीबारी और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद दुश्मन के कई मशीनगन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ते हुए अपने प्राण मातृभूमि पर न्योछावर कर दिए। असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया।

इबोला अफ्रीका तक सीमित, भारत में कोई मामला नहीं

निगरानी बढ़ी ▸ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को घोषित किया है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल

संक्रमित व्यक्ति के खून, उल्टी, पसीने, लार के संपर्क से फैलता है संक्रमण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इबोला वायरस के मौजूदा प्रकोप को 'वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किया है। इबोला वायरस के संक्रमण के अब तक विश्व में 336 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 87 लोगों की मौत हो चुकी है। यह प्रकोप इबोला वायरस की 'बंडिबुग्यो' किस्म का है।

इसकी पहली पहचान वर्ष 2007 में यूगांडा के बंडिबुग्यो क्षेत्र में हुई थी। इसलिए इसे बंडिबुग्यो नाम दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के अनुसार फिलहाल इस वायरस का संक्रमण

प्रतीकात्मक

मुख्य रूप से कांगो और युगांडा तक सीमित है। भारत में अब तक इसका कोई मामला सामने नहीं आया है।

भारत में इबोला संक्रमण का कोई मामला नहीं आने के बावजूद डब्ल्यूएचओ की तरफ से इसे 'वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित करने के बाद स्वास्थ्य विभाग व अन्य एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। आइएमए की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस समिति के अध्यक्ष डा. नरेंद्र सैनी ने बताया कि इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है, जिसकी मृत्यु दर 25 से 90 प्रतिशत तक रही है। यह संक्रमित व्यक्ति के खून, उल्टी, पसीने, लार और अन्य शरीर द्रवों के सीधे संपर्क से फैलता है। असुरक्षित अंतिम संस्कार प्रक्रियाएं भी संक्रमण फैला सकती हैं।

हालांकि, यह सामान्य परिस्थितियों में हवा से नहीं फैलता। उन्होंने हाथों की स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है।

प्रमुख लक्षण

- तेज बुखार
- अत्यधिक कमजोरी
- सिरदर्द
- मांसपेशियों में दर्द
- गले में खराश
- उल्टी और दस्त
- शरीर के अंदर या बाहर रक्तस्राव
- गंभीर स्थिति में कई अंगों का काम करना बंद होना

बचाव के उपाय

- साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ
- संक्रमित व्यक्ति के शरीर द्रवों के संपर्क से बचें
- अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण नियमों का पालन
- बायोमेडिकल कचरे का सुरक्षित निपटान
- संदिग्ध मरीज को तुरंत अलग रखें

क्या सावधानियां बरतें

- प्रभावित देशों की यात्रा से बचें
- बुखार या संक्रमण के लक्षण होने पर तुरंत जांच
- बिना सुरक्षा उपकरण के घरवाले या बाहरवाले मरीज की देखभाल न करें
- असुरक्षित अंतिम संस्कार से बचें
- संक्रमण को लेकर अफवाहों के बजाय स्वास्थ्य एजेंसियों की सलाह मानें

फिल्म रिव्यू

टाम क्लैंसीज जैक रायन : घोस्ट वार

कलाकार : जान क्रासिंस्की, वेंडेल पियर्स, माइकल केली, सिएना मिलर

निर्देशक : एंड्रयू बर्नस्टीन

अवधि : एक घंटा 45 मिनट

रिलीज प्लेटफार्म : अमेजन प्राइम वीडियो

शानदार एक्शन से भरपूर

अमेरिकी राजनीतिक एक्शन-थ्रिलर फिल्म काल्पनिक पात्रों पर आधारित है और टीवी श्रृंखला जैक रायन की कहानी को आगे बढ़ाती है। अमेजन प्राइम वीडियो पर आज रिलीज हो रही फिल्म में जान क्रासिंस्की एक बार फिर जैक रायन की भूमिका निभाते नजर आएंगे।

वर्ष 2023 में आए चौथे सीजन में जैक अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुका था। घोस्ट वार में जैक रायन न्यूयार्क में आम नागरिक की जिंदगी जी रहा होता है। सीआइए के उपनिदेशक जेम्स ग्रीयर (वेंडेल पियर्स) उससे दुबई में एक मुखबिर से रहस्यमयी पैकेट लाने को कहते हैं। जैक पहले तैयार नहीं होता फिर मान जाता है। मिशन में उसके साथ माइक नवंबर (माइकल केली) भी शामिल हैं। शुरुआत में यह बस एक साधारण मिशन लगता है, लेकिन जल्द ही बड़ी साजिश बन जाता है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआइ16 की एजेंट एमा मार्लो (सिएना मिलर) के साथ मिलकर काम करने को मजबूर जैक और माइक को ग्रीयर के अतीत के बारे में पता चलता है, जिसका संबंध एक मिशन से है। उनके रास्ते में लियाम क्राउन (मैक्स बीस्ली) आता है। क्या जैक और उसके साथी उस रहस्यमयी पैकेट तक पहुंच सकेंगे, कहानी इस संबंध में है।

रोमांचक दृश्यों से भरपूर है फिल्म चित्र सौ. : फिल्म टीम

जान क्रासिंस्की ने इसे जैक रायन सीरीज के लेखक एरन रैबिन और नोआ ओपेनहाइम के साथ मिलकर लिखा है, पर कहानी दमदार नहीं बन पाई है। हालांकि, फिल्म का एक्शन शानदार है। कार के पीछा करने वाले दृश्य रोमांचक हैं, जैसे दुबई में एक्शन के दृश्य हों या ग्रीयर का लंदन की सड़कों पर खलनायक का पीछा करना और अंत में दुबई में गोलीबारी। वहीं कई ट्विस्ट पूर्वानुमानित लगते हैं और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बिना प्रभाव के आसानी से गुजर जाती हैं।

जान क्रासिंस्की जैक की भूमिका को सहजता से निभाते हैं। माइक नवंबर के रूप में माइकल केली चिरपरिचित अंदाज में नजर आते हैं। क्रासिंस्की और केली की जोड़ी कहानी के सबसे मनोरंजक हिस्सों में से एक है। ग्रीयर के रूप में वेंडेल पियर्स गंभीरता लेकर आते हैं। एमा मार्लो के रूप में सिएना मिलर मजबूत कड़ी साबित होती हैं। उनके हिस्से में कई दमदार एक्शन सीन आए हैं। फिल्म में बेट्टी गैब्रियल भी लौटती हैं, जो सीरीज के तीसरे और चौथे सीजन से एलिजाबेथ राइट की भूमिका दोहराती हैं और अब सीआइए की निदेशक के रूप में दिखाई देती हैं। वह अपना प्रभाव छोड़ती हैं। क्राउन बने मैक्स बीस्ली ने संयमित ढंग से पात्र को जिया है। कमजोर पटकथा के कारण फिल्म प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहती है।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

अपनी राय हमें जरूर बताएं: feature@jagran.com

इधर-उधर

शादी का मंच बना रेसलिंग रिंग, दुल्हन बनी चैंपियन

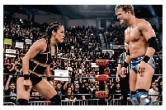

घर के कामों से पा ली आजीवन छुट्टी ● इंटरनेट मीडिया

बीजिंग, एजेंसी : चीन के गुइझोउ प्रांत में पारंपरिक रस्मों की जगह दूल्हा-दुल्हन ने शादी के मंच पर ही पेशेवर रेसलिंग मुकाबला कर डाला। इस अनोखी शादी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। मुकाबले से पूर्व दोनों के बीच शर्त रखी गई कि जो हारेगा, उसे जिंदगीभर सारे काम जैसे झाड़ू-पोछा और बर्तन धोना करने होंगे। करीब 300 मेहमानों के सामने शुरू हुए मुकाबले में दुल्हन ने शानदार फुर्ती दिखाई और दूल्हे को पटककर जीत हासिल कर ली।

डाटा सेंटर की गर्मी आसपास का 2.2 डिग्री बढ़ा सकती है तापमान

अनुसंधान

अमेरिका के सबसे गर्म शहर फीनिक्स में किए गए नए अध्ययन से पता चलता है कि डाटा केंद्रों से निकलने वाली अपशिष्ट गर्मी हवा के बहाव वाली जगहों में तापमान को 2.2 डिग्री तक बढ़ा सकती है।

एरिजाना स्टेट यूनिवर्सिटी के भूगर्भीय विज्ञान और शहरी योजना के प्रोफेसर और निदेशक डेविड सैलर ने कहा कि एकल डाटा केंद्र द्वारा पैदा गर्मी अमेरिका में 40,000 घरों द्वारा उत्सर्जित गर्मी की मात्रा को पार कर सकती है। एयर कूल्ड कंडेंसर एरे जो टरबाइन के उत्सर्जन भाप को संघनित करते हैं आसपास के वायु तापमान से 14-25 डिग्री फारेनहाइट (लगभग 8-14 डिग्री सेल्सियस) अधिक गर्म हवा को छोड़ सकते हैं, जिससे थर्मल प्लूम बनते हैं जो हवा के बहाव वाले पड़ोस में फैलते हैं। सैलर ने कहा कि वे बिजली की खपत और इसलिए गर्मी के उत्सर्जन का इतना केंद्रित लोड हैं कि हम स्थानीय स्तर पर उनके प्रभाव के बारे में चिंतित हो गए, और साथ ही हवा के बहाव वाले पड़ोस में भी। जैसे-जैसे विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय स्थितियों के तहत अधिक माप करते हैं, लगता है कि हम डाटा केंद्रों के चारों ओर अधिक प्रभाव देखेंगे। शोधकर्ताओं ने कहा कि पिछले अध्ययनों ने डाटा केंद्रों के गर्मी प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए उपग्रहों से रिमोट सेंसिंग डाटा का उपयोग किय, यह अध्ययन जर्नल आफ इंजीनियरिंग फार सस्टेनेबल बिल्डिंग्स एंड सिटीज में प्रकाशित हुआ। (प्रेट्र)

कुपोषण दूर करने को खाद्य पदार्थों में मिलाएंगे अतिरिक्त पोषक तत्व

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कुपोषण, एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए विशेषज्ञों ने मुख्य खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त पोषक तत्व (फोर्टिफिकेशन) मिलाने को आवश्यक बताया है। यह बात मंगलवार को टेक्नोसर्व द्वारा संचालित मिलर्स फार न्यूट्रिशन और भारतीय उद्योग परिसंघ के सीआइआइ फूड एंड एग्रीकल्चर सेंटर आफ एक्सीलेंस (सीआइआइ फेस) के सहयोग से इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कही गई।

खाद्य विशेषज्ञों ने कहा कि फोर्टिफिकेशन के जरिए खाद्य पदार्थों को अधिक पौष्टिक बनाकर बड़ी जनसंख्या तक बेहतर पोषण पहुंचाया जा सकता है। सम्मेलन में खाद्य तेल, चावल और गेहूं के आटे जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में विटामिन और मिनरल मिलाकर अधिक पौष्टिक बनाने की दिशा में रोडमैप तैयार करने पर चर्चा हुई। टेक्नोसर्व के सीनियर प्रैक्टिस लीडर मोनोजित इंद्रा ने कहा कि फोर्टिफिकेशन को बड़े स्तर पर सफल बनाने के लिए खाद्य उद्योग, नीति-निर्माताओं और विकास भागीदारों के बीच मजबूत सहयोग जरूरी है।

वहीं, मिलर्स फार न्यूट्रिशन इंडिया के कंट्री प्रोग्राम मैनेजर अभिषेक शुक्ला ने कहा कि फोर्टिफिकेशन भारत की पोषण सुरक्षा को मजबूत करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है।

'बचपन का प्यार' गाने के अनधिकृत इस्तेमाल पर लगाई रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने गाना 'बचपन का प्यार' और उसकी चर्चित हुक लाइन 'जाने मेरी जानेमन बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे' के अनधिकृत इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाते हुए कई यूट्यूब चैनलों और अज्ञात लोगों को बिना अनुमति इसका उपयोग करने से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि गीत के कापीराइट अधिकार आइवी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं। अगली सुनवाई 10 अगस्त को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष होगा। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने 15 मई को यह अंतरिम आदेश कापीराइट उल्लंघन से जुड़े एक मुकदमे में पारित किया।

स्क्रीन शाट

स्क्रीन पर खूबसूरती जरूरी, पर वही सबकुछ नहीं : डायना

काकटेल 2 देखने के लिए उत्सुक हैं डायना। इंस्टाग्राम (@dianapenty)

फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए बने दायरों में सुंदर और फिट होना भी बेहद मायने रखता है। हालांकि हैप्पी भाग जाएगी और काकटेल जैसी फिल्में कर चुकी अभिनेत्री डायना पेंटी कई बार सोचती हैं कि दर्शक इससे आगे भी कलाकारों के बारे में सोचें। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान डायना ने कहा कि मनोरंजन जगत का बड़ा हिस्सा लुक्स यानी आप कैसे दिखते हैं, उसके आसपास सालों से केंद्रित रहा है। जो ठीक भी है, इसे हमने अपनाया भी है। फिल्में विजुअली खूबसूरत होनी चाहिए। मुझे भी अच्छी दिखने वाली फिल्में और लोगों को स्क्रीन पर देखना पसंद रहा है। मुझे वह सराहना अच्छी भी लगती है, जहां लोग कहते हैं कि तुम खूबसूरत हो. लेकिन कई बार लगता है कि लोगों को केवल मैं कैसी दिखती हूं से आगे जाकर मैं जो करती हूं, जिन मुद्दों और मूल्यों के लिए खड़ी होती हूं, जैसा मेरा व्यक्तित्व है उसके बारे में भी जानना चाहिए। मैं जैसी दिखती हूं, वह उम्र के साथ बदलेगा। फिर कई बार लगता है कि मैं ज्यादा उम्मीद कर रही हूं, लोग इतनी गहराई से मेरे बारे में क्यों सोचेंगे। डायना साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म काकटेल फ्रेंचाइज की दूसरी फिल्म काकटेल 2, जो शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन को लेकर बनी है, को लेकर कहा कि यह शानदार लग रही है। मैं देखना चाहती हूं कि इस बार वे क्या नया लेकर आ रहे हैं। मूल फिल्म काकटेल में डायना के साथ दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान प्रमुख भूमिका में थे।

स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते अक्षय

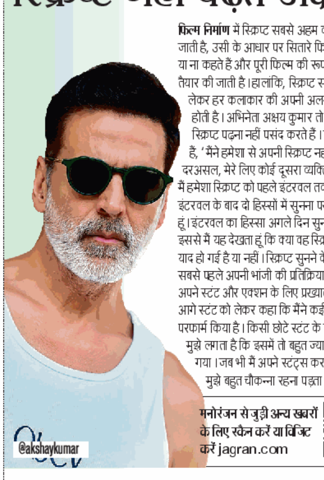

फिल्म निर्माण में स्क्रिप्ट सबसे अहम कड़ी मानी जाती है, उसी के आधार पर सितारे फिल्मों को हां या ना कहते हैं और पूरी फिल्म की रूपरेखा तैयार की जाती है। हालांकि, स्क्रिप्ट समझने को लेकर हर कलाकार की अपनी अलग सोच होती है। अभिनेता अक्षय कुमार तो स्वयं स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं पसंद करते हैं। वह बताते हैं, 'मैंने हमेशा से अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, दरअसल, मेरे लिए कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ता है। मैं हमेशा स्क्रिप्ट को पहले इंटरवल तक फिर इंटरवल के बाद दो हिस्सों में सुनना पसंद करता हूं। इंटरवल का हिस्सा अगले दिन सुनता हूं। इससे मैं यह देखता हूं कि क्या वह स्क्रिप्ट मुझे याद हो गई है या नहीं। स्क्रिप्ट सुनने के बाद मैं सबसे पहले अपनी भांजी की प्रतिक्रिया लेता हूं।' अपने स्टंट और एक्शन के लिए प्रख्यात अक्षय ने आगे स्टंट को लेकर कहा कि मैंने कई स्टंट परफार्म किया है। किसी छोटे स्टंट के बाद भी मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा हो गया। जब भी मैं अपने स्टंट्स करता हूं तो मुझे बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है।

मनोरंजन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

तो रात के तीन बजे नसीरुद्दीन के बेटे उन्हें दिखाते हैं फिल्म

कलाकार अपने लिए तो बेहतर ही फिल्में चुनते हैं, हालांकि बाद में समझ आता है कि वह इतनी अच्छी नहीं थीं। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, लेकिन वह मानते हैं कि वह कई बुरी फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं, जिसका कारण उसकी लिखाई थी। मंगलवार को मुंबई में अपनी फिल्म मैं वापस आऊंगा के ट्रेलर लांच पर नसीरुददीन शाह ने कहा कि मेरा मानना है कि किसी कलाकार की कामयाबी का पूरा सेहरा लेखक और निर्देशक के सर जाता है। अगर लिखाई सही ना हो, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। मैं इसकी जिंदा मिसाल हूं, मैंने कई फिल्मों में बुरा काम भी किया है, जो मेरे बेटे रात तीन बजे यूट्यूब पर मुझे जगाकर दिखाते हैं कि बाबा आपकी फिल्म चल रही है, जबकि मैं उस वक्त

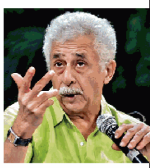

मैं वापस आऊंगा में अहम भूमिका में हैं नसीरुद्दीन शाह ● नसीरुद्दीन शाह

सोना चाहता हूं। यही इस फिल्म में भी हुआ। इम्तियाज (फिल्म के निर्देशक, लेखक इम्तियाज अली) ने बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है, खूबसूरत संवाद हैं। वह मुहब्बत और एहतियात के साथ एक्टरों के साथ काम करते हैं। कम ही ऐसे डायरेक्टर होते हैं, जो एक्टर की परफार्मेंस की वजह से रीटेक करते हैं। इस मौके पर शरवरी वाघ, वेदांग रैना समेत बाकी कलाकार भी मौजूद रहे।

ट्रेन टिकट आरक्षण में धांधली की कहानी है वेब सीरीज वेटिंग है

आम जनमानस की समस्याओं से जुड़ी कहानियों को सिनेमा में अक्सर दिखाया जाता रहा है, जिसमें कई किस्म की धांधली के किस्से भी शामिल हैं। वर्तमान में लोगों के लिए ट्रेन के तत्काल आरक्षित टिकट पाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में फिल्म सत्यप्रेम की कथा के निर्देशक समीर विद्वांस ने इस विषय पर वेब सीरीज वेटिंग है बनाई है। इस शो में अभिनेता दिव्येंदु शर्मा के साथ यशपाल शर्मा, भुवन अरोड़ा, कुमुद मिश्रा, हर्षिता गौर और विजय मौर्या जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में होंगे। इस शो को जल्द ही अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रदर्शित किया जाएगा। शो से जुड़े सूत्रों के अनुसार, शो की शूटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। यह शो तत्काल ट्रेन टिकट के आरक्षण में होने वाली धांधली पर आधारित है। निर्माताओं की तरफ से जल्द ही इस शो की रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा दिव्येंदु आगामी दिनों में पेड्डी तथा मिर्जापुर : द मूवी फिल्मों में नजर आएंगे।

वेब सीरीज वेटिंग है में मुख्य भूमिका में होंगे दिव्येंदु शर्मा। (@divyenndu)

भव्य गाने के साथ हुई उत्कर्ष शर्मा की फिल्म 'अर्जुन नागा' की शुरुआत

साल 2023 में प्रदर्शित ब्लाकबस्टर फिल्म गदर 2 के बाद फिल्मकार अनिल शर्मा ने पारिवारिक ड्रामा फिल्म वनवास बनाई। हालांकि, वो फिल्म टिकट खिड़की पर नहीं चल पाई। उसके बाद अनिल फिर अपने बेटे और अभिनेता उत्कर्ष शर्मा के साथ फिल्म एक्शन ड्रामा जानर फिल्म अर्जुन नागा बना रहे हैं। अब इस फिल्म की शूटिंग शुरु हो चुकी है। रविवार को फिल्म का मुहूर्त शाट शूट किया गया। उसके बाद सोमवार से शूटिंग पूरी लय में चलने लगी। शूटिंग की शुरुआत एक भव्य गाने को शूट करने से हुई, जिसकी कोरियोग्राफी गणेश आचार्य कर रहे हैं। फिल्म में उत्कर्ष के सामने अभिनेता अर्जुन रामपाल खलनायक भूमिका में होंगे। वह भी कुछ दिनों बाद फिल्म की टीम से जुड़ेंगे। इस गाने के बाद फिल्म के ड्रामा और एक्शन सीन शूट किए जाएंगे। यह भी खबरें हैं कि इस फिल्म में उत्कर्ष के साथ निधि अग्रवाल मुख्य नायिका की भूमिका में होंगी। हालांकि, उनके नाम को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि उत्कर्ष ने बतौर नायक अब तक तीनों फिल्में पिता अनिल शर्मा के निर्देशन में की है।

फिर पिता अनिल शर्मा के निर्देशन में काम कर रहे उत्कर्ष। फाइल

जब बात का बतंगड़ बना तो सलमान ने दी सफाई

सलमान खान ने अकेलेपन वाली पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा कि वह तन्हा नहीं हैं, परिवार, दोस्त और फैंस की दुआएं हमेशा उनके साथ हैं।

बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ अभिनेता सलमान खान के साथ जब उन्होंने गत रविवार अपनी फिटनेस दिखाते हुए बिना शर्ट के एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए अकेलेपन और तन्हाई के बीच का फर्क समझा दिया। उसके बाद इंटरनेट मीडिया पर बवाल मच गया कि सलमान अकेलापन महसूस कर रहे हैं और तन्हा हैं। इसके बाद सलमान को सोमवार देर रात इंस्टाग्राम पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने लिखा कि अरे यार मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा था। मैं कैसे अकेला हो सकता हूं, जब मेरे पास इतना बड़ा और कमाल का परिवार और दोस्त हैं। कैसे अकेला हो सकता हूं, जब आप सभी की शुभकामनाएं और दुआ मेरे साथ है। अगर ऐसा हो, तो फिर तो मैं सबसे बड़ा नाशुक्रा होऊंगा। कभी-कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूं। इसलिए थोड़ा समय खुद के लिए निकाला बस। इस बार कोई फोटो नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बना दिया, मम्मी पूछ रही हैं क्या हुआ बेटा? चिल मारो यार।

ट्रोलिंग पर भड़के पुलकित, बोले- सौरभ पर फैसला मेरा था

हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज सैफ अली खान अभिनीत फिल्म कर्तव्य में खलनायक बने सौरभ द्विवेदी को अभिनय के लिए ट्रोल किया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फिल्म के निर्देशक पुलकित ने कहा कि मैं मुंबई एक फिल्म बनाने आया था, अब तक छह बना चुका हूं। इस बात से खुश हूं कि मेरी बनाई फिल्में रिलीज होती हैं। फिल्म को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वह कम ही पढ़ता हूं। जहां तक इंटरनेट पर ट्रोलिंग की बात है, तो सौरभ का चुनाव मैंने ही किया था, जिस पर कायम हूं। मैंने अपनी समझ से जो सही लगा वह किया है। जहां तक इंटरनेट के निर्दयी होने की बात है, तो हर कोई अपनी बात रख सकता है। कुछ नापसंद है तो लिखो, लेकिन इंटरनेट का उपयोग वह बताने के लिए भी होना चाहिए कि फिल्म आनर किलिंग और जुवेनाइल क्राइम पर भी बात करती है।

बिना हिले चार-चार घंटे खड़े रहते थे नितीश भारद्वाज

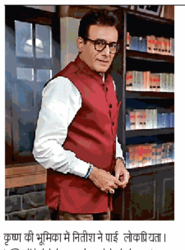

कृष्ण की भूमिका में नितीश ने पाई लोकप्रियता। (@nitishbharadwaj.krishna)

बी आर चोपड़ा द्वारा निर्मित धारावाहिक महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने के बाद अभिनेता नितीश भारद्वाज को इतनी लोकप्रियता मिली कि आज भी लोग उन्हें उस भूमिका में याद करते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें काफी मेहनत भी करनी पड़ी थी। जिस सीन में अर्जुन को श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं, धारावाहिक में दिखाए उस सीन का उल्लेख करते हुए नितीश बताते हैं, 'बी आर चोपड़ा जी मुझे हर सीन के पीछे की तकनीक भी समझाते थे। गीता उपदेश वाले सीन की शूटिंग के दौरान मैंने उनसे पूछा कि हम विश्वरूप दर्शन योग (जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप देखते हैं) वाला सीन कैसे करने वाले हैं? उस सीन में मैं सिर्फ एक जगह खड़ा था, बाकी चेहरे दूसरे लोगों को खड़ा करके शूट किए गए थे। इसको स्टाप ब्लाक फोटोग्राफी की तकनीक से किया गया था। उसमें कैमरा और मुख्य पात्र दोनों नहीं हिलते हैं। अगर दो शाट के बीच मेरा हाथ जरा भी हिल जाता, एडिटिंग के बाद सीन में हिलता हुआ दिखता। इसलिए उस सीन की शूटिंग के लिए विशेष लकड़ियां बनवाई गई थी। मैं चार-चार घंटे बिना हाथ हिलाए खड़ा रहा हूं, इस दौरान मैं अपनी नजर किसी एक चीज पर गड़ा देता था और वही देखता रहता था।'